[Mr. Speaker]

The question is:

"That at the end of the motion, the following be added, namely:—

'subject to the modification that paragraph 3 of the said report be omitted'."

*The motion was negatived.*

**Mr. Speaker:** Now I put the motion that the report as submitted by the Business Advisory Committee be approved by this House.

The question is:

"That this House agrees with the Fiftieth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 2nd November, 1960."

*The motion was adopted.*

---

**13.54 hrs.**

## MOTION OF NO-CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS —*contd.*

**Mr. Speaker:** Mr. Sheo Narain to continue his speech.

---

**श्री शिव नारायण** (बांसी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आप का बड़ा अनुगृहीत हूं कि आपने एक ऐसा विषय इस हाउस में उपस्थित किया कि सारा आपोज़ीशन साफ हो गया, वे सब उठकर चले गये हैं। उनमें दम नहीं ह कि वे अपनी आलोचनाओं का उत्तर सुनें। लेकिन वे लाबीज से सुनेंगे।

**13.55 hrs.**

[THE DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

नौ महीनों में तीन तीन बार नो-कान्फ़िडेंस मोशन पेश करके आपोजीशन पार्टीज इस का मखौल उड़ा रही है। इस नो-कान्फ़िडेंस मोशन की कोई कीमत नहीं है। वह वेस्ट-पेपर बास्केट में फैंकने लायक है।

हमारे देश में जो विद्यार्थी आन्दोलन आज चल रहा है, उस के बारे में मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि विद्यार्थी हमारे देश के भावी नागरिक हैं और हमें उन को इल-ट्रीट नहीं करना चाहिए। पुलिस को यूनिवर्सिटी कम्पाउंड में नहीं जाना चाहिये, हमारे यहां जो यह पुरानी परिपाटी चली आ रही है, उस को कायम रखा जाना चाहिए। मैं श्री चागला की इस बात का समर्थन करता हूं कि गवर्नमेंट को विद्यार्थियों की डिमांड्ज पर विचार करना चाहिए।

मैं आपोज़ीशन को बताना चाहता हूं, जो कि पीठ दिखा कर भाग गए हैं, कि हम कांग्रेस वालों में उन से ज्यादा साहस है। हम अपने देश की मुसीबतों और सुख-दुख को सुन सकते हैं और गवर्नमेंट को कह सकते हैं। हमारे बीच में ऐसे लोग हैं, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी की है। हमारे बीच में वे वयोवृद्ध नेता हैं, जिन्होंने यह नारा लगाया था, "ग़रीबों को मिले रोटी, तो मेरी जान सस्ती है"। यह पालियामेंट उस की गवाह है। यहां पर भगतसिंह, राजगुरु और सुखदेव ने बम फैंका था। यह उन के त्याग और बलिदान का प्रतिफल है कि आज कांग्रेस इस देश में पनप रही है, फल-फूल रही है।

हमारे विरोधी दल आज चीप पापुलरिटी गैन करना चाहते हैं और नन्हें विद्यार्थियों को उकसा रहे हैं। मैं डा० लोहिया, श्री एच० एन० मुकर्जी और श्रीमती रेणु चक्रवर्ती से कहना चाहता हूं कि वे इस देश के भावी नागरिकों के साथ खिलवाड़ न करें। जहां तक डा० लोहिया का सम्बन्ध है, उन को शिकायत है कि हम पिछड़ गए, हमारी बस छूट गई, कामत साहब पिछड़ गए, उन के साथी आज मिनिस्टर हैं। वास्तव में खलबली और झुंझलाहट तो इस बात की है।

मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वह विद्यार्थियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक

विचार करें। सरकार को उन की आर्थिक सहायता करनी चाहिए। मैं एक हरिजन मेम्बर हूं। मैं क्वेंटली कहना चाहता हूं कि हमारे बच्चों पर जुमले कसे जाते हैं कि हरिजनों को सब फ़ीस माफ है। मैं प्लानिंग मिनिस्टर से यह अपील करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के एक एक बच्चे की फ़ीस यूनिवर्सिटी तक माफ़ कर दी जाए। अगर वह ऐसा करेंगे तो वह एक अच्छी एग्जाम्पल सैट करेंगे और उनका काम अमर हो जायेगा। वह ऐसा प्लान बनायें कि देश का हर एक बच्चा एजूकेशन हासिल कर सके।

मेरे मित्र, श्री बनर्जी, जब भी बोलते हैं, तब वह श्री रामरतन गुप्ता और श्री सी० बी० गुप्ता का ज़िक्र करते हैं। हर बात में उनको वही दिखाई देते हैं। कानपुर में क्या स्थिति है, यह मैं जानता हूं। मैं डीटेल्ज में नहीं जाना चाहता हूं। आज सी० बी० गुप्ता यू० पी० का चीफ़ मिनिस्टर नहीं है। वह कांग्रेस का एक तपा-तपाया सिपाही है, कांग्रेस का नेता है, बैचेलर है, बाल-ब्रह्मचारी है। उस ने 43 लाख रुपया जमा किया है। आज हिन्दुस्तान का कौन सा लीडर है, जो बिना मिनिस्टर रहते हुए इतनी कलेक्शन कर सकता है? कल श्री बनर्जी ने यू० पी० का बार-बार ज़िक्र किया। हमारे उत्तर प्रदेश पर सब की नज़र है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आज आन्ध्र में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हुआ, मैसूर और महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। ये सब "विनाशकाले विपरीत बुद्धि" की बातें हैं।

मैं एक टीचर होने के नाते यह एडवाइज करना चाहता हूं कि आज हम सबको एकता के सूत्र में बंधने की कोशिश करनी चाहिए। आज कांग्रेस में ऐसे मेम्बर हैं, जो गवर्नमेंट की क्रिटीसिज्म कर रहे हैं। यू० पी० गवर्नमेंट पांच एकड़ तक के ग़रीब किसानों से जो सालाना लगान लेती है, वह एक करोड़ भी नहीं होता है। मैं गवर्नमेंट को कहना चाहता हूं कि उस को माफ़ कर दिया जाये।

कल यहां पर अमींचन्द प्यारेलाल का ज़िक्र किया गया। मैं आपोज़ीशन को कहना चाहता हूं कि इस कांग्रेस गवर्नमेंट का ही साहस है कि उस ने पब्लिक एकाउंट्स कमेटी और एस्टीमेट्स कमेटी को एपायंट किया है। हम मिनिस्टरों को भी एग्ज़ामिन करते हैं। फूड मिनिस्टर पब्लिक एकाउंट्स कमेटी में हमारे सामने आए, लेकिन हम ने उन के साथ कोई रियायत नहीं की। जहां तक हम से हो सका, हम ने उनको एग्ज़ामिन किया, उन से सवाल पूछे, चैक किया और इस बात का पता लगाने की कोशिश की कि गवर्नमेंट की मशीनरी किस तरह से ठीक चल सकती है।

मैं ने 15 अगस्त को फिनांस मिनिस्टर को कहा था कि वह पंद्रह बीस हजार में एक ट्यूबवैल बनवाते हैं, लेकिन वह एक नाली बनाने के लिए दो हज़ार रुपये खर्च नहीं करते हैं। अगर पक्की नालियां बन जायें, तो हमारे खेतों में पानी पहुंच जाये। वह हमारे खेतों तक पानी पहुंचाने का इन्तज़ाम करें।

कल श्रीमती कमला चौधरी ने बहुत ठीक कहा कि विरोधी दलों को सौतिया डाह है और वे सौतिया डाह में मरे जा रहे हैं। लेकिन यह बहुत छोटी बात है और मैं उस में ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं।

मान्यवर, हम पूर्वी जिले के उस इलाके को रिप्रेज़ेन्ट करते हैं जहां आज भुखमरी है, जहां आज सूखा है। मैं फूड मिनिस्टर का, फाइनेंस मिनिस्टर का और प्लानिंग मिनिस्टर का दोनों का अनुगृहीत हूं क्योंकि दो बार हम मिले 30 तारीख को और 13 तारीख को हमारा डेपुटेशन मिला, हम और विश्वनाथ राय मिले, ठीक से बात की और अपने आदमी को भेजा। 4 तारीख को फूड मिनिस्टर वहां जा रहे हैं उत्तर प्रदेश को देखने। फाइनेंस मिनिस्टर देख कर आये हैं। उन्होंने अश्योरेंस दिया है कि जितना मांगेंगे देंगे, उसको यूटिलाइज करो। हम सैन्ट्रल गवर्नमेंट के अनुगृहीत हैं।

[श्री शिव नारायण]

हम एहसान फरामोश नहीं हैं कि जिस पत्तल में खायें उसी में छेद करें। वह एस० एम० बनर्जी साहब को मुबारक हो, हमें नहीं।

मान्यवर, रेणु चक्रवर्ती ने कल बड़ा ललकारा, हम कम्यनिस्ट नेता हैं। मैं कहता हूं हम देशद्रोही नहीं हैं। हमने इस देश के ऊपर चीनियों को आक्रमण करने के लिए नहीं निमन्त्रित किया। अगर किसी ने निमंत्रित किया तो यह आपोजीशन के टाप कम्यूनिस्ट्स ने किया। यह हैं देशद्रोही। हम नहीं हैं। हम शासन चला रहे हैं। हम में कमियां हैं। मैं रेणु जी से पूछता हूं कि जब बंगाल में बंगाल बन्ध चलाया तो उसमें क्या किया? आपने कोई गल्ले की दुकान नहीं लुटवायी। रेल की पटरियों को उखड़वा दिया जिस से फूड मिनिस्टर सुब्रह्मण्यम साहब का गेहूं पहुंचने न पाये ताकि पालियामेंट में बैठकर उन को गालियां दे सकें। यह नक्शा है कम्यूनिस्ट पार्टी का। हजारों आदमियों को मरवा देते हैं। यह पब्लिक फैसला करेगी। अभी फरवरी में हम और आप चुनाव के मैदान में उतरेंगे। वहां जनता फैसला करेगी। जनता आप को समझ गई है कि आप कहां पर हैं। गाय की पूंछ पकड़कर यह जनसंघ पार्टी और स्वतंत्र पार्टी वाले पार उतरना चाहते हैं। गोवध कानून हमने पास किया उत्तर प्रदेश असेम्बली में बैठकर। जब गोवध विधेयक चल रहा था हमारे असेम्बली में तो लखनऊ में एक पंजाबी ने गाय को डंडा मारा। मैं ने झपटकर कन्धा कपड़ा और कहा कि वहां पर तो सत्याग्रह करते हो गोवध बन्द करने के लिए और यहां गाय को डंडा मारते हो। यह लोग सब से बड़ा अन्याय गाय के साथ कर रहे हैं जो गोवध का नारा लगा रहे हैं। हमारी सरकार ने गोवध बन्द किया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बन्द किया। मैं उस हाउस का मेम्बर था। पंडित गोविंद वल्लभ पंत हमारे चीफ मिनिस्टर थे। मुझे वह भी दिन देखने को मिला है। हमने इस के ऊपर गौर किया और कानून पास किया। हम इनसे कम हिन्दू नहीं हैं। इन से कम देशहित हमारे अन्दर नहीं है। हम उन की औलाद हैं जिन्होंने रावण के भाई विभीषण को शरण दी थी। हम उसी राम राज्य की लाइन पर चल रहे हैं जिसकी कल्पना गान्धी जी ने की थी। नौ महीने के अन्दर नई-नई प्राइम मिनिस्टर आयीं। उन प्राइम मिनिस्टर को लोहिया साहब और राजनारायण जी जो चाहे कह लें। मैं एक प्याली चाय पी आऊं तो आप कहेंगे कल कि हमने चाय पिला दी। यह नक्शे हैं। यह इनका कान्डक्ट है। भारतीय संस्कृति का दम भरते हैं।

आज कहते हैं कि स्त्रियों पर लाठी चार्ज हो रहा है। यह पांच वर्ष तक क्या कर रहे थे? सन् 62 में जब नेहरू जी की गवर्नमेंट बनी थी, उस दिन नेहरूजी से कहना चाहिए था कि गोवध बिल्कुल बन्द कर दिया जाय। इनके नेता लोग मर गए थे उस वक्त? क्यों नहीं जवाहर लाल नेहरू से कहा? यह मैं हूं जो पार्टी में खड़े होकर नेहरूजी से मैं ने कहा था कि पंडित जी, अपनी जिन्दगी में बैंक नेशनलाइज करते जाओ। आज भी कहता हूं। प्रजेन्ट प्राइम मिनस्टिर से कहता हूं। वह भी उन्हीं की बेटी है। उन्हीं का खून है। वह भी नेहरू हैं। नेहरू को रिप्लेस किया, ठीक किया। उन से बढ़कर किसका स्लेट क्लीन है इस देश के अन्दर? उनसे बड़ा कौन त्यागी और बलिदानी इस देश के अन्दर है? गायत्री देवी यहां बैठी थीं, जब वह नेफा गई थीं तब चीन ने हमला किया तब मैं ने ही ललकारा था इस हाउस में, भाग गए हैं। जनता तुम्हारा फैसला करेगी। देखेगी तुमको। मान्यवर, इस देश की जिम्मेदारी हम ने ओढ़ी है। मैं प्लानिंग मिनिस्टर से पुरजोर अपील करता हूं कि आप इनको नंगई से घबड़ाइए नहीं। जनता आपके साथ है। **आइ ऐम कमिंग फ्राम माइ कांस्टीट्युएंसी**

31 तारीख को मैं कांस्टीट्यएंसी में घूम रहा था, मैं वेरिफिकेशन कर रहा था, एक-एक से पूछ रहा था कि फलां कैंडीडट को, यहां खड़ा कर दूं, क्या ओपीनियन तुम्हारी है ? उन्होंने कहा मास्टर साहब, हम इन को नहीं पसन्द करते हैं। जनता ने कहा हम आपके साथ हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप विश्वास रखें आज जनता आपके साथ है। लेकिन आप को भी जनता के साथ बैठना चाहिए। अभी एक मित्र ने कहा, वह चले गए, मैं उनसे बात कर रहा था, उन्होंने नहीं सुना, मैं ने कहा, नहीं सुनते हैं तो जाइए। मैं कहना चाहता हूं कि आप सचेत रहिए। यह जो आपके पीछ फौज बैठी है यह कोई चौराहे के सिपाही नहीं है। यह कांग्रेस के तपे तपाये सिपाही हैं। आपके साथ बैटिल में मार्च किया है। बाबू रघुनाथ सिंह उस काशी की तपोभूमि से आ रहे हैं जो शंकर के त्रिशूल पर टंगी हुई है। वह हमारे नेता बैठे हुए हैं। कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। हमारे उत्तर प्रदेश का कांग्रेस प्रसीडेंट भी हमारा नेता है। आज सारा हिन्दुस्तान देखता है कि उत्तर प्रदेश में यह हो जायगा, वह हो जायगा। पर उत्तर प्रदेश एक सूत्र में रहेगा और 85 के 85 यहां आयेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हम ज्यादा उदार हैं। हमने बाहर के लोगों को चीफ मिनिस्टर बनाया, कमिश्नर बनाया, कलेक्टर बनाया। जिसको एग्ज़ाम्पिल सीखना हो मुझसे सीखे आकर। नमूना हम देते हैं। रेणु जी बड़ा ब्लफ मारती हैं, बड़ा दम मारती हैं इस हाउस में बैठकर। इससे काम न चलेगा ? कहता बहुता मिले, गहता मिले न कोय। उस को ग्रहण करना चाहिए सही सलाह दो क्योंकि तुम उधर बैठते हो, तुम्हारा एग्जाम्पल हम से अच्छा होना चाहिए। **बिकाज यू आर गोइंग टु रिप्लेस दिस गवर्नमेन्ट टमारो**। और जिस गवर्नमेंट का आपोजीशन वीक हो....... (**व्यवधान**) उसूल तो यही है आपोजीशन का But they are totally unfit. They are divided. They are joining hands today.

जनसंघ सोशलिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट राइटिस्ट। हम से कहते हैं कि कांग्रेस वाले बड़ा झगड़ा करते हैं। बिल्कुल ठीक। और तुम हमारी नकल करते हो ? हमारे पास तो राजसत्ता है, हम लोगों में पटकापटकी होती है, मैं कहता हूं कि मैं मिनिस्टर हो जाऊं, रघुनाथ सिंह कहते हैं मैं हो जाऊं। हम लोग तो इस में हैं। तुम पर क्या है जो तुम लड़े जा रहे हो ? मैं पूछना चाहता हूं हीरेन्द्र मुखर्जी साहब से, उन्होंने कल कहा हुक्वर्म्स है यह, तो मैं ने प्वाइंट आफ आर्डर रेज किया कि जो इतना बड़ा काबिल हो, अपने को प्रोफसर कहता हो, वह अपने साथियों का हुकवर्म्स कहे तो वह क्या है ? जनता कहती है कांग्रेस वाले बेईमान हैं, चोर हैं सब कुछ हैं लेकिन औरों से अच्छे हैं। तो उन को नाबदान का कीड़ा बताते हैं। वह नाबदान के कीड़ों से भी बदतर ह। यही पब्लिक कहती है और कौन पब्लिक कहती है ? एम० ए० पास से लेकर घुरहू निरहू तक, ऊपर से नीचे तक। दिस इज दि क्लूजन आफ दि पब्लिक। यह जनता आज भारत की कहती है हमारे सीने के ऊपर चीन ने पंजा जमा रखा है एक तरफ से और एक तरफ से पाकिस्तान ने जमा रखा है और यह बैठे हुए देश के अन्दर मखौल कर रहे हैं। हमारे आगे की जनरेशन के साथ इन्होंने मखौल किया। हमारे बच्चों को बिगाड़ने की नीति इनकी है। यह याद रखो, वही बच्चे इन को ठीक करेंगे। यह हमारे भावी नागरिक इस देश के रक्षक हैं। मान्यवर, 22 वर्ष के बच्चों ने सीमा पर जाकर मुल्क की रक्षा का चार्ज ले लिया। अमेरिका के बड़े बड़े जेट्स को हमारे छोटे-छोटे नेट्स ने मार गिराया और देश के सम्मान को ऊंचा किया। मैं उन का आदर करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं उन विद्यार्थियों का या उन गुरुजनों को, पुलिस की लापरवाही से जिनको गोली लगी, या डंडे से जो बच्चे मर गए हैं मैं उन के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यह अपोजीशन वालों को कहना चाहिए था।

[श्री शिव नारायण]

लेकिन उन्होंने एक लब्ज नहीं कहा कि वह उन के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं । मैं कांग्रेस पार्टी का मेम्बर हूं, मैं कहता हूं । कांग्रेस वाले जिम्मेदार हैं, उनकी ड्यूटी है कि देखें कि देश में डिसिप्लिन कायम रहे । हमारे कांस्टेबिल लोग दिल्ली वाले स्ट्राइक पर हैं, स्ट्राइक करने वाले हैं । मैं ने परसों उन से बात की । . मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि 75 रुपया तनख्वाह बहुत कम है । या तो उनके खाने , कपड़े, रहने की व्यवस्था कर दीजिए, मकान दीजिए और एक पैसा न दीजिए ।......(**व्यवधान**)....... हां, थोड़ा बहुत दो न ? 75 के बजाय 150 कर दो, क्या हर्ज है ?

आप उनकी तनख्वाह 75 से 150 रु० कर दीजिये, यह करना बहुत जरूरी है, उन की यह जायज मांग है । हमारे प्लानिंग मिनिस्टर सोशलिस्ट हैं, समाजवादी नेता रहे हैं, उनकी यह ड्यूटी है कि आमदनी में इतने बड़े फर्क को समाप्त कर के जांय, तनख्वाहों में 1 और 10 की रेशो कर दें, इस से मुल्क में उनकी जय-जयकार हो जायगी, हमारा देश उनकी पूजा करेगा, जैसे आज नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री का नाम लिया जाता है । आज मैं अपने पुराने नेता शास्त्री जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, मैं उनका चेला रहा हूं, उनका वर्कर रहा हूं, परमात्मा उनकी आत्मा को शान्त रखे और वे देश को अपना आशीर्वाद दें, देश फले फूले, ऊंचा उठे । मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे बिगड़ न जांय, गवर्नमेन्ट उन को पूरी मदद दे, उन की फीसें माफ़ करें ।

मास्टर लोग आज काला बिल्ला बांधे फिरते हैं, मैं उन से प्रार्थना करूंगा वे उसको उतार दे, सरकार उनकी दिक्कतों को जरूर सुनेगी, और उनको हल करने का प्रयत्न करेगी । हिन्दुस्तान में एजूकेशन को नेशनलाइज कर देना चाहिये । इस में सरकार को विशेष खर्चा नहीं करना पड़ेगा, जितनी ग्रान्ट वह देती है, उस में काम चल सकता है, आज ये इंस्टीचूशन्ज बिजनेस सेंटर्स बन गये हैं, मैं खुद इस का भुक्तभोगी हूं और जानता हूं कि वहां पर आज क्या हालत है । एक एन्ट्रेन्स पास सैक्रेटरी एम०ए० पास को डांटता है, यह नामुमकिन है, ऐसा नहीं होना चाहिये । अगर सरकार इस को नेशनलाइज कर के अपने हाथ में ले ले, तो इस से देश में डिसिप्लिन बना रहेगा और असन्तोष समाप्त हो जायगा ।

इन शब्दों के साथ मैं सरकार से कहता हूं कि इस डिवाइड एण्ड रूल की पालिसी पर आप अमल करने की कोशिश न करें, आप इस देश में समाजवादी व्यवस्था ला दीजिये, एक और दस का रेशो कर दीजिये, देश जय जयकार बोल उठेगा । कांग्रेस गवर्नमेन्ट फिर आयेगी, मैं डंके की चोट कहता हूं कि फिर आयेगी । यह भगोड़ों के बस का काम नहीं है, ये गवर्नमेन्ट नहीं चला सकते हैं । मैं इस नो-कान्फीडेन्स मोशन का कन्डेमनेशन करता हूं, जो भाग गये हैं अपने रेजोल्यूशन को छोड़ कर, जिन्होंने इस को शुरू किया था, श्री त्रिवेदी जी यहां से चले गये हैं, यह बिलकुल कन्डेमनेबल है, यहां अपोजीशन नहीं है, मैं चाहता हूं कि अभी इस का क्लोजर हो जाये, खत्म हो जाये, देखते हुए रह जायेंगे । जब कोई उधर से बोलनेवाला नहीं है, और हम नहीं बोलेंगे तो अपने आप साफ़ हो जायेगा और मिनिस्टर साहब जवाब दे कर छुट्टी पा जायेंगे ।

आपकी इजाजत से मैं अपनी गवर्नमेन्ट को सूचित करना चाहता हूं कि गरीबों की आप परवाह करें, गावों में किसानों को पानी पहुंचायें, बीज पहुंचायें । मैं अपने

अफसरों से भी कहता हूं कि यह देश तुम्हारा है, किसी चीनी या अंग्रेज का नहीं है, रूसी का नहीं है, अमरीकन का नहीं है, मैं अपील करना चाहता हूं, भगवान के लिये, गौड-सेक के लिये, गांधी जी ने कहा था— Seeker of truth should be humbler than the dust. मैं स्वयं विदेशी माल का, पी० एल० 480 का विरोध करता हूं और देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि दो जून भूखे रह कर इस प्रावलम को सौल्व करें। हम चाहते हैं कि सरकार सहयोग करे, अधिकारी वर्ग सहयोग करें, हर बड़ा छोटा सरकार चलाने में, देश की रक्षा चीन और पाकिस्तान से करने में सहयोग करें।

इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का कन्डेमनेशन करता हूं।

**श्री राम सहाय पाण्डेय** (गुना) : उपाध्यक्ष जी, मुझे अविश्वास के प्रस्ताव पर बोलने का आपने आदेश दिया और मैं असंगत देखता हूं कि इस सदन में प्रस्ताव उपस्थित करने वाला दल यहां उपस्थित नहीं है।

**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : साबित हो गया कि कान्फीडेंस है सरकार में।

**श्री राम सहाय पाण्डेय** : यद्यपि वैधानिक दृष्टि से देखें तो यह प्रक्रिया, अविश्वास की प्रक्रिया, विरोधी दल को प्राप्त है। लेकिन उसके साथ यदि विवेक की दृष्टि से देखें तो यह सत्य है कि उस अविश्वास में जन-मानस का समर्थन होना चाहिये, परिस्थितियों को सिंहावलोकन होना चाहिये और इस प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं होना चाहिये,। हम जानते हैं वे मायूस हैं, फस्ट्रेटेड हैं, लेकिन सदन में इस प्रकार का, हर सदन के आरम्भ में अविश्वास प्रस्ताव को उपस्थित करना, अनर्गल बातें कहना, सत्य से दूर जाकर



असत्य बातें कहना, असत्य बातों का प्रचार करना और जब बहस हो रही हो, उस समय सदन का परित्याग करना, यह बड़ा अनुचित है और उस प्रक्रिया का अपमान है जिस प्रक्रिया के माध्यम से वे उस प्रताव को उपस्थित करते हैं।

श्रीमन् मैं अविश्वास प्रस्ताव पर अपने विचार प्रकट करने से पहले यह निवेदन करूंगा कि यहां पर देश भर से चुने हुए प्रतिनिधि उपस्थित होते हैं। दर्शक दीर्घा में बैठे हुए देश के अनेक भागों से आये हुए लोग उपस्थित होते हैं, वे उत्कट उत्साह से देखते हैं कि इस सदन में बैठ कर हमारे प्रतिनिधि किस प्रकार से देश का निर्णाय करते हैं। क्या अवस्था उस जन-मनामनस की होती होगी, जब वे देखते होंगे कि न सदन में अध्यक्ष की प्रतिष्ठा होती है, न सम्मान होता है, न आदर होता है और न उसकी आज्ञा का पालन होता है। मेरे घर में ठहरे हुए मेरे साथी कार्यकर्ता परसों यहां आये और उन्होंने कहा कि हमारी सामान्य मण्डी कमेटियां और छोटी छोटी नगर-पालिकाओं में भी इस प्रकार की अनुशासनहीनता का प्रदर्शन नहीं होता है, जैसा यहां होता है। यह सर्वोच्च सदन है, यहां कोई किसी की बात नहीं मानता है, मुझे पण्डित जी के वे वाक्य याद आते हैं, जब अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ, तब उन्होंने कहा था— Sir, You are the custodian of democracy. आप इस प्रजातन्त्र के सर्वोत्तम मुखिया हैं और इस श्रेष्ठ स्थान पर बठकर सदन की मर्यादा और देश के जनमानस की भावना को संरक्षण देते हैं। हम रोज देखते हैं कि अध्यक्ष जिस किसी सदस्य को, विरोधी दलों के सदस्यों को जो निर्देश देते हैं, जो आदेश उनकी तरफ से दिया जाता है, उसकी सम्पूर्ण रूप से अवहेलना होती है।

**श्री वाल्मीकि** : यहां तो दल ही नहीं है।

**श्री राम सहाय पाण्डेय** : उन की अप्रतिष्ठा होती है। कभी कभी ऐसा अनुभव होता है, क्या यह सत्य है, क्या इस पर विश्वास किया जा सकता है कि इस देश में प्रजातन्त्र चलेगा क्योंकि जब चुने हुए प्रतिनिधि भी अनुशासन नहीं मानेंगे तो इस प्रकार अन्दर और बाहर ऐसी अवस्था पैदा हो सकती है। जब आस्था डगमगा जाएगी। सब से पहले आस्था सदन की यह है कि हम अनुशासन के साथ, संगत के साथ, न्याय के साथ आदर करें, उस सर्वोच्च अधिकारी का जो इस सदन की प्रक्रिया को कार्यसंचालन का उत्तरदायित्व लेकर बैठता है।

श्रीमन्, बड़ी आलोचना होती है। आज दो तीन बड़ी समस्यायें हमारे सामने हैं। एक सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने खाद्यान्न का है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में सरकार ने कल्पना की थी कि अपने तमाम साधनों को बटोर कर, इस देश में किसानों के श्रम और साधनों को बटोर कर 100 मिलियन टन अनाज उत्पन्न करेंगे। यह हमारा एक भौतिक दृष्टिकोण है, यह हमारे साधनों को बटोरने की प्रक्रिया थी, लेकिन जब मैं भौतिक दृष्टिकोण और सामग्री की बात करता हूं तो मैं इस बात को विस्मरण नहीं कर सकता हूं कि जहां तक हमारे भौतिक साधनों का सम्बन्ध है, वहां तक हम बटोर सकते हैं, योजना बना सकते हैं, किसान को साधनों की उपलब्धि दे सकते हैं, लेकिन यदि कभी प्रकृति नाराज हो जाये, ईश्वर साथ न दे, वर्षा न हो, सूखा पड़ जाय, या कभी कभी कहीं ऐसा भी हो गया कि बाढ़ आ गई, उस स्थिति में हमारी तमाम योजनाओं पर संकट आना स्वाभाविक है। हम चाहते थे कि बाहर से अनाज न मंगायें ? क्या हमें अच्छा लगता है कि हम बाहर से अनाज मंगायें, इस से हमारे आत्म सम्मान को बड़ी ठेस पहुंचती है और आत्म-सम्मान किसी राष्ट्र के जीवन में सर्वोपरि होता है। लेकिन जब प्रश्न यह होता है कि हम ने इस प्रजातन्त्र की जो सब से पहला आश्वासन दिया है वह यह कि हम तुम्हारा पेट भरेंगे तब हम अन्तर्राष्ट्रीय सहअस्तित्व की छत्र छाया में अन्य राष्ट्रों की तरफ हाथ बढ़ाते हैं कि तुम्हारे पास जो है तुम दो, हमारे पास जो है हम दें। हम ने पिछले वर्ष बाहर से 10 मिलियन टन अनाज मंगाया लेकिन 10 मिलियन टन मंगाने के बाद भी स्थिति इतनी खराब हो गई। हम ने 10 मिलियन टन अनाज मंगाया इस वर्ष के लिये यह आशा थी कि भारत में अनाज अच्छा होगा और वर्षा होने से थोड़ी सम्भावनायें बढ़ी थीं। लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले, मध्य प्रदेश के छतीसगढ़ और अन्य जिले, राजस्थान और थोड़ा भाग गुजरात का भी है, जहां पर कि सूखा पड़ गया।

आज की स्थिति में कोई ऐसी बात नहीं है जो हम जनता से छिपाना चाहते हैं या सदन से छिपाना चाहते हैं। एक एक दिन का उत्पादन और अपने बफर स्टाक को हम ने बतलाया है। हम ने चेतावनी दी है कि हमारे पास अनाज नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति भी आप देख लें। सन् 1964-65 में अमरीका के पास 38 मिलियन टन अनाज सरप्लस था और अभी हाल में जो फैक्ट्स ऐंड फिगर्स वहां प्रकाशित हुए हैं उन से पता चलता है कि उन के पास अब सिर्फ 5 मिलियन टन रह गया है। संसार के 38 देश हैं जहां अनाज की कमी है। चीन तो अनाज बाहर से सोना बेच कर ले रहा है, रूस में कमी है वह आस्ट्रेलिया और कैनेडा से ले रहा है।

सब से पहला प्रश्न जीवन का आता है और उस के संरक्षण के लिये जहां से भी अनाज प्राप्त हुआ हम ने लिया। इस वक्त भी हम वार्ता करेंगे और सहयोग सब का लेंगे। स्वावलम्बन हम चाहते हैं, उत्पादन हम बढ़ाना चाहते है, लेकिन जब प्रकृति के प्रकोप का

हम पर असर पड़ता है तब हमारी चिन्ता बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी एक आश्वासन है कि जब तक हमारी सरकार परिस्थितियों का अध्ययन कर के उस के निर्वाह का साहस और क्षमता रखती है तो कोई कारण नहीं है कि हम इस स्थिति का मुकाबला न करें। कई बार आश्वासन दिया गया है कि जो कुछ भी हमारे पास है, सामर्थ्य और सामग्री के माध्यम से हम उन क्षेत्रों में जहां अनाज की कमी है उसे पहुंचायेंगे। यह हमारा आश्वासन है। यह हमारा आश्वासन उन लोगों से भी है जहां अनाज अधिक है। उन के माध्यम से हम आश्वासन उन क्षेत्रों को भी देंगे जहां अन्न की कमी है। हम चाहते हैं कि इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि जहां अनाज अधिक है वह अपने अधिक अनाज को ही न दें बल्कि साथ साथ थोड़ा त्याग भी करें। यह नहीं है कि बार बार इस प्रकार का सूखा पड़ेगा। कल का दिन अच्छा है इस कल्पना के साथ हम आगे बढ़ें और उन प्रदेशों से जहां सरप्लस है उन प्रदेशों को जहां सरप्लस नहीं है सहायता करें।

अनाज की समस्या के लिये हम सावधान हैं। हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि इस स्थिति का मुकाबला करें। और जहां तक सम्भव होगा, सम्भव ही नहीं होगा, हम भगीरथ प्रयत्न करेंगे कि कोई भी व्यक्ति इस धरती के ऊपर भूखों न मर जाये। वह दिन बड़े दुर्भाग्य का होगा अगर कोई आदमी भूखा मर जाये। लेकिन जितना साहस, क्षमता और शक्ति हमारे पास है, सरकार के पास है उतनी शक्ति से और जनता के सहयोग से हम चाहेंगे कि इस स्थिति का निवारण हो।

आज कल एक अशान्ति का वातावरण उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। विद्यार्थियों को भड़काया जा रहा है. इंडोनीशिया का उदाहरण दे कर इस देश में क्रान्ति की ललकार की जा रही है। इंडोनीशिया में क्या हुआ, मैं उस के डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि विद्यार्थी जगत में इंडोनीशिया में जो हुआ उस की प्रेरणा दे कर क्रान्ति का आह्वान किया जाये।

विद्यार्थी समाज के सामने आज दो प्रश्न हैं और हम चाहते हैं कि उन का समाधान वे स्वयं करें। उन के अभिभावक भी करें। एक है अध्ययन का और दूसरा है आन्दोलन का। यह निर्णय उन को करना होगा कि आया वह अध्ययन करना चाहते हैं या आन्दोलन करना चाहते हैं। जहां तक अध्ययन का प्रश्न है, उन को अधिक से अधिक जितनी सुविधायें दी जा सकती हैं वह दी जायें। अच्छे अध्यापक, अच्छे प्रोफेसर, अच्छा वातावरण, अच्छी सामग्री उन को प्राप्त हो, इस का हम समर्थन करते हैं। लेकिन अध्ययन से उदासीन हो कर एस्केपिज्म की टेन्डेन्सी ले कर अगर वह सड़क पर आ जाते हैं और आन्दोलन करते हैं तो मैं उन से निवेदन करना चाहता हूं कि यह ठीक नहीं है। राजनीति में उन के भाग लेने के मैं विरुद्ध नहीं हूं, राजनीति आजके जीवन की अभिन्न प्रक्रिया बन गई है। राजनीति में वह भाग लें, लेकिन स्वस्थ वातावरण का परित्याग न करें। भविष्य की कल्पना की कुंठा से वह अपने आप को इतना वापस न खींच लें कि उन का भविष्य अन्धकारमय हो जाय। हम चाहते हैं कि आन्दोलन की स्थिति इस देश में बन्द हो, बन्द और घेरा डालने की स्थिति। इस का समर्थक वह दल है जिस के नेता ने जर्मनी में ट्रेनिंग पाई है। जर्मन फासिस्ट ओरिएन्टड माइन्ड है। मैं समझता हूं कि इस देश में यह नहीं चल सकता है। एक दिन बन्द, एक दिन घेरा डालो, यह एक ऐसी स्थिति है जिस के पीछे हिंसा की भावना है। उस में सब से बड़ा ब्रीच आफ प्रिविलेज यह होता है कि हमारे फंडामेन्टल राइट्स अर्थात् मौलिक अधिकारों पर जो कि हमें प्राप्त हैं और मौलिक सिद्धान्तों पर कुठाराघात होता है। जैसे बम्बई बन्द किया गया। एक व्यक्ति सड़क पार कर

[श्री राम सहाय पाण्डेय]

अपने निर्दिष्ट स्थान पर जाना चाहता है, लेकिन वह कहते हैं कि हम नहीं जाने देंगे ।

यह हमारे मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात नहीं तो क्या है । जब बन्द किया जाता है किसी औद्योगिक नगर में, मैं बम्बई का उदाहरण लेता हूं, तो एक दिन के बन्द में 60 या 62 करोड़ रुपये के उत्पादन की हानि होती है । एक तरफ तो उत्पादन अधिक चाहते हैं अनाज और वस्त्र का और दूसरी तरफ बन्द कर के गतिरोध पैदा करना चाहते हैं । कलकत्ता या इस प्रकार के दूसरे शहरों में, जैसे कानपुर है, जब बन्द किया जाता है, जब बन्द का नारा दिया जाता है तो उस से अन्ततोगत्वा उत्पादन की क्षत्ति होती है और किसी भी देश की, जिस की आर्थिक स्थिति डगमगा रही हो, जिस की एकानामी आज तक कंसोलिडेट न हो पाई हो, आर्थिक स्थिति में दृढ़ता पैदा नहीं हो सकती, जिसे उत्पादन की आवश्यकता है । हम जिस गति से जाना चाहते हैं तो उस में कोई कुंठा पैदा करे, गतिरोध पैदा करे तो इसे कहां तक बर्दाश्त किया जा सकता है । मैं समझता हूं कि यह नहीं होना चाहिये । उस में किसी प्रकार की भी हानि पहुंचाना देशद्रोह के बराबर है । किसानों के पास जा कर भाव की बात कही जाती है कि तुम को भाव अधिक मिलना चाहिये और वही विरोधी दल शहरों में आ कर कहता है मजदूरों से कि तुम को अनाज सस्ता मिलना चाहिये ; एक दल के कुछ लोग कहते हैं कि स्टील प्लान्ट कहां रक्खा जाये और उसी दल के कुछ लोग कहते हैं कि स्टील प्लान्ट यहां न रक्खा जाये । उन लोगों ने बंटवारा कर लिया है, वही लोग यहां हैं और वही लोग वहां हैं ।

चूंकि विरोधी दल के लोग वहां नहीं हैं इसलिये आप के माध्यम से उन से कहना चाहूंगा . . . .

**एक माननीय सदस्य** : डा० अणे हैं ।

**श्री राम सहाय पाण्डेय** : डा० अणे हमारे बड़े आदरणीय सदस्य हैं । मैं चाहूंगा कि कुछ बातों का स्पष्ट उत्तर आये कि इन जिला बन्दों, प्रदेश बन्दों और भारत बन्द से, यह जो बन्द के नारे हैं उन के प्रदर्शन से क्या हानि होती है । क्या यह सत्य नहीं है कि उत्पादन के क्षेत्र में बहुत बड़ा कुठाराघात है । इस से अपने देश की आर्थिक स्थिति को क्षत्ति पहुंचती है और अन्ततोगत्वा जनता को नुकसान पहुंचता है । मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इन बन्दों और घेरा डालो नारों के पीछे क्या यह सत्य नहीं है कि इन प्रवृत्तियों के पीछे हत्या और सम्पत्ति नष्ट करने के प्रति आग भड़कती है । क्या इस प्रकार की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन नहीं मिलता । क्या इंडोनीशिया का उदाहरण दे कर विद्यार्थी जगत में और समाज में कानून को अपने हाथों में लेने के प्रति उकसाया नहीं जाता । क्या विरोधी दलों में एक दल ऐसा भी नहीं है जो चीन को निमंत्रण देता है कि वह भारत पर आक्रमण करे, उन से जो धन और शस्त्र प्राप्त करता है और जो कुछ यहां हो रहा है उस की पूरी खबर उन को देता है । जो हम में अविश्वास की भावना व्यक्त करने चले हैं, हमारे विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव जिन्हों ने पेश किया है वे करते क्या हैं और कहते क्या हैं ? कहते हैं पुलों को तोड़ दिया जाए, अशान्ति पैदा कर दी जाए और जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाए तो फिर चीन को सिगनल दिया जाए यहां से कि इस समय अवसर है, आप आक्रमण कर दें । मैं आप के माध्यम से विरोधीदल वालों से पूछना चाहूंगा कि क्या उन में एक ऐसा दल नहीं है जो कि साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहित करता है, जो भारतीय संस्कृति और धर्म की गुण गाथा तो गाता है लेकिन क्या यह सत्य नहीं है कि उसी दल के एक सदस्य ने मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष पर जूते से प्रहार किया था और

कुर्सी पर बैठे हुए उपाध्यक्ष की उधर से आगे बढ़ कर गर्दन दबाने की स्थिति पैदा की थी ? मैं चाहता हूं कि कल आप उन से मुझे इस प्रश्न का उत्तर दिलावाइये। भारतीय संस्कृति तथा भारतीय धर्म और सभ्यता विशेष की बात करने वाले इस चीज को भूल गये हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। इस दल से मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि जिस सदस्य ने उपाध्यक्ष पर जूते से प्रहार किया था उस सदस्य के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही भी की गई है ? मेरी जानकारी यह है कि कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यदि ऐसे दल ने कभी सरकार बना ली तो हर बात का फैसला फिर जूते से ही हुआ करेगा और जो संस्कृति के निर्माण की बात है उस के बीच में जूता ही रखा जाएगा, और अगर कोई मानेगा तो तब तो ठीक है नहीं तो एक हाथ में जूता होगा और दूसरे में संस्कृति और इन दोनों में समन्वय यह दल स्थापित करेगा। मैं विरोधी दल वालों से पूछना चाहता हूं कि क्या उन में एक ऐसा दल नहीं है ?

मैं यह पूछना भी चाहूंगा कि क्या एक ऐसा भी दल नहीं है जो अपने को राइटिस्ट कहता है, जो अपने को राइटिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी कहता है और दूसरा अपने आप को लैफिटस्ट पार्टी कहता है ? दायें बायें ये दोनों नाम इन्होंने दे रखे हैं, ये दो संज्ञायें दे रखी हु। लेकिन मेरी दृष्टि में साम्यवादी दुनिया में एक ही है, चाहे वह राइट हो और चाहे लैफ्ट हो। ये कभी राइट नहीं हो सकते हैं, ये दोनों लैफ्ट हैं। इन दोनों का काम ध्वंस करना है, क्या यह सही नहीं है ? इन दोनों का काम प्रजातन्त्र को नष्ट करना है, क्या यह सही नहीं है ? हमारे दल पर भी कभी कभी भ्रष्टाचार के आरोप लगाये जाते हैं, कभी कभी कहा जाता है कि इन को व्यापारियों से पैसा आता है, उद्योगपतियों से पैसा आता है। हम तो उस का चिट्ठा रखते हैं जिन से पैसा लेते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो पचास पचास हजार आदमियों के प्रदर्शन आयोजित किये जाते हैं, ये जो बन्द आयोजित किये जाते हैं, और अभी यह जो एक बड़ा प्रदर्शन विद्यार्थियों का आयोजित होगा, इन प्रदर्शनों के लिये पैसा कहा से आता है ? एक बात मैं स्वतन्त्र पार्टी वालों से पूछना चाहता हूं आप के माध्यम से। असैम्बलीज में जो उन के सदस्य ये हैं वे राज्य सभा में सदस्य कैसे चुन कर भेजते हैं ? क्या उन को भेजते वख्त ये सौदेबाजी नहीं करते हैं ? जितने विरोधी दल यहां हैं उन के कुछ सदस्य बाहर असैम्बलीज में भी होते हैं। जब ये सदस्य राज्य सभा के लिए सदस्य चुन कर भेजे जाते हैं तो कैसा सौदा वे करते हैं, कैसे वोट ये देते हैं ? मैं लांछन नहीं लगाना चाहता हूं। मैं यह भी नहीं कहना चाहता हूं कि वे पैसा लेते। लेकिन आप पूछिये इन से कि ये काली कोठरी में बैठ कर गुड़ कैसे फोड़ते हैं ?

हम इस ओर से आंखें बन्द नहीं कर सकते हैं कि देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, देश में अनाज की कमी है, उत्पादन की कमी है। इस सब के जहां और भी कई कारण हैं वहां सब से बड़ा कारण नैसर्गिक है, प्राकृतिक है और इस संदर्भ में अगर हम सब मिल कर सहयोग करें, सद्भावना के साथ, राष्ट्रीयता की भावना को आगे रख कर, राष्ट्रीयता के संरक्षण के लिये, हम मिल जुल कर काम करें तो हम इस परिस्थिति से पार हो सकते हैं, हम आगे जा सकते हैं ? यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है, अनाज अगर कम है तो एक राष्ट्रीय प्रश्न है और राष्ट्रीय स्तर पर ही इस का समाधान खोजा जाना चाहिये। अगर सूखा पड़ा हुआ हो और हम रेलों द्वारा अनाज उन क्षेत्रों में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो तो आप देखें कि क्या किया जाता है ? किया यह जाता है कि रेलों की पटरियां उखाड़ी जाती हैं। यह जो मरघट पर रोटी पका खाने कीस्थिति है यह ठीक नहीं है। आज की स्थिति में स्वस्थ भाव से समालोचना करने की आवश्यकता हो तो समालोचना कीजिये कुछ राय दीजिये, हमारी त्रुटियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कीजिये, आप साधुवाद के पात्र होंगे।

[श्री राम सहाय पाण्डेय]

लेकिन आज के इस वातावरण में विक्षुब्धता, घृणा, हिंसा, शत्रुता की भावना फैलाना और इस की कोई परवाह न करना कि प्रजातन्त्र को नुकसान इस से पहुंच रहा है, ठीक नहीं है। अगर प्रजातन्त्र रहेगा तो हम भी रहेंगे, विरोधी दल भी रहेंगे और अगर प्रजातन्त्र शाश्वत रहेगा तो एक दिन वह भी आ सकता है जब कि कांग्रेस के लोग उस तरफ होंगे और विरोधी दल के लोग यहां पर बैठे होंगे, तो मुझे ऐसा होता दिखाई नहीं देता है। लेकिन इस की सम्भावना हो सकती है कि उन की सरकार कभी बन जाए। लेकिन जो स्थितियां पैदा की जा रही हैं, मार्ग में जो कांटे बोये जा रहे हैं प्रजातन्त्र के, और जिस तरह से अशान्ति, विद्रोह और हिंसा की भावना पैदा की जा रही है, जो वातावरण बनाया जा रहा है मुझे भय है कि इस को बड़ी भारी कीमत हमें और उन को भी देनी पड़ेगी जब वे सरकार बनायेंगे। आप देखें कि जिस दिन इस अविश्वास के प्रस्ताव को यहां पेश करने की अनुमति मांगी गई थी उस दिन पचास से ज्यादा सदस्य इस के पक्ष में खड़े हो गये थे लेकिन अन्तिम दिन जब इस के पक्ष और विपक्ष में मत लिये जायेंगे तो बीस पच्चीस ही इस के पक्ष में अपने मत देंगे। मैं समझता हूं कि हम सब लोग मिल कर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि विरोधी दल के सदस्यों को वह सुबुद्धि दे, उन के अन्दर राष्ट्रीयता की भावना पैदा करे, उन के अन्दर जनता के प्रति ममत्व की भावना पैदा करे, उन के अन्दर दायित्व के निर्वाह की शक्ति और क्षमता पैदा करे। और दूसरे वे सब राष्ट्रीयता के स्वरूप उन में पैदा हो जायें तो मैं नहीं समझता हूं कि इस से कोई हानि होगी। लेकिन हिंसा अशान्ति, विक्षुब्धता, क्षुद्रता और शत्रुता को अगर माध्यम बनाया गया तो प्रजातन्त्र को खतरा है। राष्ट्रीयता के नाम पर प्रजातन्त्र के नाम पर जो जनता के नाम पर हम सब को चाहिए कि हम राष्ट्र के सामने उत्पन्न परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए एक हो कर काम करें। सरकारें बनती और बिगड़ती हैं, इस से देश को कोई बड़ी भारी हानि नहीं होती है। लेकिन प्रजातन्त्र के बिगड़ने का जब प्रश्न होगा तो बड़ा भारी प्रश्न होगा। जिस दल की भी सरकार बने, वह दल स्थानीय होना चाहिये, राष्ट्रीय होना चाहिये, गम्भीर होना चाहिये, अच्छे आचरण वाला होना चाहिये, जिम्मेदार होना चाहिये। मैं नहीं समझता हूं कि कि ये गुण विरोधी दल के हैं।

मुझे एक बात का बड़ा अफसोस है। मुझे अफसोस है कि दादा कृपलानी कैसे उधर बैठे हुए हैं। दादा कृपलानी सदैव हमारे साथ रहे हैं। हमें उन का आशीर्वाद चाहिये। देश को उन का आशीर्वाद चाहिये। उन की वाणी में शक्ति है। उनका प्रभाव है। जो वह हम को कहते हैं हम उस को मानते हैं। मैं उन से प्रार्थना करूंगा कि वे अपना प्रभाव कुछ विरोधी दल वालों पर भी डालने की कोशिश करें, अपने प्रभाव का उधर भी प्रयोग करें। ये आप की बात नहीं मानते हैं। आप की राय से विरोधी दल हो सकता है कि ठीक रास्ते पर आ जाये। इन को सही रास्ते पर लाना, इन को ठीक रास्ते पर लाना मैं समझता हूं एक बड़ा राष्ट्रीय कर्तव्य है। दादा कृपलानी इन विरोधी दलों को जिम्मेदार बनायें, इन को राष्ट्रीय बनायें, इन को कहें कि वे चीन की तरफ न देखें, ये यहां पैदा हुए हैं, और भारत मां इन की मां है, इनसे कहें कि लूटपाट विद्यार्थियों को ये न सिखायें, इन से कहें कि शान्ति शाश्वत, प्रजातन्त्र शाश्वत। धन्यवाद।

**Shri J. B. Kripalani** (Amroha): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am sorry that the moral support that I would get from the Opposition is absent. I hope the Congressmen will lend me their mornal support as they need my moral support.

I did not stand among the fifty who wanted this motion to be debated. There was reason for that because it seems to me that the Opposition parties had previously some confidence in this Government. You cannot bring a vote of no-confidence unless you had previously some confidence. I lost confidence in this Government many years back, and why? Because I saw from the beginning that they were repudiating the policies of Gandhiji whom we call the Father of the Nation. Nothing has changed; the British Government was a hindrance in our way; that hindrance was removed, and we thought that everything had changed, but we changed our policy. So, I lost confidence with this Government long ago.

I am glad to say that many Congressmen too have lost their confidence now.

**An Hon. Member:** No.

**Shri J. B. Kripalani:** They may say no here; they may vote against the no-confidence motion. I will join them in voting against the no-confidence motion, but they cannot say no to that, when they are very much oppressed by what is going on in the country. They realise that the country is going down and down. On the last occasion, if you remember, I said that I have sympathy with this Government, and I pity this Government Why? Because it is falling by its own weight; it is the weight of mistakes of commission and omission, and there was no need for bringing a no-confidence motion. But today, I am very sorry for the Congress Government, and for the Congress people. I am an old man; I can only express my sorrow. Why? Because even Chiang Kai-shek has learnt by experience. Our Government does not learn even by sad experience. It goes on committing the very same mistakes.

Now, there are two Ministers recently appointed in the two new States that have been created. And what a mess they have made! They say on the one hand that they are out to root out corruption, and on the other, they have put in the Ministry people who have been condemned for their actions in the past by no less a man than the Chief Justice of the Supreme Court; you have put them in. You had your experience and you had a very powerful man in the Punjab; because of his corruption he had to come down and I considered the Government of India responsible for the murder of Kairon because they allowed him to go on in a blind way till somebody killed him. If they had checked this corruption in time he would have been living today and perhaps there may not have been the partitition of the Punjab.

Today, the Minister for Planning, Shri Asoka Mehta, when there a talk of money for pension for old age, he said we have not got money and we must look to our resources. This Government have never looked to the resources of the country. It has always relied upon resources that will come from outside and these improverish the country. In one State newly created, they have appointed 11 Ministers, one Speaker, one Deputy-Speaker, making 13 in all. I hear that there are only 40 Congress Members. There One-third of the Congressmen are Ministers. Here also, one-fith or one-sixth of the Congress Members are Ministers. They do not see that they are wasting the money of a poor country in multiplying offices for themselves and also for their officers. I have heard Chief Ministers saying that the efficiency of the administration will increase if 33 per cent at least of the incumbents that are occupying the places today were taken off. Why did this staff increase? Because everybody had a nephew or a nephew-in-law or a villager or a villager-in law or a caste-man or a caste-man-inlaw to be accommodated. They have been blindly going on multiplying offices till these employees are a burden on the administration.

[Shri J. B. Kripalani]

I also have in the past managed offices. I held that if one more man in the office would spoil the discipline, I would say I would have one less and give overtime allowance to those who are working than have one more superfluous man. On the admission of the authorities themselves, 33 per cent of the staff is absolutely useless and it spoils the work of the other 67 per cent.

The Government blame the opposition. Of course, the Opposition parties are to blame for creating confusion in this House, but the Congressmen are more to be blamed because having a sure majority, yet, they create confusion in this House, and the confusion gests worse confounded.

Further, these people who give lectures to us, to be well-behaved, to unite with the Government—are they united amongst themselves? In every State, there is a division between Congressmen and Congressmen. Who started the agitation between Karnataka and Maharashtra? They were the Chief Ministers of the two States. They who should know better raised a Frankenstein which will swallow them up. Again, who is responsible for this Andhra trouble today? I say that it is the Chief Minister of Andhra Pradesh and the Congressmen who are responsible for what is happening there. This is not something that has been done by the Opposition. The Opposition might have helped a little but the original sin is that of Congressmen. And I challenge any Congressman to contradict this.

Not only has the Maharashtra and Karnataka trouble been created by the Congressmen but even the Defence Minister who should be above all parties, because he has to defend the country, joins in the fray. You in the Government alongwith the Congressmen create confusion. I will not talk of UP. It is a sacred subject! But everybody knows what is happening there. If I were free, I would give you an account of Uttar Pradesh that will take your breath away.

**Shri Thirumala Rao** (Kakinada): Are you not free?

**Shri J. B. Kripalani:** I am not free because you will say he is defending his wife. You have often said that. Do I not know you people? When I stand for election you say he should go and learn wisdom from his wife. When my wife stands for election as Chief Minister, you say that she will go and give all the secrets of the Cabinet to her husband! Have I not experience of these things? You never see a belt but you must hit below it. I have seen this. This is a temptation to you.

Then about the students trouble. I will say nothing; let Mr. Chagla say. What does Mr. Chagla say? We are talking about the autonomy of the universities. But he said that the Vice-Chancellors of universities are appointed not because of their academic qualifications but for political reasons. I do not appoint Vice-Chancellors; nor does anybody in the Opposition appoint them. It is the Congresmen; it is the Congressmen who dabble in the Politics of the universities, and take away the autonomy of the universities.

They are responsible. I say they are also responsible for the trouble among the students. One section of Congressmen is called 'ministerialists' and the other section is called 'dissidents,' and it is the job sometimes of the ministerialists and sometimes of the dissidents to excite students and to make them to rebel against lawful authority. First of all, the authority is not lawful and, then, whatever authority there is, is destroyed by ministers in the Congress. I hold them responsible.

Shri Chagla said—that Vice-Chancellors appointed for other reasons, for political reasons, for non-academic reasons and they are slaves of these ministers who appoint them. Do you expect slaves to keep law and order?

Do you expect them to keep discipline? Do you expect them to be good examples to their students? You cannot expect it. I hold the Congress governments responsible for the students trouble.

I have been a teacher for long years and I never had trouble with the students. Why is there trouble now? It is because the students are taught by those who are not competent in their subjects, by those who do not treat them as they should treat their children. Even if one virtue out of these two is present in a teacher the students will never create trouble. I have seen teachers, a good men, who treat the students as their own children who are affectionate to them, who invite them to tea-parties, who, if they smoke, can offer them cigarettes and so on. Such teachers even if they do not teach well, the students say, "they are a good men and they should not be disturbed." I have also seen teachers who are very harsh, who are disciplinarians but who teach their subjects very well. About them the students say, "whatever may be their faults, they are good teachers, therefore they should not be disturbed." But here we have teachers who lack both these qualities. How do you expect the students to be disciplined.

There is another thing that the Government, the Minister of Education, has to take care of. There are conferences of these Vice-Chancellors. There are conferences of these Ministers. There are conferences of policemen. All these Conferences are very good in their own way. But have a conference which will go into the details of what is happening in, what are called, the students' unions. Every student union has thousands of rupees at its disposal and their executive dispose them of as they like. Every young man who becomes the President of the Union wants to show his strength by engineering a strike. Thus he gains popularity. I can tell you, 95 per cent of the students want to study. It is these 5 per cent who are responsible for all this trouble. Remember that you have convened many conferences, but you have not tackled this question of so much money being in the hands of students who do not know how to utilise that money. Sometimes they have invited me. When they invite me they listen to me. After listening to me they say: "Sir, come for a tea-party". I say: "I have no time for a tea-party." Who goes to that party? A few professors and the executive of the students' union go. Like that money is being wasted. Therefore, there must be an enquiry as to what these unions do. They spoil the atmosphere of the colleges and universities. Unless you tackle this question you cannot tackle the question of discipline among students.

I remember, in one place in Uttar Pradesh and, therefore, I have to talk of it—some school students came and said: "Sir, we are going on a strike today. I asked: What grievances have you?" Their reply was: "We have no grievances, but our leaders in Allahabad and in Lucknow have given the command to strike and so we are going on strike." They plainly said that they had no grievances. You cannot reason with these children who get such bad example, who got such bad example from these executives, as also from their Vice Chancellors who are slaves of the politicians in the Government. To all these things the Congressmen have to reply, and if they do not reply they are talking with their tongue in their cheeks.

Then there is the food problem. In the days of Shri Patil he said that he was geeting grain from America for building up a buffer stock. But when the monsoons failed, when there were floods, when there was drought, we did not hear anything of this buffer stock. I do not know where they went, because it is difficult to know the activities of men and mice here. Buoth men and mice swallowed away the buffer stock. It is not as if for the first time there is drought in India

[Shri J. B. Kripalani]

or for the first time there are floods in India. We are periodically used to these and we must provide for them.

If we think in terms of planning, planning means foresight, scientific forestight. Unfortunately, we have not even the hind-sight. Even Chiang Kai-shek could improve, but our Government does not improve by experience. Then what happens? There is confusion. Then the police is asked to act. The police know only one way, that of firing at people. I think I cannot condemn the police for firing. For instance, in Andhra they wanted to attack the oil refinery. I really find fault with the Opposition who say that the police should not use violence. If a refinery is set on fire, I do not know what would happen. Then there are students who have gone and looted the treasury or at least tried to loot the treasury. Of course, in a treasury, there is nothing, there is only paper, and paper can be printed again. But, after all, it is called a treasury, as the Congress is Congress though it may not be now the Congress of Mahatma Gandhi. It may be a dead Congress, but it is Congress. Names do not change but the nature of the things that are there change. When I was a child, when I was crawling and could not even wear my clothes I was called Kripalani, now also I am called Kripalani and when I die they will say that Kripalani died. Names do not change but things change. You must remember that the police brought up in the traditions of the Britishers will always resort to firing but it is for us to see that such situations are not brought about. We can do that if we avoid mistakes. If the Andhra Congressmen had not started this agitation the Opposition would not have done so. If the trouble between Maharashtra and Karnatak had not been started by the top Congressmen, the Opposition could not have done it. They could have done a little mischief but not much. But when the ruling party itself in one State is against the ruling party in another State, it can do incalculable harm to the country. Let Congressmen look within themselves. They might have the votes, but I say they have not the moral authority that a good government always has. They have the physical authority, and they use that physical authority and, as I say, they are entitled to use it in order to see that there is no greater confusion than what they have themselves created. All right, they use their physical power. Where do they use it? I am sorry, I am going to touch on a very delicate subject. Here, in this capital, a man is sitting with his wife and his wife is taken away. When Ram's wife was taken away, neither Ram nor Lakshman was there. But here both Ram and Lakshman are sitting here and doing nothing. Why don't the Government ask the police to shoot people who commit such crimes? In Mahabharat, when Dussasan, wanted to take away the clothes of Draupati, the elders were sitting tongue-tied and helpless. Here you the elders are sitting with the police but you cannot defend your women.

15 hrs.

Gandhiji brought women out of their homes and purdahs, in those days women could go in the streets without fear. Women could safely travel from one part of the country to another. Today no woman in Delhi can go out without a chaperon; today no woman can travel without some male companion. Gandhiji took the women out of the purdah and brought them in the open. Today by our inefficiency we are going to thrust them back into purdah. Are there no men left here to protect them?

We have allowed our women folk to occupy the highest position. How degraded are we that we attack the character of those whom we have ourselves appointed to these high positions? We attack their character. And let me tell you that it is not the goondas that attack their character, but

it is the politicians that attack their character. Because, goondas are not interested in their character; it is the politicians that want to demounce them, to displace them. Therefore, they malign them and their character. I can under stand it if women who choose to be in politics are criticised for their political sins of omissions and commissions. But to put women in the highest positions and then attack their character is the meanest thing. It is never done. Yet, it is done in this country, and I say it is done by politicians, some of whom are Congressmen.

Sir. you should excuse me if I use strong words, because I can use no other language. In the Ramayana even Ravana did not touch the woman. But the Ravans of today are molesting them. But today we allow our women to be dishonoured and we allow our police to fire on the students, we allow our police to fire on the mob, but in this city the Home Minister has not got the guts to tell the Superintendent of Police that unless you produce the culprit you will be no more, you will go. He talks of fighting bribery and includes bribe-taking Ministers in the Cabinet. He uses the police and justifies it. I also justify the use of police when oil refineries are attacked, or when treasuries are attacked, though the treasury may consist only of inflated money printed in Nasik, which can be printed again. I do justify that kind of action. But I would justify it more if the police force is used to protect and safeguard the honour of our womenfolk. India has always prided upon the honour of her women. Because of the honour of one woman we had the Ramayana war and so also Mahabharata war. But here these elders sit still and do nothing when some people malign the character of our women, not in the political field but in a personal way.

**Mr. Deputy-Speaker:** He should conclude.

**Shri J. B. Kripalani:** Sir, if you want me stop, I will stop here. I have only a few words to say. I am in earnest. I am not talking in vain. I talk of things that I have seen and I talk of things that you have seen. The previous speaker attacked the opposition. However cursed the opposition may be, it cannot bring about the fall of the country. If the country falls, it is because those who rule the country are at fault. Even in this age of famine, when Government itself has admitted that 41 districts out of 54 districts in UP are affected by drought, in Bihar not only is there no food but the administration has also cracked, in these days I have seen people thinking only of their tickets, people thinking only of the position they will occupy and how they can displace others so that they can occupy those places. This is the condition in the country today.

If you think that I have said anything that is wrong, you dismiss it, but please keep your house in order. Now it is a house divided against itself. When a house is divided it is standing on sand, the flood may come and sweep it away. Things do not fall physically first; they first fall morally; physical destruction may come later. The destruction of the Congress Government is Congressmen pitted against one another. Even Congressmen admit it in their private talks, but in public they give the vote to Congress. So, this vote has no meaning. You have corrupted even the voters by bringing in caste, money and liquor in order to get your people elected. Take away these things. For God's sake, save this land of Gandhiji and and do not play with our destiny. We had a great man who led us. Let us all be a little worthy of the inheritance that we have received. It is said that it is not only at the time when liberty is achieved that sacrifice is needed but every generation has to make sacrifice for safeguarding liberty; eternal vigilance is the price of freedom. Congressmen have got to be more vigilant before they accuse the opposition parties. Opposition parties do make confusion, but you add to the confusion. Please, for

[Shri J. B. Kripalani]

God's sake, consider the words that I have spoken and at least take care of our women folk, if you can do nothing else.

**श्री म० ला० द्विवेदी** (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस अविश्वास के प्रस्ताव को माननीय श्री त्रिवेदी जी ने इस सदन में उपस्थित किया है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर त्रिवेदी जी अपने दल में ही अपने प्रति विश्वास प्राप्त करने का प्रस्ताव रखते तो उनको वह विश्वास प्राप्त न होता। इसका कारण यह है कि जनसंघ की नीति जो है, जो उसकी परम्परा है उसके विरुद्ध उनका आचरण है। उदाहरण के लिए मैं कहूंगा कि जनसंघ की नीति यह है कि देश की भाषा हिन्दी हो। लेकिन जब वह भाषण अपना करते हैं, अविश्वास प्रस्ताव पेश करते हुए जो भाषण उन्होंने दिया है या किसी महत्वपूर्ण बात को कहते वक्त जिस भाषा में वह उसको कहते हैं, वह एक विदेशी भाषा है, अंग्रेजी भाषा में वह भाषण करते हैं और आज भी उन्होंने इसी भाषा का प्रयोग किया है। इसलिये मुझे यही कहना पड़ रहा है कि :

त्रिवेदी जी बनने चले हैं अफलातून,
पैरों तले है टोपी, सिर पर है पतलून।

टोपी से मेरा मतलब भारतीयता से है और पतलून से मेरा मतलब अंग्रेजियत से है।

**एक माननीय सदस्य** : फिर कहिए।

**श्री म० ला० द्विवेदी** : "त्रिवेदी जी बनने चले हैं अफ़लातून, पैरों तले है टोपी, सर पर है पतलून।"

श्री त्रिवेदी की यह हालत है कि वह जनसंघ की नीति पर अविश्वास करते हैं, उसकी बेसिक नीति के ख़िलाफ़ बोलते हैं, उनके अपने दल में उन को विश्वास नहीं मिलता है, लेकिन यह हमारी सरकार के विरुद्ध अविश्वास-प्रस्ताव लाने की चेष्टा करते हैं।

क्या विरोधी दलों की ओर से बार-बार अविश्वास-प्रस्ताव लाना इस सदन का उपहास करना नहीं है ? क्या वे लोग इस तरह इस सदन को एक तमाशा नहीं बनाना चाहते हैं ? आप देखिए कि पिछले सैशन में एक अविश्वास-प्रस्ताव आया और उससे पहले सैशन में भी अविश्वास प्रस्ताव आया। क्या देश के सामने इस सरकार पर अविश्वास की समस्या ही सबसे बड़ी समस्या है ? अभी आचार्य कृपलानी ने कहा कि देश पर संकट घिरा हुआ है और उत्तर प्रदेश, बिहार तथा मध्य प्रदेश की स्थिति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सूखे से लोग भूखे मर रहे हैं। क्या विरोधी दलों के सदस्यों के लिए यह अधिक उचित नहीं था कि वे अविश्वास-प्रस्ताव लाने से पूर्व सूखे की स्थिति पर बहस की मांग करते ? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आज विद्यार्थी देश भर में खूंरेजी कर रहे हैं, बसों और रेल के डिब्बों को आग लगा रहे हैं, लोगों से मारपीट कर रहे हैं और कानून की अवज्ञा कर रहे हैं। क्या विरोधी दलों का यह कर्त्तव्य नहीं था कि वे उन विद्यार्थियों के पास जाकर उनके आंसू पोंछते और उनसे पूछते कि उन की मांगें क्या हैं ? लेकिन नहीं, वे छिप कर उनके बीच में जाकर तोड़-फोड़ और आगजनी का काम खुद करते हैं और नाम विद्यार्थियों का लगता है। अगर विद्यार्थियों की अपनी कोई मांग होती, तो वह शिक्षा सम्बन्धी मांग होती, उनकी अपनी समस्याओं को हल करने की बात होती। लेकिन आज विद्यार्थियों की तरफ से जो इस प्रकार की मांगें की जा रही हैं कि अमुक प्रिंसिपल को हटा दो, अमुक काम कर दो, वे मांगें विद्यार्थियों की नहीं हैं। इन मांगों की आड़ में ये लोग विद्यार्थियों में क्रान्ति की आग फूंक रहे हैं।

कम्युनिस्ट भी इस अविश्वास-प्रस्ताव में शामिल हो रहे हैं। मुझे मालूम है कि हर

विश्वविद्यालय में कम्युनिस्टों के कुछ लोग जाते हैं और उनको आन्दोलन करने और तोड़-फोड़ की कार्यवाहियां करने के लिए उकसाते हैं।

**डा० मा० श्री अणे** (नागपुर) : कांग्रेस वाले भी जाते हैं।

**श्री म० ला० द्विवेदी** : कांग्रेस वाले भी जाते हैं, लेकिन वे क्रान्ति करवाने का प्रयत्न नहीं करते हैं, वे आग नहीं लगवाते हैं, लेकिन ये लोग तो बसों और अन्य राष्ट्रीय सम्पत्ति को क्षति पहुंचाते हैं। उनकी हालत यह है : "कथनी है कुछ और, कुछ और है करनी, चीन की सरकार को ये मानते हैं जननी।" ये कम्युनिस्ट देश की राष्ट्रीयता के विरुद्ध हैं, समाज के विरुद्ध हैं। वे किसी भी काम में साथ नहीं देना चाहते हैं। वे यहां आ कर डेमोक्रेसी का ढोंग और स्वांग रचते हैं। वे पाखण्डी, धोखेबाज और देश के ग़द्दार **हैं**

स्वतन्त्र पार्टी वाले भी इस अविश्वास-प्रस्ताव में शामिल हैं। उनका यह हाल है कि "परम स्वतन्त्र, न सर पर कोई, साख इन्होंने अपनी देश में खोई।" जहां तक स्वतन्त्र पार्टी का सम्बन्ध है, जो असन्तुष्ट कांग्रेस वाले थे, जिनको मिनिस्टर नहीं बनाया गया, जिन को ऊंचा ओहदा नहीं मिला, वे स्वतन्त्र पार्टी में चले गए। यह पार्टी देश भर में अपनी साख खो बैठी है। क्या इस सदन में अविश्वास-प्रस्ताव लाना और तोड़-फोड़ की कार्यवाही करना ही उनका काम है? गांधीजी और कांग्रेस ने भी आन्दोलन किया था, लेकिन गांधीजी के आन्दोलन के पीछे रचनात्मक काम था। वह चरखा चलाते थे। उन्होंने हरिजनों के उद्धार का काम किया था। उन्होंने नमक बनाने का काम हाथ में लिया था। उन्होंने देश भर में रचना के कामों की एक ऐसी लहर चलाई थी कि आज हम लोग उनको बापू के नाम से पुकारते हैं। विरोधी दल के लोग भी महात्मा गांधी को बापू कहते हैं, लेकिन वे उनके सिद्धान्तों के अनुसार आचरण नहीं करते हैं। कोई भी रचनात्मक काम बता दीजिए जो विरोधी दल अपनाए हुए हैं। वे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जाकर ग़रीब किसानों के आंसू नहीं पोंछना चाहते हैं। वे विद्यार्थियों को सन्तोष दिलाने का काम नहीं करना चाहते हैं। आज देश भर में विग्रह फैला हुआ है, भुखमरी फैली हुई है, लेकिन उसमें उनकी रुचि नहीं है। उनकी रुचि केवल इसमें है कि इन्दिरा गांधी की सरकार को, कांग्रेस सरकार को हटा दिया जाये। वे जानते हैं कि उनके अविश्वास-प्रस्ताव में इन्दिरा गांधी की सरकार नहीं हट सकती है, क्योंकि उसके पास दल की ताकत है। अगर वे उसको हटाना ही चाहते हैं, तो पहले वे दल को इकट्ठा करें, बहुमत इकट्ठा करें और वह चुनाव से पहले नहीं हो सकता है। तो फिर यहां पर अविश्वास-प्रस्ताव लाना बकवास करना नहीं, तो और क्या है? यह जनता के धन को बर्बाद करना है। वे इस अविश्वास प्रस्ताव को इसलिए लाए हैं, ताकि वे जनता के सामने साबित कर सकें कि हमने सरकार के दोषों और ग़लतियों को प्रकट किया है।

मैं मानता हूं कि सरकार में दोष है। मैं यह भी मानता हूं कि देश में बड़ी खराबी पैदा हो गई है। लेकिन क्या सरकार उसका उपाय नहीं कर रही है? क्या वह उसका उपाय नहीं करना चाहती है? अगर विरोधी दलों का सहयोग मिले, तो जितनी बुराइयां हैं, उनमें से आधी तो फ़ौरन दूर हो जायेंगी और बाकी बुराइयां भी प्रयत्न करने पर दूर हो जायेंगी। लेकिन सहयोग देना तो दूर रहा, ये कदम कदम पर रोड़े अटकाते हैं। आप रोज देखते हैं कि रोज एक, डेढ़, दो घंटे का समय, जो कि शून्य का घंटा कहलाता है, बेमतलब की बहस में चला जाता है, सरकार

**The words were subsequently withdrawn by the Hon. Member, *vide* Debates dated 4-11-66—Motion of No-Confidence in the Council of Ministers.

[श्री म० ला० द्विवेदी]

का रुपया व्यर्थ जाता है और जो काम हम करने आए हैं, उस को हम नहीं कर पाते हैं।

जो लोग अपने को समाजवादी कहते हैं, वे भी इस अविश्वास-प्रस्ताव में शामिल हैं। उनकी स्थिति यह है: "तानाशाही है मन में, ऊपर समाजी बाना, हुल्लड़बाजी को हो इन ने ईश्वर माना।" वे सिर्फ हुल्लड़बाजी से प्रजातन्त्र को चलाना चाहते हैं। लेकिन क्या जनता मूर्ख है कि वह यह नहीं समझे ी कि ये किस तरह से हम को बर्बाद करना चाहते हैं और समाजवाद के नाम पर हुल्लड़बाजी के द्वारा अपनी पार्टी को जनता में लोकप्रिय बनाना चाहते हैं? एक भी ऐसा समाजवादी बताया जाये, जो जनता के पास जाकर उसके लाभ और हित की बात करता हो। वे यहां नहीं हैं, लेकिन वे मेरे भाषण को पढ़ लेंगे, सुन लेंगे। अगर उनमें काम करने का बूता है, तो वे जनता में जाकर रचना के काम करके दिखायें और यहां पर अविश्वास-प्रस्ताव में शामिल होकर व्यर्थ के अफ़लातून बनने की कोशिश न करें।

आने वाले चुनाव में हम कैसे जीतेंगे, हम कांग्रेस को कैसे बदनाम कर सकते हैं, सिर्फ इस लक्ष्य को लेकर उनके सब काम यहां पर हो रहे हैं। ये लोग केवल बकवासबाजी और बातों के ज़रिये गढ़ जीतने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि भारत की जनता बहुत समझदार है। उसने देखा है कि कांग्रेस की सरकार ने केवल अभी से नहीं, बल्कि जब से कांग्रेस ने जन्म लिया, तब से लेकर आज तक वह रचनात्मक काम करती रही है।

आचार्य कृपलानी कांग्रेस वालों को कहते हैं कि उनको कुछ सीखना चाहिए, उनको अपना घर ठीक करना चाहिए। क्या उन्होंने इस बात की ओर ध्यान दिया है कि उन जैसे ईमानदार आदमी कांग्रेस से बाहर चले गए और अवसरवादी उसमें शामिल होने लगे। लेकिन वह केवल अवसरवादियों की निन्दा नहीं करते हैं, बल्कि वह सब कांग्रेसियों को समेट कर गाली देना चाहते हैं। क्या आचार्य जी सच्चे दिल से कह सकते हैं कि उन के पुराने और ईमानदार साथी आज भी कांग्रेस में शामिल नहीं हैं? आचार्य जी भी आंख मीच कर बात करते हैं और सभी कांग्रेसमैनों को बदनाम करने की बात करते हैं। मैं मानता हूं कि कांग्रेस में बुरे आदमी भी हैं, लेकिन वे कैसे आ गए? पहले जो व्यक्ति त्याग, तपस्या और रचनात्मक काम करता था, वही कांग्रेस में सम्मिलित हो सकता था, लेकिन आज चापलूसी, चाटुकारिता, बेईमानी और पैसे के बल पर कुछ ग़लत आदमी कांग्रेस में आ आ गए हैं। ऐसे लोगों का बहिष्कार करके कांग्रेस को सुधारने की आवश्यकता है। लेकिन आचार्य जी यह बात कभी नहीं बताते हैं। वह तो कांग्रेस को बदनाम करके अपना नाम ऊंचा करना चाहते हैं कि जो कुछ हूं, मैं हूं। उनके प्रति मेरी श्रद्धा है, लेकिन वृद्ध और बुद्धिमान का कर्त्तव्य यह है कि वह सही बात कहे। कांग्रेस में अच्छे लोग भी हैं, और ज़्यादा लोग अच्छे हैं। कुछ लोग ख़राब हैं। अगर उनको हटा दिया जायेगा, तो हमारी संस्था ठीक हो जायेगी और हम अपने झगड़े तय कर लेंगे। लेकिन आचार्य जी विरोधी दलों के झगड़े में पड़ना नहीं चाहते हैं। वह हम को सलाह देते हैं। हम उनकी सलाह को मान लेंगे, क्योंकि वह वृद्ध हैं और पुराने कांग्रेसमैन हैं। हमें विश्वास है कि वह फिर हमारा साथ देंगे।

विरोधी दलों की ओर से कहा गया है कि कांग्रेस ने अपने मिसरूल से देश भर में तबाही ला दी है। अगर उनकी आंखें हैं, अगर वे सोच-समझ कर, ईमानदारी से, कुछ अनुभव करके बात करते, तो वे कहते कि कांग्रेस ने मिसरूल नहीं किया है, बल्कि कांग्रेस ने जनता को अच्छा शासन देने का प्रयत्न किया। बात यह है कि विश्व-भर में

जो समस्यायें हैं, वे समस्यायें भारत में भी हैं। हम महसूस करते हैं कि उन समस्याओं को सुलझाने के लिए जबरदस्त और तगड़े हाथों की आवश्यकता है। अगर उनका सहयोग मिले, तो हमारे हाथ मजबूत हों और हम मजबूती से उन समस्याओं को हल कर सकेंगे। लेकिन वे मिसरूल के हालात पैदा करते हैं और उसके लिए कांग्रेस गवर्नमेंट को बदनाम करते हैं। वे जगह जगह आगजनी और खून-खच्चर कराते हैं और पुलिस को गोली चलाने के लिए उत्तेजित करते हैं और फिर इन सब बातों के लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। जनता इस बात को समझ सकती है और समझेगी कि इन बुराइयों के पीछे विरोधी दल हैं, न कि कांग्रेस। कांग्रेस चाहती है कि देश में शान्ति हो, कांग्रेस गवर्नमेंट चाहती है कि देश में व्यवस्था हो और तन, मन, धन से हमारी प्रधान मंत्री और सरकार के सभी लोग लगे हुए हैं कि हम इन समस्याओं को हल करें और मुझे विश्वास है कि हम उनको हल कर सकेंगे। अगर हमारे विरोधी हमें सहयोग नहीं दे सकते तो कम से कम वे शान्त हो जायें, उल्टे सीधे प्रस्ताव रखना बन्द कर दें और देखें कि दो महीनों में स्थिति सुधरती है या नहीं। लेकिन वह स्थिति को सुधरने नहीं देना चाहते। वह समझते हैं कि वह कांग्रेस को हरा देंगे। उन्हें सोचना चाहिये कि जनता किसके हाथों में ताकत दे दे। क्या वह उन लोगों के हाथों में ताकत दे देगी जो भड़िये बैठे हैं, जो और भी बड़े बड़े घाघ बैठे हुए हैं जिन्होंने सिर्फ असन्तोष के कारण कांग्रेस को छोड़ा है और वह जनता का विश्वास पाकर जीत जायेंगे। मुझे विश्वास नहीं है कि जनता इतनी मूर्ख होगी कि ऐसे लोगों को, जो कि देश की सत्ता पर विश्वास नहीं करते, जो राष्ट्रीय एकता में सहयोग नहीं देना चाहते, जो देश में एकता कायम नहीं होने देना चाहते, जो रचनात्मक कामों में विश्वास नहीं करते, वह देश में सफल बनायेगी। जो अलग-अलग बैठे हुए हैं लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पर पचास-पचास खड़े हो जाते हैं, मगर जब उनके मन की बात कही जाती हैं, उनको जवाब मिलता है तब सारा विरोधी दल सदन में देखने को नहीं मिलता, वह गायब हो जाते हैं। किसी न किसी बहाने से भागना चाहते हैं। वह जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव का क्या हश्र होगा, लेकिन सिर्फ पब्लिक में प्रचार करने के लिये, अखबारों में नाम कमाने के लिये वह अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। मैं इस अविश्वास प्रस्ताव के प्रति अपना अविश्वास प्रकट करता हूं और चाहता हूं कि वह अपना प्रस्ताव वापस ले लें। वह सरकार को आश्वासन दें कि वह मिल कर सरकार को सहयोग देंगे, वह मिल कर सरकार को सफल बनायेंगे। जहां सरकार गलती करेगी वहां उसको समझायेंगे। अगर समझाने से सरकार नहीं समझती तो हम कांग्रेस के सदस्य यहां आंख मूंद कर नहीं बैठते हैं। हम अक्ल लेकर आये हैं, हमें जनता ने चुना है। लेकिन वह समझते हैं, उनका ख्याल है कि हम डम्ब "ड्रिविन कैटल" हैं, वही वीर हैं, बहादुर हैं, वही अफलातून सिपाही हैं देश के। मैं इस बात को गलत तरीके से चलने नहीं दे सकता। हम उन्हें समझायेंगे और उनमें बुद्धि आनी चाहिये, समझना चाहिये कि गांवों में जो लोग हैं, उन में भी अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं। वह जानते हैं कि उन में अक्लमन्द लोग हैं जिनको जनता ने चुना है। इस लिये हम परामर्श से काम लें तो संसद की कारवाई चलेगी। खाम-ख्वाह बकवासबाजी से देश का धन खराब करना है और इससे हम कहीं पहुंच नहीं सकते। इससे देश का पतन होगा और राष्ट्र के प्रति अविश्वास होगा, राष्ट्रपिता के प्रति अविश्वास होगा, जिन की वह पूजा करते हैं।

हमारे देश की कर्तव्यपरायणता, धर्म और संस्कृति ऐसी है जो यह कहती है कि खुराफात में न पड़ो, सज्जनता और सचाई से काम लो। जब सभी उपाय नाकामयाब

[श्री म० ल० द्विवेदी]

हो जायें, सभी तरीके खत्म हो जायें, कोई आपकी बात मानता न हो तब आपकी मर्जी में जो आये वह कीजिये । गांधी जी ने भी वही रास्ता अपनाया और हम भी उसी रास्ते को अपनायेंगे । हम कांग्रेस में नहीं रहेंगे जब हम देखेंगे कि हमारी बात नहीं मानी जाती । लेकिन मेरा विश्वास है कि कांग्रेस का जन जन इस बात में लगा हुआ है कि हम अपनी समस्याओं को समझें, हम देश की समस्याओं को समझें और शान्ति की स्थापना करें तथा देश में जो बड़े बड़े संकट आये हुए हैं, जैसे सूखा है, भुखमरी है और जो तबाही आई है अवमूल्यन के कारण, उनका सामना करें । कैसे हल करें, यह सुझाव कोई नहीं बतलाता । सिर्फ कहते हैं कि गलती करते हैं । अगर हम गलती करते हैं तो सही रास्ता बतलाइये । उनके पास कोई जवाब नहीं है । मेरा कहना यह है कि जो आदमी कहता है कि गलत है वह सही मार्ग भी दिखाये और बतलाये कि यह सही रास्ता है । अगर उस रास्ते को हम न अपनायें, हमारी सरकार न अपनाये, तब आपकी बात हम मान सकते हैं । लेकिन यह बात नहीं है । यहां कोई सही बात आपकी किसी के सामने नहीं आती, सिवा अविश्वास प्रस्ताव के, सिवा खाम-ख्वाह की बहस के । बेमतलब बातें करके देश में भ्रमात्मक वातावरण पैदा करने का जो प्रयत्न कर रहे हैं यह बिल्कुल गलत है, धोखेबाजी है, यह देश के प्रति गद्दारी है । इसलिये मैं अपील करता हूं ताकि उनकी चेतना जगे और वे सही रास्ते पर चलने लगें ।

अपनी सरकार से मेरी प्रार्थना है कि उन्होंने बिहार सरकार को 5 करोड़ रुपयों का अनुदान देकर बहुत बड़ा काम किया है । इस लिये हमारे विरोधी सदस्यों को यह कहना कि हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है, गलत हो गया है । मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जहां जहां खेती सूख चुकी है वहां उदारता से पम्पिंग सेट वगैरह देने का इन्तजाम करे । ताकि पुरानी फसल जो खराब हो गई वह तो हो गई लेकिन नई फसल जो रबी की है वह अच्छी हो जाये । इस तरफ वह पूरा पूरा ध्यान दे और हम कांग्रेस-मैन उनको पूरा सहयोग दें ताकि हम जनता में जाकर कह सकें कि सरकार उन की तबाही को रोकने का प्रयत्न करेगी । मैं आशा करता हूं कि हमारे सब साथी इसमें हमें सहयोग देंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं इस अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में और सरकार के पक्ष में अपना मत प्रकट करता हूं और चाहता हूं कि विरोधी सदस्य भी इसको मानें ।

**श्रीमती सुभद्रा जोशी** (बलरामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस वोट आफ नो कानफिडेंस के प्रस्ताव पर बोलते समय यदि मैं देश की स्थिति के ऊपर रोशनी नहीं डालूंगी तो हमारी सरकार के साथ भी अन्याय होगा और अपोजीशन पार्टियों के साथ भी अन्याय होगा ।

पिछले दो महीनों से मुझ को जो यू० पी० का पूर्वी हिस्सा है, जहां आजकल सूखा पड़ रहा है, वहां की स्थिति को बहुत नजदीक से देखने का मौका मिला । सितम्बर में जब वहां की खेती अच्छी तरह लहलहा रही थी और बहुत अच्छी पैदावार वहां हुई थी उस समय गांव के लोगों ने कहा मुझ से कि अगर उनको सात दिन के अन्दर पानी मिल जाये, फिर कहा कि छः दिन के अन्दर पानी मिल जाये, फिर कहा कि चार दिन के अन्दर पानी मिल जाये, फिर कहा कि तीन दिन के अन्दर पानी मिल जाये तो उनकी खेती बच सकती है । मैंने गांव गांव में जा कर देखा तो मेरा सिर शर्म से झुक गया । मैं जहां खड़ी हुई थी वहां खेत में ट्यूबवेल लगे हुए थे, चाहे वह सरकारी थे या प्राइवेट थे, उन मे से एक भी ट्यूबवेल काम नहीं कर रहा था । मैंने टेलीफोन खटखटाया, मैंने अधिकारियों के

और मंत्रियों के दरवाजे खटखटाये, पर मेरे देखते देखते वह खेत सूखते चले गये और लोगों को पानी मिलने की नौबत नहीं आई। एक भी ट्यूबवेल वहां नहीं चला।

इसी तरह से दूसरी चीज मैं अर्ज करना चाहती हूं। उन सब चीजों का यहां पर बहुत जिक्र हुआ। लालेसनेस की बहुत सी बातें यहां हुईं। जब मैं इसी तरह से खेत में खड़ी इन्तजार कर रही थी कि कोई ट्यूबवेल आता है या नहीं, तब वहां पर एक मजमा चला आया। गांव के उन लोगों के हाथों में लाठियां थीं, उनके हाथों में बन्दूकें थीं, उन के हाथों में फरसे थे, उन के हाथ में तमाम किस्म के हथियार थे। मैं ने उनसे मजाक में पूछा कि आप कहां जा रहे हैं, कहीं हमला करके आये हैं या कहीं हमला करने जा रहे हैं। तो वह बोले कि वह मेरे दर्शन करने के लिये आये हैं। मैं ने कहा कि दर्शन करने इस तरह से आये हो। तो बोले कि आपकी सरकार में हमें जिन्दगी का खतरा है, हम हमेशा इसी तरह से घूमते हैं। उन्होंने कहा कि हम स्टेशन पर जा रहे थे एक गांव के आदमी को छोड़ने के लिये लेकिन हथियार देख कर पुलिस ने हमें लौटा दिया। मैंने पूछा कि तुम्हारे साथी का क्या हुआ जिस को छोड़ने जा रहे थे। तो बोले कि उसको पुलिस थाने पहुंचा दिया गया। जिस वक्त मैं उन से खड़ी बात कर रही थी उस वक्त जीप खेत के बाहर से गुजरी। उस में भी हथियार रखे हुए थे। मैं ने उन लोगों से पूछा कि क्या वह आपकी जीप है। उन्होंने कहा नहीं, जो हमारे दुश्मन हैं उन की जीप है। मैंने उनके पूछा कि इस तरह से तुम हथियार लिये हुए क्यों घूमते हो और वह हथियार लिये हुए क्यों घूमते हैं तो जो मजमा खड़ा था उस ने अपने अपने किस्से बयान करने शुरू किये। एक ने कहा कि जो जीप के अन्दर जा रहा था उसने मेरा हाथ तोड़ दिया, दूसरे ने कहा कि उसने मेरी पसली तोड़ दी, तीसरे ने कहा कि उसने मेरी लड़की उठा ली और चौथे ने कहा कि उसने हमारे पड़ोसी को मार दिया। विक्टिम आदमियों का जो गिरोह था वह बलरामपुर के गांव में हथियार लिये-लिये घूम रहा था। मैं ने बलरामपुर के उस गांव का इस लिये जिक्र किया कि मैं उस को एक नमूना महसूस करती हूं। मैं इस लिये उसका जिक्र नहीं कर रही हूं कि मेरा उससे खास सम्बन्ध है, पर मैं समझती हूं कि हिन्दुस्तान में इस प्रकार के हजारों गांव होंगे जहां के छोटे छोटे किसानों ने सिचाई की है लेकिन जिस के 100 बीघे जमीन है वह 50 बीघे वाले की जमीन छीन लेता है, जिस के पचास बीघे जमीन है वह दस बीघे वाले की जमीन छीन लेता है और गरीब आदमी घूमते फिरते हैं। वह अदालतों के चक्कर लगाते रहते हैं लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। यह एक नमूना मैं ने आपके सामने पेश किया।

साथ ही साथ विद्यार्थियों की भी कुछ बात यहां पेश करना चाहती हूं। पांच वर्ष पहले वहां चुनाव हुआ। उस वक्त एक कालेज के विद्यार्थी कांग्रेस की तरफ हो गये और एक कालेज के विद्यार्थी दूसरी पार्टी की तरफ हो गये जो कि मुखालिफ पार्टी थी। जो कालेज था वहां से विद्यार्थी निकाल दिये गये, प्रोफेसर्स निकाल दिये गये, ला क्लासिस का पढ़ाना बन्द कर दिया, उसकी ईंट से ईंट बजा दी गई। यह सब इस वास्ते हुआ कि राजनीतिक विक्टिमाइजेशन वहां हुआ। न विद्यार्थियों की किसी ने सुनी, न टीचर्ज की सुनी, न प्रोफेसर्स की सुनी। उन लोगों ने जिनका वह कालेज था इस तरह से तबाही मचाई कि आज वहां पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं रह गया है। किसी ने उनकी नाहीं सुनी। वाइस चांसलर के पास वे गये, चांसलर के पास वे गए, मिनिस्टर के पास वे गए, लेकिन कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हुई, उन के साथ किस तरह से अन्याय किया गया, है, इसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। यह मैं आपको विरोधी दल वालों की कारगुजारी बता रही हूं जो कि आज

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

हमारे विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया है।

आज उनकी तरफ से यह कहा जाता है कि इस सरकार को हट जाना चाहिये, यहां पर देश में ला-लेसनेस है, देश में भुखमरी है, यहां पर सूखा पड़ गया है, यहां पर विद्यार्थियों की शिकायतें सुनी नहीं जाती हैं, यहां पर गोली चलाई जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर यही कारण हैं जिनकी बिना पर सरकार को चले जाना चाहिये तो मैं कहूंगी कि सब से पहले अपोजीशन वालों का अपने पदों से हट कर चले जाना चाहिये। जिस जगह का मैं जिक्र कर रही हूं वहां पांच असेम्बली की सीट्स हैं जिन में से चार सीटें जनसंघ के पास हैं। यह बलरामपुर की बात मैं आपको बता रही हूं। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या किसी अपोजीशन के आदमी ने वहां जाकर देखा है कि कहां सूखा पड़ा है, क्या किसी अपोजीशन के आदमी ने जाकर देखा है कि वहां किसानों की जमीनें छीनी जाती हैं, लोग वहां पर जमा होकर तलवारें और बन्दूकें लेकर घूमते हैं। जनसंघ के एक म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं जिसकी शिकायत है कि हमारा हाथ तोड़ दिया है, किसी ने कहा है कि मेरी पसली तोड़ दी है, किसी ने कहा कि जमीन छीन ली है, किसी ने कहा कि लड़की उठा ली है। आज वहां के लोगों की जुर्रत नहीं है कि कोई जा कर पुलिस में उसकी रिपोर्ट लिखा सके। इतना आतंक उसका है।

आज विरोधी दल वाले हमारी नुक्ता-चीनी करते हैं। क्या नुक्ताचीनी करना ही उनका कर्त्तव्य है? उनको देखना चाहिये कि उन्होंने कौन सा रोल प्ले किया है जब कोई संकट देश के सामने उपस्थित हुआ है। लोग पूछते हैं कि अगर कांग्रेस चली गई तो कौन सी पार्टी कांग्रेस का स्थान ले सकती है, कौन सी जमात है जो इस सरकार को हटा कर सरकार बना सकती है? मुझे तो कोई दिखाई नहीं देती है और न जनता को दिखाई देती है। मैं आपको उस जमात की बात बता रही हूं, उस जमात का हाल बता रही हूं जिस जमात के माननीय सदस्य ने यह प्रस्ताव पेश किया है। और भी इस जमात के बारे में आप से निवेदन करना चाहती हूं। जब चीन ने हम पर हमला किया तो हमारे अपोजीशन के भाइयों ने बहुत से विदेशी मामले भी उठाये थे और बहुत से देश के अन्दर के मामले भी बताये थे। विदेश की बातों का मैं जिक्र नहीं करना चाहती हूं क्योंकि अन्दर के अपने प्राब्लेम्स ही बहुत हैं। जब चीन ने हम पर हमला किया तो इस पार्टी के लोगों ने, जन-संघ के लोगों ने डिफेन्स में कौन सा हिस्सा लिया? यहां आकर इन्होंने कहा कि हम सरकार के हाथ मजबूत करना चाहते हैं लेकिन दिल्ली की सड़कों पर, हिन्दुस्तान के कोने कोने में जाकर इन्होने भाषण दिये और कहा कि सिपाहियों, तुम जो फ्रंट पर जा रहे हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। इन्होंने कहा कि फौजियों के पास कपड़ा नहीं है, उनके पास जूते नहीं हैं, उनके पास बन्दूकें नही है। जिस वक्त हमारे देश के नौजवान अगर उनका वश चलता तो खाली हाथों से चीनियों का मुकाबला करके उनको खदेड़ देते, जिस वक्त उनके अन्दर कुर्बानी का जजबा था, इस जमात ने उनको डिमारे-लाइज करने की कोशिश की। जिस वक्त रिक्रूटिंग आफिसेस के सामने हजारों आदमियों की भरती होने के लिए भीड़ लगी रहती थी उस वक्त इस जमात ने दिल्ली के अन्दर रामलीला मैदान में, गांधी ग्रांउड में, एल० आई० सी ग्राउंड में और हिन्दुस्तान के कोने कोने में कहा कि वहां जो फ्रंट पर लड़ाई करने के लिए जाते हैं, उनके पास तमंचा नहीं हैं, उनके पैरों में जूते नहीं हैं, पहनने के लिए उनको कमीज नहीं दी जाती है, बरफ में उनको भेजा जा रहा है लेकिन बरफ से बचाव का उनके पास कोई सामान नहीं है यह है वह तरीका जो कि इन्होंने सिपाहियों की हिम्मत बढ़ाने के लिए अपनाया।

जब सरकार ने कहा कि उसको सोना चाहिये तो इन्होंने कहा कि सोना मत दो, इस सरकार का कोई भरोसा नहीं हैं, इस सरकार पर भरोसा मत करो। इन्होने फौजियों से कहा कि क्यों मरने जाते हो, तुम्हारा मिनिस्टर चीन से मिल गया है। हर तरह से इन्होंने डिमारेलाइजेशन का वतावरण पैदा करने की, कोशिश की। यह इनका एक बड़ा भारी कांट्रीब्यूशन था देश की मुसीबत के समय में। इस के बाद पाकिस्तान का हमला हुआ। तब इन्हों ने जो नफरत फैलाई, माइनोरिटीज के खिलाफ जहर उगला उस को मैं आप को बतलाना चाहती हूं। इन के आर० एस० एस० के लोगों द्वारा यह कहा जाता था कि काश्मीर के मुसलमान तो हिन्दुस्तान के साथ हैं लेकिन बाड़ा हिन्दू राव के मुसलमान साथ नहीं हैं, दिल्लो के मुसलमान साथ नहीं हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, हैदराबाद के मुसलमान साथ नहीं हैं। मुझे याद है वह दिन जब काश्मीर के अन्दर इनफिल्ट्रेटर्ज आए थे और पाकिस्तान ने उन को यह कह कर भेजा था कि जाओ, काश्मीर के मुसलमान तुम को छाती से लगा लेंगे, वहां जा कर कब्जा कर लो। उस वक्त हमारे प्रकाशवीर जी काश्मीर गए और वापिस आ कर उन्हों ने एक लम्बा चौड़ा भाषण दे डाला। अपने बयान में उन्हों ने कहा कि काश्मीर के सारे मुसलमान पाकिस्तान के साथ हैं। यह कौन सा देश प्रेम उन्हों ने दिखलाया? कौन से देश प्रेम का सबूत दिया उन्हों ने यह कह कर। फौरन ही हिन्दुस्तान की जनता ने, हिन्दुस्तान के अव्वाम ने समझ लिया कि इस वक्त हिन्दुस्तान के अन्दर माइनोरिटी मौजारिटी का सवाल नहीं है और यह सवाल नहीं उठाना चाहिए, हिन्दू और मुसलमान का सवाल नहीं उठाना चाहिये और अगर यह सवाल उठाया गया तो इस से देश कमजोर होगा और उन्हों ने इस किस्म की बात को सुनने से इन्कार कर दिया। यह सब मैं इस वास्ते बता रही हूं कि जिन्हों ने इस प्रस्ताव को यहां रखा है उन का क्या रोल रहा है।

एक और बात मैं आपको बतलाना चाहती हूं। जब देश का पार्टिशन हुआ, देश के दो टुकड़े हुए तब वैस्ट पाकिस्तान से तमाम हिन्दू भाई आ गए लेकिन हिन्दुस्तान से तमाम मुसलमान पाकिस्तान नहीं चले गए उन्होंने हमारे हैं नेताओं पर, गांधी जी पर, नेहरू जी पर विश्वास किया और करोड़ों की तादाद में वे यहां रह गए। लेकिन इस प्रासेस में आप देखें कि देश का बटवारा नहीं हुआ बल्कि फैमिलीज का बटवारा हो गया। दुर्भाग्य से अगर बाप यहां रह गया तो बच्चा पाकिस्तान में चला गया, एक भाई यहां रह गया तो दूसरा भाई पाकिस्तान में चला गया बहने किसी की यहां रह गई तो उनके भाई पाकिस्तान चले जाए, बहने वहां तो भाई यहां रह गए। इस तरह से फैमिलीज का बटवारा हो गया। फौज में हमारी माइनोरिटी के लोग भी थे, मुसलमान भी थे और इतिहास गवाह है कि उन्होंने रावलपिंडी पर जा कर बम फेंके, सियालकोट पर जा कर बम फेंके, पेशावर पर जा कर बम फेंके। उन्होंने यह नहीं सोचा कि बम मेरे बाप पर गिरता है, यह नहीं सोचा कि भाई पर गिरता है, यह नहीं सोचा कि मेरे बच्चों पर गिरता है। हिन्दुस्तान की माइनोरिटीज ने यह सबूत दिया कि उनके बच्चों से ज्यादा प्यारा उनको भारत है, उनके रिश्तेदारों से ज्यादा प्यारा उनको यह देश है। इस सब चीज को देख कर जन संघ को अपना रवैया बदलना पड़ा। उस समय नफरत की बात वे नहीं कह सके। थोड़े दिन वे चुप रहे। उसके बाद व्हिसपरिंग कम्पेन चला। ऊंची ऊंची जगहों पर मुस्लिम लीडर थे, माइनोरिटी के लोग थे उनके खिलाफ इन्होंने कम्पेन चलाया। जिस वक्त हम कह रहे थे कि हिन्दुस्तान में हिन्दू और मुसलमान सब एक हैं तब इस जमात के लोगों ने जानबूझ कर कहानियां फैलाई, किस्से फैलाये, कभी कहा कि उपराष्ट्रपति जेल में है और कभी कुछ और। उपराष्ट्रपति का जब रामलीला ग्रांउड में भाषण हुआ तो

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

इन्होंने कहा कि जेल मे इनको जबर्दस्ती बुला कर लाया गया है । जब युद्ध खत्म हो गया, पाकिस्तान से लड़ाई खत्म हो गई तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के गुरुजी ने लखनऊ में जा कर भाषण दिया जिस में उन्होने कहा कि सरकार जो बहादुरी के लिए एवार्ड दे रही है वह कम्युनल बेसिस पर दे रही है । उस वक्त अबदुल हमीद को एवार्ड मिला था। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की खुशामद करने के लिए ये एवार्ड उनको दिये जा रहे हैं, नहीं तो उन्होंने कोई सेवा हिन्दुस्तान की नहीं की है। यह रवैया है जो इनका माइनोरिटी के प्रति रहा है । ये बदग्रमनी फैलाते हैं, ऊधम मचाते हैं।

ग्राजकल इन्होंने एक ग्रौर नारा दे रखा है कि गाय की रक्षा होनी चाहिये । मैं चाहती हूं कि इस सदन के सदस्य ग्रौर से इस बात को सुनें, दुनिया इस बात को समझे। एक समय था कि जब ग्रंग्रेज हिन्दुस्तान पर राज्य करता था, तो हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े पुंजीपति उस ग्रंग्रेज को, जो सिर्फ गौ-हत्या ही नहीं करवाता था, बल्कि जो गाय को खाता भी था, लाखों ग्रौर करोड़ों रुपया चन्दे में देते थे ग्रौर उस की सरकार को यहां पर मजबूत बनाने में मदद देते थे। हमारे देश में जब ग्रजादी नहीं थी, तो किस ने गौ-रक्षा का नारा लगाया था ? गांधी जी ने कहा कि हम को गाय का दूध ग्रौर घी इस्तेमाल करना चाहिये ग्रौर हम को उस की सेवा करनी चाहिये, क्योंकि हिन्दुस्तान एक कृषि-प्रधान देश है, इस लिए नहीं कि गाय का सम्बन्ध किसी एक धर्म से है, बल्कि इस लिए कि हिन्दुस्तान के गरीब लोगों को दूध ग्रौर घी मुयसर हो।

जब ग्राजादी ग्राई, तो इन पूंजीपतियों ने ग्रपनी सरमायादारी ग्रौर ग्रपनी जहनियत को छिपाने के लिए गौ-रक्षा का नारा लगाया मैं नमूने के तौर पर सिर्फ एक ही नाम लेना चाहती हूं। ग्राजादी ग्राने के बाद सब से पहले-गौ-रक्षा के लिए एक गौ-रक्षा संघ या गौ रक्षा समिति पता नहीं, उस का क्या नाम था बनाई सेठ डालमिया जी महाराज ने, जिन की डालमियावाड़ी में, जहां मुझे एक हड़-ताल के सम्बन्ध में जाने का मौका मिला, मजदूर दो रुपये रोज पर काम करते थे । ग्राजादी के बाद ग्रपनी सरमायादारी ग्रौर चोर-बाजारी को बचाने के लिए, जिस को हिन्दुस्तान के बच्चे-बच्चे ने ग्रब देख लिया है, वह गौ-रक्षा के लिए एक संस्था बना कर एक धर्मात्मा साधू के वेश में दुनिया के सामने ग्राकर खड़े हो गए ।

मैं साफ कहना चाहती हूं कि जहां तक मेरा ताल्लुक है, लोग ग्राज भी मेरे बारे में कहते हैं कि पढ़-लिख कर भी इस में पुराने विचार रह गए है, यह एम० ए० पास कर के भी गंवार की गंवार ही रह गई है, यह न तो मांस ग्रौर ग्रंडे खाती है ग्रौर न केक पेस्टी खाती है । जब मैं मुनि सुशीलकुमार जैसे जैनी महात्मा को गौ-रक्षा के ग्रान्दोलन ग्रौर उस के जलूस के ग्रागे देखती हूं, तो मुझे ख्याल ग्राता है कि जो दूसरे जानवर मारे जाते हैं, उन के बारे में ग्रावाज क्यों नहीं उठाई जाती जानवरों से प्रेम करने वाले की हैसियत से में यह बात कह रही हूं।

एक दिन मैं ने एक मुहल्ले में देखा कि एक ग्रादमी ग्रपने एक हाथ में बकरे का कटा हुग्रा सिर ले जा रहा है ग्रौर दूसरे हाथ एक जिन्दा बकरे को खींचता हुग्रा ले जा रहा है। वह बकरा चलता नहीं था। उसके पैर ग्रागे नहीं उठते थे । महीनों ग्रौर बरसों तक मुझे वह नजारा नहीं भूला उस को मैं ने देखा, दुनिया ने देखा, वह बाजार में से हो कर निकला, लेकिन उस निष्ठुरता ग्रौर क्रूरता के दृश्य के खिलाफ किसी ने ग्रपनी ग्रावाज नहीं उठाई ।

मैं लखनऊ ग्रौर दिल्ली वगैरह के स्टेशनों पर पिजरों में बन्द बन्दरों को देखती हूं। हो सकता है कि उन की कुर्बानी से इन्सा-

नियत की सेवा होती हो, परन्तु जितने दिन वे जिन्दा रहते हैं, हम उन को किस हालत में रखते हैं? न उन के लिए खाना होता है और न पानी । वे पिंजरों में बन्द पड़े रहते हैं । लोग उनको टौज करते हैं और वे चिल्लाते हैं । उन में से आधे तो मर जाते हैं । लेकिन किसी जैनी का हृदय द्रवित नहीं होता है, किसी की इन्सानियत पुकार नहीं करती है ।

यही बात मैं गाय के लिए कहना चाहती हूं । हमारे यहां गाय मुसलमान भी पालता है और हिन्दू भी पालता है । मैं मुसलमानों की बात नहीं करती हूं । जब हम लोग गाय को पालते हैं, जो गाय को पूज्य समझते हैं, जो गाय को मां कहते हैं, तो हम उस की क्या सेवा करते हैं ? जितना दूध वह देती है, उस को हम पी लेते हैं और उस को कुछ खिला देते है, या ज्यादातर वह सड़कों पर घूम कर अपना पेट भर लेती है । जब वह गाय दूध देना बन्द कर देती है, तो देहात के लोग उस को कहीं चरने के लिए भेज देते हैं और शहर के लोग उस को बेच देते हैं ।

मैं चाहती हूं कि सरकार गोवध को भी रोके, बकरे के बध को भी रोके और चिड़िया और बन्दर के वध को भी रोके । मैं तो सब जानवरों के वध को रोकने के पक्ष में हूं । आज सिर्फ यही काफी नहीं है कि सरकार यह कानून बना दे कि गाय नहीं मारी जायेगी सरकार को यह कानून बनाना चाहिये कि जो आदमी गाय को पालेगा, वह जब दूध नहीं देगी, तो भी वह उस को घर में रख कर उस की परवरिश करेगा । जब हम गाय को छोड़ देते हैं, तो वह किसी लालाजी की दुकान पर मुंह डालती है या किसी किसान के खेत में घुस जाती है और वह चाहे कितना ही बड़ा तिलकधारी हो, वह लाठी ले कर उस को मारने दौड़ता है ।

जो साधू गौ-रक्षा के नाम पर जलूस निकालते हैं, मैं रोज देखती हूं कि उन के हाथ और पैर भी हैं और वे बोलना भी जानते हैं और गाली देना भी जानते हैं । लेकिन गाय न कारखाना खोल सकती है, न नौकरी कर सकती है, न प्रार्थना कर सकती है, न भीख मांग सकती है । गाय तो तभी जिन्दा रहेगी, जब आप और हम उस को खिलायेगें । वह कोई काम नहीं कर सकती अगर उस को पालने वाला उस को खिलायेगा नहीं, तो वह कहां से खायेगी ? या उस को सरकार खिलाये और या पालने वाला खिलाये ।

अगर सरकार यह कानून बना दे कि जिस की गाय दूध देना बन्द कर देगी, वह उस गाय को भी रखेगा और दूध के लिए दूसरी गाय पालेगा, जब वह दूसरी गाय भी दूध देना बन्द कर देगी, तो वह उस को भी रखेगा और दूध के लिए तीसरी गाय भी पालेगा और इसी तरह तीसरी गाय का दूध सूखने पर दूध के लिए चौथी गाय भी पालेगा, तो हिन्दुस्तान की जनता कहेगी कि यह सरकार बेवकूफ है । वह कहेगी कि हमारे बच्चों को तो दो वक्त खाना नहीं मिलता है, वे बिना इलाज मर जाते हैं, हमारे लोग फुटपाथ पर सर्दी से सिकुड़ कर मर जाते हैं, लेकिन यह सरकार कहती है कि गाय दूध दे या न दे ,उस को घर में रख कर पालो । हिन्दुस्तान की सरकार को भी सोचना चाहिये कि आज हिन्दुस्तान में करोड़ों लोग बिना अनाज, बिना पानी और बिना इलाज के मर जाते हैं ।

मैं गौ-रक्षा का नारा लगाने वालों से भी यह अपील करना चाहती हूं कि हिन्दुस्तान में लाखों साधुओं को खिलाने के बजाय, जो खेती कर सकते हैं, जो नौकरी कर सकते हैं जो हाथ-पैर चला सकते हैं, जो मजदूरी कर सकते है, जो डैम बना सकते हैं, और तालाब और कुएं खोद सकते हैं, वे लाखों रुपये उड़ीसा की उन हजारों गायों के चारे पर खर्च किये जायें, जो वहां बिना चारे के भूख से मरने वाली हैं । मैं अपोजिशन से बहुत अदब के साथ अर्ज करना चाहती हूं कि जो

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

लाखों और करोड़ों रुपये आज इस काम पर लगाए जा रहे हैं, अगर वे गौशाला वगैरह खोल कर गौ-रक्षा के लिए खर्च किये जाये तो फिर कौन गौ-हत्या करने के लिये जायेगा। लेकिन अगर गौ-रक्षा का नारा लगाने वाले हिन्दुस्तान के सरमायदार और धनी आदमी गौ-रक्षा करने के लिए गोशाला नहीं खोलते हैं और उस के बजाये सिर्फ एक कानून बना कर रख दिया जाता है, तो मुझे खतरा यह दिखाई देता है कि गाय को वह मारने लगेगा, जो आज गाय को माता कहता है, जो उस की पूजा करता है। हम इन बातों को बहुत अच्छी तरह से सोचें।

हमारे यहां विद्यार्थियों का एजीटेशन चल रहा है। एक दिन श्री बागड़ी बोले, "स्पीकर साहब, चूंकि आप के लड़के पर गोली नहीं चली, इस लिए आप इस सवाल को नहीं उठाने देते।" कल श्रीमती रेणु चक्रवर्ती बोली, "चूंकि आपके लड़के वहां पर मौजूद नहीं थे, इस लिए आप को एहसास नहीं हैं।" मुझे भी यही शिकायत है कि अगर आपोजिशन वालों के लड़के उस में होते, तो वह लड़कों से पूछते। जब हम आज अपोजिशन वालों से पूछते हैं, इनकी क्या मांगें हैं, कहते हैं कुछ पता नहीं। जब हम कहते हैं कि इनको कौन भेज रहा है तो सोशलिस्ट पार्टी, कम्यूनिस्ट पार्टी, जन-संघ पार्टी, स्वतंत्र पार्टी तमाम पार्टीज कहती हैं इनके पीछे हम नहीं हैं। अगर यह उन के पीछे नहीं हैं, अगर कांग्रेस उन के पीछे नहीं है, अगर इन अपोजिशन पार्टीज को पता नहीं कि इन बच्चों के पीछे कौन है तो इनको आवाज उठानी चाहिए कि हिन्दुस्तान के बच्चे, तुम्हारे साथ हम नहीं, तुम्हारे साथ यह जमातें नहीं, तुम्हारे साथ कांग्रेस नहीं, जो तुमको ले जाने वाले है उन को कोई जानता नहीं, तुम जो कर रहे हो उसके साथ कोई नहीं। कौन तुमको यह करने के लिए तैयार करता है? पूछना चाहिए था, रोकना चाहिए था, संभालना चाहिए था। सिर्फ शिकायतें दूर करने की बात नहीं है। कोई उनको रोकता नहीं है। किस्सा इस बात का है कि जो मरने वाले मर गए, उसकी कब्र और चिता से फायदा उठा कर हम लोग वोट लें। मैं इसलिए कहती हूं कि कम्यूनिस्ट पार्टी ने कहा कि हम उसके साथ नहीं हैं और यह मैं जानती हूं उपाध्यक्ष महोदय, दूर की बात नहीं करना चाहती, दिल्ली की बात मैं जानती हूं, कम्यूनिस्ट पार्टी का उसमें हाथ नहीं है। किसका हाथ है? हम अन्दाजा लगा सकते हैं पर मैं यह जानती हूं कि उन का हाथ नहीं है।

**एक माननीय सदस्य** : और जगहों पर तो उनका हाथ।

**श्रीमती सुभद्रा जोशी** : यह कहते हैं कि नहीं है। जब इन का हाथ नहीं है तो बसों को जलाना, रेलों का उखाड़ना, सामान को लूटना, यह कौन सा कायदा है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जिक्र करना चाहती उस सम्पति का जिसका सर्वनाश होता है। जब मैं बलरामपुर जाती हूं तो लोग कहते हैं कि यहां अस्पताल खोल दो, हमारी औरतों को पचास-पचास और सौ सौ मील जाना पड़ता है। अस्पताल नहीं, सड़क नहीं, स्कूल नहीं। एक-एक सड़क, एक-एक अस्पताल, एक एक स्कूल के लिए मांग की जाती है, उन की तरफ तवज्जह नहीं और जो सड़कों पर मार्च करके सम्पति का नाश करते हैं, उनकी अवाज उठाई गई। और फिर किसकी आवाज उठायी जाती है? मैं कम्यूनिस्ट पार्टी से पूछना चाहती हूं कि बसों के कन्डक्टर मजदूर नहीं हैं, जो बसें चलाते हैं, वह मजदूर नहीं हैं, जो पुलिस के कर्मचारी हैं वह मजदूर नहीं हैं? पुलिस का यूनियन बने तो उसकी आवाज उठायी जायेगी और जिस वक्त पुलिस वालों को पत्थर मारे जायगे तो उनकी आवाज नहीं

उठायी जायेगी। क्या वह गरीब नहीं हैं ? क्या उन के बच्चे नहीं हैं ? क्या हमेशा वही कसूर पर होते हैं। यह किसी ने श्रवाज उठायी ? एक तरफ मजदूरों की हमदर्दी दिखाते हैं और एक तरफ एक मजदूर वर्ग पर दूसरे मजदूर वर्ग से हमला करवाते हैं। मुझे यह देखकर इस बात का रंज है कि इन चीजों का क्यों इन को ख्याल नहीं आता ? और फिर क्या कहते हैं कि हम लोग हट जायें, हम लोग स्वयं हट जायें और यह लोग हमारी जगह आ जायें।

आखिर में मैं एक चीज सरकार से निवेदन करना चाहती हूं। मैं ने कुछ एनार्की का जिक्र किया, ट्यूबवेल्स का जिक्र किया, सूखे का जिक्र किया, विद्यार्थियों की मांगों का जिक्र किया। आज दिल्ली की बात हमारे आप के सामने है। दिल्ली के इंजीनियरिंग कालेज की बात, ला कालेज की बात, सरकार ने बहुत तहकीकात की तो मालूम हुआ कि मांगें सही हैं। मैं सरकार से यह पूछना चाहती हूं कि यह मांग साल भर पहले क्यो नहीं पूरी की ? मैं अदब से निवेदन करना चाहती हूं कि आप लड़कों पर गोली चला लीजिए, लाठी चला लीजिए, जो भी करना चाहें कर लीजिए, पर मैं आप से निवेदन करूंगी कि उन अफसरों को, उन सेक्रेटरीज को, अंडर सेक्रेटरीज को, उन को जिन्होंने उनकी बातों को सामने आने नहीं दिया और समय पर उन को पूरा नहीं किया उन को पहले डिसमिस करना चाहिए, उनके खिलाफ ऐक्शन लेना चाहिए।

एक बात का, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत जिक्र हुआ स्टील प्लांट का। मैं प्रधान मंत्री से बिलकुल ऐग्री करती हूं, किसी प्रेशर के अंडर हम को कुछ नहीं करना चाहिए। पर मैं बहुत अदब से अर्ज करना चाहती हूं कि आप वहां स्टील प्लांट लगायें चाहे न लगायें और चाहे गोली चलायें न चाहे चलायें पर अगर कोई चीफ मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर या कोई एक्समिनिस्टर का जरा भी इशारा या हाथ इसमें है तो पहले उसको हटाना चाहिए और कार्यवाही बाद में करनी चाहिए।

**Shri Humayun Kabir** (Basirhat): Mr. Deputy-Speaker, it is with sadness and after a great deal of hesitation that I have decided to speak on this no-confidence motion this afternoon.

It is not easy for me to speak against the Government when I have been a member of the Congress Party for many years and have also shared in the responsibilities of office. I also admit that the policies which have led the country to its present pass are policies in framing some of which I also had a share. Nevertheless, I feel it necessary to speak because the pass to which the country has been brought is one where everyone must offer his analysis, try to find out why the present situation has been reached and chalk out remedial measures.

My hon. friend who spoke just now deserves, I think, the congratulations of the House because she has put many things with a force and vividness which everyone will admire. But probably she did not realise that in a sense her speech was itself one of the strongest condemnations of the Government and one that any member of the Opposition could emulate. She spoke of utter lack of law and order. She referred to Balrampur, how people go about flouting authority, how people go about creating a reign of terror. That is precisely the situation we are facing today. I am speaking today because the country, after 19 years of freedom and 15 years of planning, has reached a stage when in almost every sphere, on every front, we have reached almost the nadir of our fortunes.

I shall refer first to the food problem. I will not go into details because in the last session when there was a food debate, I placed my views at some length before the House and made

[Shri Humayun Kabir]

certain suggestions. But I cannot help saying that it is a very sad commentary on our planning and a sad reflection on the Central Government itself as well as the State Governments that after 15 years of planning and centralised control, which seeks to control almost every aspect of national life, millions are even today denied food and drinking water, their essential needs are not met.

We have also a situation where our dependence on imports from abroad for the very sustenance of our life is increasing from year to year. If I remember aright, during the First Five Year Plan, the average import per year varied between 1 and 2 million tons of grain. The situation today after the Third Five Year Plan is that we have had in the last few years to import 5, 6, 7 and 8 million tons, and today the prospect, the threat, is that unless we are given about 10 million tons for the coming year, millions of people may face starvation and death.

This is certainly a sad state of affairs and this in itself entitles people to question whether the policies which have been followed till now have been on correct lines. I think there should be a searching of heart, and unless there is a searching of heart, we cannot get out of the difficulties into which we have brought this country today.

I will give only one example of the way in which the problem of food has been bungled. I do not blame the present Food Minister. He alone is not responsible but he also has some share in it. Even before, for the last 15 years, we have not been able to settle even the figure of agricultural production in this country.

**16 hrs.**

[SHRI SHAM LAL SARAF *in the Chair*]

The agricultural statistics are completely unreliable. According to the National Sample Survey there is one figure of the total production of foodgrains in the country; according to the figures collected by the Food and Agriculture Ministry there is a completely different figure. Sometimes the difference between the two has been as much as 50 per cent, but the normal variation has been 20 per cent. Today we know that the figures which were given by the National Sample Survey in 1950 were much nearer the mark than the figures collected by the Food and Agriculture Ministry. If the figures of the National Sample Survey were correct, the deficits which have been thrown at us again and again would have proved illusory in many cases. I really do not know how to explain the situation.

I would give you the example of my own State of West Bengal. In the last few months we were told again and again that there is acute shortage of foodgrains. All kinds of cordons were introduced, levies were introduced. People could not take food from one village to another. You know that wherever there is a checkpost, there is a door open to corruption, and the whole of Bengal, the economic life of Bengal, was corrupted because of this multiplication of checkposts and cordons which separated district from district, police station from police station, even village from village, and we were told there were no foodgrains. A few weeks ago these cordons have been removed, the checkposts have been abolished, and immediately there is adequate supply of foodgrains in the State and prices have come down. This should have been a difficult period because the new harvest has not come in; it will be coming in very soon but it has not come in yet. The fact that as soon as the cordons and the checkposts were removed there was a general fall of prices suggests that there was something very wrong indeed in the food policy which was pursued. I have referred to the agricultural statistics. If our agricultural statistics had been accurate, if we could depend upon

them, we might have avoided the shame and the disaster of devaluation which today threatens to overwhelm the entire country. This is one front on which the failure of the Government has not brought the country into a sorry pass.

I next turn to the problem of security. I am not referring to external dangers. We know that we have unfriendly neighbours, neighbours who are hostile and who will threaten our integrity whenever they get an opportunity, but I am more concerned with the situation inside the country. Law and order has almost vanished from large areas of the country. If you can get in the city of Delhi itself incidents like the one which was reported a few days ago, that from a house when husband and wife were together sitting in their home, the wife, was carried away, if an incident like that can happen in the city of Delhi itself you can imagine to what straits this country has been brought. I know my hon. friend the Home Minister is an extremely earnest and honest person and he has done his best. I also remember that on one occasion he said that he had doubled the police......

**The Minister of Home Affairs (Shri Nanda):** May I interrupt him and just say that in this case the kidnapping culprits have been caught and are being dealt with?

**Shri Humayun Kabir:** It is some consolation to know that the culprits have been arrested, but far more serious is the fact that an incident like this could take place in the capital city of India.

My hon. friend said the other day in another place that he was taking strong measures and the police froce was being doubled. It has been doubled; actually I think it has been quadrupled since the beginning of independence, but that is not a support for the Government, that is not in praise of the Government; it is, in fact, a condemnation of the Government. If the police force has to be continually increased, and I hope my hon. friend Mr. Mathur will not take me amiss if I refer to a remark of his when he heard that the police had been doubed,—his immediate retort was that doubling the police was not perhaps enough; perhaps we must have one policeman for every citizen and then and then alone security would return to this country—if that is the kind of mentality which the Government has even today that we can maintain law and order only by continually increasing the police force, I think the Government are going on a wrong line. No Government in the world, however strong it may be, even if it be a naked dictatorship, can survive for long unless it rules by authority, by prestige; it is not by repression that any Government can continue in power for very long, and the expansion of the police force is a symbol of using repression, of using naked power, whereas Government must, in fact use the instrument of prestige, the instrument of authority.

In a country like ours where we have had throughout an authoritarian society we have a structure of society where power has been maintained mainly on account of two elements, partly fear because of the exercise of power and partly respect. Respect because persons exercising the power had a moral authority to give the necessary lead to the people of the country. Unfortunately today it seems that both these are disappearing. Fear has largely disappeared. For that I am not sorry; it is good that in an independent country fear shall not be a major force in maintaining law and order. But simultaneously respect for authority has disappeared. That is where I think the gravest danger to the country lies.

These incidents of breakdown of law and order have affected our national life at many points. There have been many complaints from minorities—linguistic, religious and others. In many cases there have been incidents of lawlessness where unruly elements in

[Shri Humayun Kabir]

the community have taken the law into their hands and the Government has not been able to tackle them. We have today this gigantic phenomenon of what is called the student disorder and it is also called youth unrest. It is true that there is this world phenomenon; youth are revolting against conventional standards of society. Many of the old ideas have been discarded by them but new ideals have not been built up to replace them. It is a phenomenon which exists all over the world. But this state of affairs has a special risk in a country like India precisely because of the reason I mentioned earlier. Ours has for centuries been an authoritarian society. In other societies even if this revolt of the youth takes place, there are agencies in society to interfere and act as checks to a certain extent; in many of the western democratic societies there are certain inbuilt resistances and safeguards which prevent society from going to utter ruin. In a society like ours if the respect and fear for authority—I should say respect more than fear—is once shaken we are faced with a serious crisis.

I think it is here that the Government should search their hearts. Why is it that there is this kind of lawlessness everywhere in India today? What ever be the cause, at the slightest provocation there is a kind of outburst which is completely out of all proportion to the original cause due to which the incident or trouble started. There seems to be no correspondence at all between cause and effect. There is a general sense of unrest, general sense of disturbance, general sense of malaise. You talk to any one in any part of the country; no one seems to be happy. The other day a friend of mine who is a Congress Chief Minister in a State approached a certain businessman for election funds. That businessman himself told me this story. He said: Sir, since you have asked for some funds, I will certainly give you, but I will ask you only one question. In any country, wherever there is a Government, they have some supporters; in some cases it is the rich class which supports the Government; in other cases it is probably the middle-class which give their unstinted support to the Government; in yet other cases, it is the poor who stand behind the Government and give it sustenance and support; why is it that in your case neither the rich nor the middle-class nor the poor are behind you; why it is that even though you exercise such power you cannot face a public meeting now though in the past you have been one of the most popular men in the State? Of course there was no answer; there could be no answer to this question. This is where I think the highest leadership in the country inside the Congress and in the Government have to ask themselves the question: why is there the breakdown of authority? why is it that there is no moral prestige in Government? I think the answer will be: because there has been a fall from standards. There has been condonation of corruption on a scale which is almost unprecedented in the history of this country.

**Shri C. K. Bhattacharyya** (Raiganj): What business took the hon. ex-Minister to this so-called businessman?

**Shri Humayun Kabir:** My hon. friend should have known that I have contacts with all kinds of people; I have contact with the students, with the teachers, with the businessmen. I am not one of those persons who think that businessmen are untouchables. I know my hon. friend will probably go to them but pretend that they are untouchables. If he has any friends amongs them, it is far better to acknowledge them rather than hide that fact. In any case, it is a fact, and if my hon. friend does not know that man in public life would continue to meet all kinds of persons, then I can only say that probably he is not a public man and his public life consists only in getting a ticket somehow and

getting returned to the House and coming here to Parliament.

**Shri C. K. Bhattacharyya** *rose*—(*Interruption*).

**Shri Humayun Kabir:** I am not yielding.

**Mr. Chairman:** Order, order. He is not yielding.

**Shri C. K. Bhattacharyya:** I do not want him to yield, Sir, but this is a cock and bull story.

**Shri Humayun Kabir:** The major reason for our malaise is this; there has been a loss of prestige and moral authority because there has been a condonation of corruption at the highest level. In this very House itself, we have seen that persons whom some of the highest in the land have regarded as not fit to hold responsible positions, have yet been maintained in the highest positions of authority. In this very House, we have seen that people who have been condemned, about whom it has been suggested that they should not again occupy positions of power and prestige, have been brought back by the backdoor. Those who have been shown the front gate and asked to go out have come back through the backdoor and they are still in positions of authority. How can we expect the people of this country to have any respect for Government, for the highest leadership, when corruption is not stamped out, when we know that in almost every sphere of Government corruption is not only tolerated but in some cases even encouraged? We talk of high standards and this is the example we set before the people. We talk of austerity and yet the ostentation in which some of the persons who have no ostensible means of living, live in luxury, princely luxury, is well known. The people of the country are not blind; they see it every day and have asked questions, what is the source of income of these people who are living in this luxury? How can you think that the moral standards of the country will be improved when persons like that are in positions of authority in the Government and also in the organisation?

Sir, we talk of student indiscipline. This is a problem to which I have given very anxious thought, not today but for quite a number of years, and I have tried to analyse it as carefully as I could. Ultimately, it boils down to want of leadership. If the older generation does not command the respect of the younger generation, how can we expect the yonger generation to behave properly? You must also remember that the younger people suffer from two drawbacks. They are emotionally unstable. During the period of adolescence, when they have any provocation they get excited. This is one of the marks of adolescence and we cannot fight against that nature. We will also have to remember that they are intellectually immature. When intellectual immaturity and emotional instability feed upon the kind of situation which we see all around, when we see the low standards gradually leading to standards being further lowered all around, is it surprising that many of them should get out of hand and commit all kinds of things of which every honest citizen should feel ashamed and be sorry and grieve?

I agree with my hon. friend who spoke just now that we have to be sympathetic to the students, but, at the same time, we have also to see that wherever law and order is violated, law and order must be maintained. The sanctity of society must be maintained and if you allow this very basic condition of society to be undermined, it would be very, very difficult indeed to restore the situation and bring back the social situation to normality in the country.

There are two other points on which I would like to make some brief comments. I have spoken about devaluation many times. I am amazed at the carelessness, at the almost callous and curious indifference with which this plunge into devaluation was taken. I

[Shri Humayun Kabir]

was in Europe at that time. I have visited Europe many times. Even this year I was in Europe twice; never have I felt so ashamed, never have I felt so humiliated as I felt in Europe during the month of June, immediately after devaluation. Wherever I went, there was a kind of contempt and pity for India. There was a great deal of sympathy also and we are grateful to those who show sympathy for India. But, at the same time, there was an attitude of condescension even from those who have the least right to express their condescension for us.

Why did we devalue? Even today Government has not been able to give one single satisfactory reason as to why we devalued. We were told at one stage that devaluation was due to the pressure of the World Bank. This morning the Finance Minister said that the advice was there but we did not do it because of the World Bank, we did it on our own. That, in a sense, makes the situation even worse. The World Bank has, of course, advised devaluation to many countries. The World Bank has at one stage advised even the United States of America to devalue. It is advising the United Kingdom to devalue almost every year; there is in fact a constant pressure. The World Bank advised Pakistan, Ceylon and Nepal, countries in our neighbourhood, to devalue. None of these countries listened to that advice and yet the assistance that the World Bank gives to them continues. We have to remember that the World Bank, even during the days of Indo-Pakistan war, did not stop their aid. It was perhaps the only international agency which continued to give help to us. Therefore, it is not due to the pressure of the World Bank and I am glad the Finance Minister has absolved the World Bank of that responsibility.

Why then did we devalue? We were once given the reason that we devalued because at one time England had devalued, France had devalued, Italy had devalued and Germany had devalued. There was not the slightest notice of the entirely different situation in these countries. All these countries have a very developed economy, have tremendous productive power and are producing goods and services of every type. They could not sell them in the world market because the prices were high. The moment they devalued and brought down the prices the sale of their goods went up and their exports went up. We are not in that happy situation. We are not producing finished goods. We are exporting mainly five or six fundamental articles, basic materials like jute, tea, hides and skin, iron ore, a few textiles, some engineering goods, groundnut oil and things like that for which the demand is not elastic. They have a comparatively inelastic demand. With this inelastic demand, devaluation has not helped us at all. What has actually happened is, there has been no increase in our exports. Our export earnings have not really increased in any substantial manner in the last five or six years. I have studied the figures. From 1961 to 1966 there is an increase of about Rs. 100 crores or so. We also overlook the fact that Goa came to India after 1962 and Goa brought exports worth about Rs. 100 crores. Therefore, there has been no sizeable increase in the export trade. In fact, many exporters are complaining today that as a result of devaluation they have been so hard hit that the exports of India will go down.

On the other hand, the value of imports has gone up. I was amazed this morning when a friend from this side asked the Finance Minister what is the increase in the indebtedness of India as a result of devaluation and he said that he did not know. I cannot imagine a more callous and a more surprising answer from a Finance Minister. It is the Finance Minister's business to know what is the increase in the national debt on account of devaluation. His only reply was that he will have to look up the

figures. These things should be at his finger tips. This is the way in which the whole thing has been treated in a completely callous, if I may say so, heartless way, playing with the fortunes and lives of millions of people in this country.

The prices are going up. Devaluation will make prices go up. For people to say that there will be devaluation but no increase in prices suggests that they probably do not know the meaning of the word "devaluation". The meaning of the word "devaluation" is that the money value has gone down. If the money value has gone down it follows as a corollary that the prices of articles must go up. Even then necessary corrective measures were not taken. The result is that today our economy is in a stage of almost near collapse. This is all due to the light-hearted and casual manner in which a major decision like devaluation was taken.

Sir, if I had the time I would have spent a little more time on the question of planning. But before I do so I would like to mention one other major problem where also the Government has failed. I am not speaking about Calcutta because I come from the eastern part of India, I am speaking of Calcutta because it is India's major port and the economic life of almost one-third of India depends on the prosperity of Calcutta port. Calcutta city is literally dying before our eyes. We want improvement in transport and communications, we want improvement in drinking water and drainage, we want improvement in housing and slum clearance. We want Calcutta to be a living, vital city so that it can serve the whole of eastern India, and if there is any case for special assistance from the Centre for the rehabilitation of a city, it is Calcutta. It was, therefore, a shock to me to learn that the present Government has refused to give additional help to the State Government, even so far as the second bridge over the Hooghly is concerned, by saying that the funds have to be found by the State Government, knowing fully well that the State Government have not got enough resources for it. I do not today refer to the other projects in the eastern part of India which have been slowed down for want of funds.

I will conclude by saying—so far as planning is concerned, I hope I will have an opportunity of speaking at greater lengthy when planning is taken up later in the session—that it is wrong planning and fascination for centralisation and giganticism, the fatal lure for building up units without proper planning, which has brought us to the present pass. We have five steel mills in the country. We are going to build the sixth, the great Bokaro plant. But there also I would ask the Government to once again examine the whole question and to see whether it is more economical to add 5 million tons of steel production to the country at a cost of Rs. 500 crores, or to build a new plant at a cost of almost Rs. 1,000 crores and produce only 2 million tons. It is simple economics, it is commonsense that in our present stage of economic development we should make every rupee go as far as possible.

It is this lure for giganticism, the lure for centralisation, trying to control everything from one centre that has led to many of these ills, and that is why, finally, before I conclude, I would like to say that the time has come when the people should have the chance of trying another Government. I know it will not happen today, but it is likely to happen at least in some States after the next general elections. I am almost positive about two or three States but already there is a lurking fear. Those who are the supporters of the Government are already going about and saying if non-Congress Governments come into power, there will be President's Rule, if non-Congress parties form the majority, some device would be found by which the Constitution will be defeated. This kind of propaganda is going on and weakening peoples' faith in constitutional methods. I think it would be

[Shri Humayun Kabir]

right and proper for the Central leadership—I would confess that even today I have a little more faith in the Central leadership than the leadership in the States—it is for the Central leadership to say that this kind of rumours are unfounded and wherever any party gets a majority it would be allowed to function properly, according to the Constitution, so long as it follows a constitutional way.

**श्री यशपाल सिंह** : ऐसी बात नहीं है कि इनमें कुछ ज्ञान की कमी है या ये लोग कुछ पढ़े लिखे कम हैं या इनका नालिज कम है। लेकिन गीता माता की आज्ञा है विधि निषिद्ध कर्म, करने वाले को मार डालता है। इन्होंने पिछले उन्नीस साल में जो कुछ किया है, उसका नतीजा पराजय हुआ है, जितनी भी एफर्ट्स इन्होंने की हैं, जितने भी डिवेलेपमेंट के कार्य किए हैं उन सब का नतीजा डिफीट हुआ है, शिकस्त हुआ है। बात बहुत छोटी सी है। देश के अन्दर इन्होंने वह जागृति पैदा नहीं की जिस जागृति के मातहत देश का बच्चा बच्चा सैनिक बन जाता और अपने बॉर्डर्स की हिफाजत करता। जहां भी मैं जाता हूं इस इतने बड़े देश में वहां हर आदमी यही पूछता है कि चीन अब हमला तो नहीं करेगा, चीन अब आगे तो नहीं बढ़ेगा। यह जो डिफीटिज्म दिया हुआ है यह इनका दिया हुआ है। अगर देश के अन्दर विजय की भावना पैदा होती तो देश के लोग यह पूछते कि कौन सी तारीख को हम चीन के ऊपर हमला करेंगे। लेकिन यह देश को सिखाया नहीं गया। देश को आराम से सुलाया गया है, देश को बहकाया गया है। देश को कहा गया है कि अगर एक एटम बम गिर गया तो डेढ़ करोड़ आदमी मारे जायेंगे। जरूरत इस बात की थी कि देश को शिक्षा दी जाती संभावितस्य चाकीर्तिरणादतिरिच्यते। जिल्लत की जिन्दगी से मौत अच्छी है, अपमान के जीवन से मृत्यु बेहतर होती है। आज भी कोई ऐसी बात नहीं है कि हम इसका निराकरण न कर सकें। जो पराजय हुई हैं, वह विजय में परिणित न हो सके। थोड़ा सा आपको सुधार करने की जरूरत है। इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंड। सबसे पहले आप लोग यह सोचें कि देश के साथ जो अहित हुआ है वह सिर्फ इसलिए हुआ है कि देश के अन्दर विजय की भावना नहीं आई है, देश के अन्दर पराजय की भावना आई है। आप देखें कि जो अंग्रेज ने रूल बना रखा था बन्दूक आदि का लाइसेंस देने के बारे में वही रूल आज भी कायम है। जिस तरह से अंग्रेज रिवाल्वर के लाइसेंस, राइफल के लाइसेंस दिया करते थे उसी तरह से आज भी दिये जाते हैं। वही सिस्टम आज भी चल रहा है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि हरदोई के एक एम० एल० ए० की बन्दूक के लिए दरख्वास्त इसलिए नामंजूर कर दी गई कि उसकी दरख्वास्त की कलेक्टर साहब ने सिफारिश करने से इन्कार कर दिया। इस तरह से दरख्वास्तें बन्दूक के लाइसेंस के लिए खारिज कर दी जाएं तो क्या आप समझते हैं कि देश की रक्षा हो सकती है। यह अंग्रेजों का बनाया हुआ आर्म्स एक्ट है। इसको आप खत्म करें। हर एक बालिग को, हर एक ईमानदार आदमी को, हर एक सच्चरित्र आदमी को, हर एक बालिग लड़के और लड़की को हथियार रखने का हक होना चाहिये।

एक तरफ तो यह कहा जाता है कि देश की हम रक्षा करेंगे और दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि न्यूकलियर वैपन्ज़ हम नहीं बनायेंगे। ये दोनों मुतजाद चीजे हैं। देश की रक्षा आप कैसे करेंगे? एक तरफ तो ये यह कहते हैं कि बच्चे का विकास होगा, उसको नारिशमेंट मिलेगा और दूसरी तरफ कहते हैं कि उसको हम दूध नहीं पिलायेंगे। एटम बम आप नहीं बनाते हैं, हाइड्रोजन बम आप नहीं बनाते हैं तो सिवाय पिटने के और कोई चारा नहीं है। काफी पिट चुके हैं। थोड़ा सा हड्डियों में खून रह गया है वह भी निकल जाएगा। जो गलतियां की गई है उनका आज सुधार करें।

मैं नन्दा साहब से कहना चाहता हूं कि कुरप्शन का नारा वह न लगायें। यह नारा लगाना बेसूद है। नारा लगायें प्रोडक्शन का। भ्रष्टाचार का नारा न लगायें, पैदावार का नारा लगायें। अगर पैदावार नहीं होगी तो भ्रष्टाचार जरूर होगा। मां नहीं चाहती है कि बच्चे के दूध में पानी मिलाया जाए, उसको पानी मिला हुआ दूध दिया जाए। लेकिन घर में अगर आठ बच्चे हैं और गाय पाव भर दूध देती है तो मां को जबरदस्ती, मां को मजबूरन दूध में पानी डालना पड़ेगा, मजबूरन एडलट्रेशन करना पड़ेगा। अगर पैदावार नहीं बढ़ेगी तो जरूर भ्रष्टाचार होकर रहेगा। अगर बार बार आप कुरप्शन का नारा लगायेंगे तो कुरप्शन होकर रहेगा। सिंक आफ दी डेविल एंड देअर ही इज। यह कुरप्शन आपके सिर पर सवार रहेगी। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि एक करोड़ इंसान भी देश में मेहनत नहीं करते हैं। मैं नागपुर गया था। चारों तरफ मैंने घूम कर देखा। दो दिन और दो रात मैंने वहां गुजारे। न वहां लोग हल चला रहे थे, न किताब पढ़ रहे थे, न ट्रैक्टर चला रहे थे, न फावड़ा चला रहे थे, न वहां स्कूल चल रहे थे। डेढ़ डेढ़ महीने से स्कूल बन्द पड़े हैं। इसलिए बन्द पड़े हैं कि स्टूडेंट्स में अनरेस्ट है। विद्यार्थी अनुशासनहीनता करते हैं। जो शिक्षा आप दे रहे हैं, उसके रहते अनुशासनहीनता नहीं बढ़ेगी तो और क्या होगा? उनको कोई मारेल एजुकेशन, उनको कोई रिलिजस एजुकेशन, उनको कोई दीनियात की तालीम, उनको कोई इखलाकी तालीम नहीं दी जाती है। अगर यह शिक्षा दी गई होती तो उनके अन्दर अनुशासनहीनता न आती। लेकिन जो शिक्षा आप दे रहे हैं, उसके रहते आप कभी भी देश का कल्याण नहीं कर सकते हैं। जरूरत इस बात की थी कि देश में शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता, उसका नेशनलाइजेशन कर दिया जाता। अगर ऐसा हो गया होता तो आज यह हालत न होती। आज यह नौबत न आती कि विद्यार्थियों पर आप गोली चलाते।

विद्यार्थियों पर गोलियां क्यों चलाई जाती हैं? इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि इनएफिशेंट लोग पुलिस इत्यादि में भरती कर लिए गए हैं। एस० पी० और डी० एस० पी० वगैरह जो अंग्रेजों के जमाने में भरती किए जाते थे उनकी छातियां चौड़ी होती थीं उनकी भुजायें लम्बी होती थीं, उनकी आवाज में शेर जैसी गरज होती थी। आज की तरह से भाई भतीजों को भरती नहीं कर लिया जाता था। आज तो मिनिस्टर्ज की सिफारिशों पर इनको भरती कर लिया जाता है। एक दो नारे लगे नहीं, मौत खड़ी हुई सामने दिखाई दी नहीं, इनका दिमाग काम करना बन्द कर देता है, एक दम कह देते हैं कि गोली चला दी जाए। निहत्थी जनता पर महात्मा गांधी के राज में, गांधी जी के फालोअर्ज द्वारा, मूक विद्यार्थियों पर, बेजुबान बच्चों पर गोली चलाना, इससे बड़ा और कोई पाप नहीं हो सकता है। देश की दो समस्यायों को आप हल कर लें तो तीसरी समस्या को हल करने की जरूरत नहीं है। एक एजुकेशन की समस्या को और एक पैदावार की समस्या को। पिछली बार भी इसी हाऊस में मैंने कहा था कि इस देश के अन्दर आज सरकारी आंकड़ों के अनुसार 60–65 करोड़ एकड़ जमीन ऐसी है जो कल्टीवेबल लैंड है। सरकार के पास सिर्फ ढाई करोड़ हल हैं और सिर्फ 45,000 के करीब ट्रैक्टर हैं जो वर्किंग कंडिशन में हैं। इनको लेकर चलें तो इस 65 करोड़ एकड़ जमीन की परिक्रमा भी आप नहीं कर सकते हैं। इस जमीन के चारों तरफ घूम भी नहीं सकते है। बैलों को काटते काटते देश का इन्होंने इतना नुकसान कर दिया है कि अब देश अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह सकता है। जिन बच्चों को डी० एम० एस० का दूध मिलता है क्या व बच्चे विकसित हो सकते हैं क्या उन में से पंडित मदन मोहन मालवीय, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी पैदा हो सकते हैं? पांच-पांच दिन का बासी दूध उनको पीने को मिलता है। इसमें मक्खियों का जहर होता है मेंढकों का

[श्री यशपाल सिंह]

रस होता है, मछलियों का अरक होता है। इसी सदन की टेबल पर ऐसा दूध रखा गया है जिसमें दो-दो इंच लम्बे कीड़े थे। क्या आप समझते हैं कि जिन बच्चों को वह दूध मिलता है उन में से कोई लोकमान्य तिलक या महात्मा गांधी पैदा होगा ? हरगिज नहीं हो सकता है। जिस गाय को हमारे धर्म-शास्त्र और वेद भगवान् मां कह कर पूजते हैं यक-कलम यह कानून बनाया जाय कि उस गौ-माता पर छुरी चलाना पाप है अपराध है। हिटलर ने एक दफ़ा कहा था कि बाइबल के एक सफ़े पर हजारों सल्तनतें कुर्बान की जा सकती हैं। इस देश की पचास करोड़ जनता जिस गौ को अपना पूज्य मानती है, सरकार उस पर गोली चलाती है और फिर सरकार कहती है कि देश में खुशहाली नहीं आती है। खुशहाली क्यों और कैसे आएगी, जब सरकार मां पर गोली चला रही है ?

जिसको वेद में मां कहा गया है, जिसका दूध पीकर दयानन्द और विवेकानन्द पैदा हुए, जिसके बारे में हदीस शरीफ़ में यह हुक्म हुआ है "लहमुहा दाउन व समनहुआ दवा उन व अलबनुहा शिफ़ाउन" यानी गाय का दूध गिजा है गाय का घी दवा है चिकित्सा है लेकिन उसका गोश्त सरासर बीमारी और रोग है उसकी हत्या को, कॉ स्लाटर को तो सरकार बन्द नहीं कर सकती है और फिर कहती है कि देश की तरक्की के दरवाजे बन्द हैं।

महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर आजादी एक तरफ हो और गौ दूसरी तरफ़, तो मैं पहले गौ की तरफ़ बढ़ूंगा, क्योंकि अगर गौ होगी तो आज़ादी फिर आ जायेगी, लेकिन अगर गौ नहीं होगी, तो आजादी नष्ट हो जायगी। श्री नन्दा की इस बात से मैं सहमत हूं कि चाहे हमें अरब, दो अरब रुपये का नुकसान उठाना पड़े, लेकिन हमें कॉ स्लाटर बन्द कर देना चाहिए। लेकिन वह सिर्फ़ कहते हैं, अमल नहीं करते हैं, प्रैक्टिकल काम करके नहीं दिखाते हैं। ये सिर्फ़ उनके विचार हैं और ख़ाली विचार कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर देश को बचाना है तो देश के दो मसलों को हल किया जाना चाहिए, एक खाद्य समस्या और दूसरी एजूकेशन की समस्या। आज से बीस साल पहले मैंने यह नारा लगाया था कि अगर शिक्षा में दीनियात की तालीम शामिल नहीं हुई, धर्म-शिक्षा शामिल नहीं हुई, तो यह खुद मर जायेगी। "तुम्हारी तहज़ीब अपने खंजर से आप ही खुदकशी करेगी, जो शाखे नाजुक पै आशियाना बनेगा नापायदार होगा"। जिस अंग्रेजी तालीम और जुबान से हमको दो सौ साल तक गुलाम रखा गया, जिससे हमारी लक्ष्मी, हमारी शोभा, हमारी सम्पत्ति और हमारी आजादी का अपहरण हुआ, वही अंग्रेजी तालीम और अंग्रेजी जुबान आज भी सरकार के लोगों पर लदी हुई है। वे आज भी उसी की गुलामी कर रहे हैं।

जिस देश ने अपने धर्म, स्वत्वों और अधिकारों की रक्षा की, उसने तुरन्त अपनी जुबान में काम करना शरू कर दिया। बर्मा जिस दिन आजाद हुआ, उसी दिन से उसने बर्मी जुबान में अपना सारा काम-काज करना शरू कर दिया। श्रीलंका ने भी आजाद होते ही फौरन सिंहली जुबान में काम करना शरू कर दिया। जिस दिन इसराइल स्टेट वजूद में आई, उसी दिन उस ने हेब्रू में काम करना शरू कर दिया, जो कि दो हजार साल पहले यहूदियों की जुबान थी। इन देशों की तुलना में एक हमारा देश है, जहां उन्नीस साल के बाद भी इस पार्लियामेंट में एक भी बिल हिन्दी में पेश नहीं किया जा सका, सुप्रीम कोर्ट का एक भी फ़ैसला हिन्दी में नहीं लिखा जा सका। यह आजादी किस तरह जिन्दा रहेगी ? यह आजादी अंधेरे में आई थी जिसकी वजह से आज भी देश में अंधेरा छाया हुआ है। यह योजना अंग्रेजी में आई थी, इसलिए देश को इससे कोई लाभ नहीं पहुंच सका।

आज दूसरे देशों में क्या हो रहा है ? चीन में अंग्रेजी को कितनी हिकारत की निगाह से देखा जाता है । रूस के एक भी बेटे-बेटी ने अंग्रेजी नहीं पढ़ी, लेकिन उन लोगों ने स्पूटनिक बना कर चांद के साथ सांठ-गांठ शुरू कर दी । हमारे इन लोगों को अंग्रेजी नहीं आई, लेकिन उसके पीछे ये अपना ईमान बेच बैठे हैं । इस पार्लियामेंट में नब्बे फ़ीसदी लोग ग़लत अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी बोल कर शान गांठी जाती है, अपना पांडित्य उछाला जाता है, समझा जाता है कि हम बहुत बड़े माने जायेंगे । मैं नफ़रत करता हूं । मैं मानता हूं कि अंग्रेजी का पांडित्य होना चाहिए, लेकिन जहां बाप-बेटे, एम० पीज० और मिनिस्टर अपनी भाषा को छोड़ कर एक दूसरे को अंग्रेजी में ख़त लिखते हैं, वहां का धर्म, संस्कृति और देशभक्ति जिन्दा नहीं रह सकते हैं । देशभक्ति सब से पहले अपनी मातृभाषा से प्रेम सिखाती है ।

यह सब बातों को जानते हैं, हर एक बात को समझते हैं, इनका ज्ञान अथाह है, इन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है, लेकिन गीता माता में लिखा है कि विधि-निषिद्ध किया हुआ काम कर्ता को मार डालता है । यह जो कुछ जानते हैं, उसको अमल में नहीं लाना चाहते और अमल के बिना तालीम बिल्कुल बेकार है, कर्म के बिना विद्या बिल्कुल निरर्थक है । जैसे गधे के सिर पर कुरान रखते हैं, वही हालत हो जाती है ।

सरकार से मेरी ।वनती है कि अगर विद्यार्थियों के मसले को हल करना है, तो वह धर्म, दीनियात और इख़लाकियात की तालीम शुरू करे, जिससे कौमें बनती हैं, उठती हैं और तरक्की करती हैं, सूरज की तरह से चमकती हैं । आज हमारी हालत यह है कि हम दस दिन तक दावत खिलाते हैं, लेकिन हम काश्मीर और चीन के मुताल्लिक एक लफ़ज भी बयान में नहीं लिख सकते हैं, काश्मीर के मामले में एक की भी राय, अपने हक़ में नहीं ला सकते हैं ।

मैं सरकार से कहूंगा कि वह राय-आम्मा का ज़िक्र न करे । अगर सरकार चाहती, तो हमारी पचास करोड़ जनता हिमालय पहाड़ की तरह खड़ी हो जाती, लोहे की दीवार बन कर खड़ी हो जाती, गुरु गोविन्द सिंह की सेना खड़ी हो जाती, लेकिन उसने चाहा नहीं है । उसने डिफ़ीटिज्म, पराजय, नाचने-गाने, सिनेमा और कल्चरल प्रोग्राम्ज की शिक्षा दी है । जिस देश की लाखों मुरब्बा मील की ज़मीन पर दुश्मन का झंडा लहरा रहा है, उसके सिनेमा, शराबख़ाने, नाच-गाने और कल्चरल प्रोग्राम एक मिनट के लिए भी बन्द नहीं हुए । देश का क्या नुक्सान हो जाता, अगर एक साल के लिए भी सिनेमाघर और नाच-गाने बन्द कर दिये जाते ? जब से मैं पैदा हुआ हूं, आज तक मैंने सिनेमा नहीं देखा है, गाना नहीं सुना है, लेकिन क्या मेरे कल्चर में कोई कमी है, क्या मेरी ट्रेनिंग में कोई कमी है, क्या मेरे मेकिंग में कोई कमी है ? मुझे काम सौंप कर देखिये । मैं दस दिन तक बग़ैर खाये-पिये हुए काम कर सकता हूं, रात-दिन निराहार और निर्जल रह कर काम कर सकता हूं ।

जिस देश में बच्चों को डाल्डा और कोटोजम खाने को मिलता हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वह देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है । चूंकि आप पक्षपातरहित हैं, आप में कोई पक्षपात नहीं है, इसलिए मैं आप के सामने यह कहना चाहता हूं कि डाल्डा और कोटोजम एटम बम से भी ज्यादा ख़तरनाक है । एटम बम तो एक दफ़ा जला देता है, लेकिन डाल्डा और कोटोजम घुला-घुला कर, तिल-तिल कर ख़त्म करते हैं । अगर देश में कोई महापाप है, तो वह डाल्डा और कोटोजम है । सब से महापाप वनस्पति का है । महात्मा गांधी ने, जिनके हम अनुयायी हैं, जिन पर हम को अभिमान है, जिनके नाम पर मैं अपने प्राण निछावर कर सकता हूं, जिनके नाम पर कांग्रेस वोट मांगती है, उन्होंने एक दफ़ा नहीं, हजार दफा नवजीवन,

[श्री यशपाल सिंह]

यंग इंडिया और हरिजन में लिखा था कि जिस तरह जाली रुपया बनाने वालों को सजा दी जाती है, उसी तरह से जाली घी बनाने वालों को भी सजा दी जानी चाहिए। लेकिन डालडा और कोटोजम के कारखाने इन लोगों के मातहत चलते हैं और फिर भी वे समझते हैं कि हम महात्मा गांधी की शान को दोबाला कर रहे हैं।

आज जरूरत इस बात की है कि आमूल-चूल परिवर्तन किया जाये। जिस ग्लास में शराब भरी हुई है, उस में दूध नहीं भरा जा सकता है। पहले शराब से ग्लास को खाली करना होगा, तब उसमें दूध भरा जायेगा। जो कुछ इन लोगों ने सीखा है, उसका नतीजा पराजय हुआ। उनको पराजय की भावना को निकाल देना चाहिए। अगर हमारे देश के पचास करोड़ लोग संगठित हो जायें, आर्गनाइज्ड हो जायें, मिलिटेरिली ट्रेन्ड हो जायें, तो उनमें इतनी शक्ति है कि अगर वे पैर मार देंगे, तो जमीन हिल जायेगी, दुनिया उनसे अपनी हिफ़ाजत चाहेगी, ये दूसरों के दरवाजों पर दूध, गेहूं और हथियार मांगने नहीं जायेंगे। पचास करोड़ की यह नेशन आज संसार को शिक्षा दे सकती है। यह वह देश है, जिसके लिए हमारे धर्म-शास्त्र में लिखा हुआ है, "एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः। स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरेन् पृथिव्यां सर्वमानवाः"॥ दुनिया आ कर इस देश के चरण छूती थी, शिक्षा और दीक्षा लेती थी। आज यह देश पिटा हुआ, पराजित और परास्त है। इसमें आमूल-चूल परिवर्तन करना पड़ेगा और आज नन्दा साहब को यह कसम खानी पड़ेगी जैसा कि हमारे वेद भगवान में लिखा हुआ है :

"यन्ति प्रमादं अतन्द्राः"

इस मुल्क के अन्दर यहां की दूकानें एक मिनट के लिए बन्द नहीं होनी चाहिएं, यहां के बाजारें एक मिनट के लिए बन्द नहीं होने चाहिए, यहां के कारखाने एक मिनट के लिए बन्द नहीं होने चाहिए। अगर बाप थकता है तो बेटा बैठे, बेटा थकता है तो भतीजा काम करे। लेकिन शाम को 8 बजे दिल्ली कैपिटल में अन्धेरा हो जाय, सारी दूकानें बन्द हो जायें, पुलिस के सिपाही झांक झांक कर देखें, कोई रुपया तो नहीं गिन रहा है, कोई रेजगारी तो नहीं गिन रहा है, कहीं कोई रोशनी तो नहीं है। इससे बड़ा अनर्थ कोई नहीं हो सकता क्योंकि

"पुरुषो वै राष्ट्रम्
राष्ट्रं वै अश्वमेधः"

यह वेद की वाणी है। अगर पुरुष सुन्दर होंगे, चौबीसों घंटे काम में लगे रहेंगे तब देश सुन्दर हो सकता है। देश कभी सुन्दर नहीं हो सकता जब तक इन्सान सुन्दर न हों। इंडिविजुअल करेक्टर बनेगा तो नेशनल करेक्टर बनेगा। व्यक्तिगत चरित्र ऊंचा उठेगा तो राष्ट्र का चरित्र ऊंचा उठेगा। देश का सामाजिक चरित्र सुन्दर बनेगा। अगर हमारा जाती का चरित्र ऊंचा होगा तो कौम का चरित्र ऊंचा होगा। लोग यह समझते हों कि पब्लिक लाइफ कुछ और हो और प्राइवेट लाइफ कुछ और हो, तो वेद भगवान इस बात को मना करते हैं। वेद भगवान की आज्ञा है :

यदन्तरं तद्बाह्यं, यद्बाह्यं तदन्तरम्।

वेद भगवान इस बात को कहते हैं कि सच्चा पुरुष वह है जिसकी प्राइवेट लाइफ और पब्लिक लाइफ एक हो। यह जो लोग कहते हैं कि इनका सामाजिक जीवन ऐसा है, इनकी प्राइवेट लाइफ ऐसी है, वह गलत कहते हैं। जिसकी प्राइवेट लाइफ, व्यक्तिगत जीवन ऊंचा न हो वह कभी भी देश के अन्दर कोई क्रान्ति नहीं कर सकता, देश को ऊंचा नहीं ले जा सकता। मुझे याद है, शैली ने हमारा अनुकरण किया है, यूरप हमारी तरफ आ रहा है, शैली ने लिखा है :

"The most fatal error that ever happened in the world was the

separation of political and ethical science."

दुनिया के अन्दर सब से बड़ा महापाप जो हुआ है वह यह हुआ है कि प्राइवेट लाइफ को और पब्लिक लाइफ को अलग अलग कर दिया है । नीति शास्त्र और धर्म शास्त्र को अलग कर दिया है, आचार शास्त्र को और राजनीति को अलग अलग कर दिया है । महात्मा गांधी एक चिराग लेकर आये थे, युग पुरुष थे, एक प्रकाश-स्तम्भ थे और उन्होंने कहा था कि प्राइवेट लाइफ को और पब्लिक लाइफ को मिलाकर के एक कर दो । जिसने अपना जीवन परमेश्वर के अधीन नहीं किया है, जिसने अपना जीवन भगवान कृष्ण के चरणों मे अर्पित नहीं किया है वह हरगिज हरगिज देश का कल्याण नहीं कर सकता । देश का कल्याण वह करेगा जिसने अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में न्यौछावर कर दिया है । कुरान पाक इसी बात का हुक्म करता है :

"कुल इन्न सलाती व नसूकी
व महयाया व ममाती
लिल्लाहे रब्बिल आलमीन ।।"

जिसका जीवन और मरण, जिसकी इबादत, जिसका रोजा, जिसकी नमाज भगवान के चरणों में अर्पित हो जाती है वही संसार में जिन्दा रह सकता है और देश को आगे ले जा सकता है ।

अधिष्ठाता महोदय, आप पक्षपात से ऊपर हैं । मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि आज से यह हुक्म दीजिये, रूल बनवा दीजिये कि सब से बड़ा भ्रष्टाचार है खाली रहना । जो खाली बैठा हुआ है, जो आइडिल है, आलसी है, जो पुरुषार्थहीन है, जो कर्महीन है, जिस में कर्मण्यता नहीं है वह सब से बड़ा पापी है । भ्रष्टाचारी वह है जो ताश खेलता है । भ्रष्टाचारी वह है जो जुआ खेलता है, जो चौपड़ खेलता है, जो क्लबों में जाकर के शतरंज खेलता है, जो देश के रुपये के साथ देश के समय के साथ, एक एक मिनट के साथ खिलवाड़ करता है, भ्रष्टाचारी वह है। मैंने नहीं देखा इस मुल्क के अन्दर ताश खेलने वाले, समय बर्बाद करने वाले का किसी का चालान हुआ हो । जब तक आलसी और प्रमादी का, जब तक पुरुषार्थहीन का चालान नहीं किया जायगा तब तक देश नहीं बच सकता जो कर्म नहीं करता, जो मेहनत नहीं करता, जो देश के लिए पसीना नहीं बहाता वह सबसे बड़ा अभागा है, वह सबसे बड़ा कर्महीन है । सब से बड़ा पापी है । वेद भगवान कहते हैं :

चरैवेती, चरैवेती ।
सूर्यस्य पश्यश्रेमाण यो न तन्द्रयते चरन् ।
चरैवेती, चरैवेती ।

हमारे ऋषियों का आदर्श है जिसका पुरुषार्थ एक मिनट के लिए भी रुक जाता है, जिसकी तपस्या एक मिनट के लिए भी रुक जाती है उसका कयाण नहीं हो सकता । आज इस देश को बचाने की जिम्मेदारी सब से ज्यादा नन्दा साहब पर है । जितना वह अपना पूजापाठ करते हैं उसका कुछ हिस्सा हम लोगों को भी दिया करें, जितना भजन करते हैं उसका हिस्सा हम लोगों को भी दें, जितना व्रत रखते हैं उसका हिस्सा हमको दें । वह अकेले स्वर्ग में चले जायं और हम स्वर्ग के भागी न बनें, यह ठीक नहीं होगा । सब से ज्यादा इस वक्त जिम्मेदारी नन्दा साहब पर है और देश के अन्दर सदाचार का वायुमंडल न पैदा हुआ, महात्मा गांधी के चरणों का अनुसारण करने के लिए तैयार न हुए, धर्म और इखलाक को ऊंचा न किया, सदाचार का जीवन बिताना नहीं सीखा तो देश का और ज्यादा पतन होगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहूंगा कि आज की बेला में हमारी यह बातें मान लें । एक तो एवर ओपेन शाप्स, एवर ओपेन पार्क, एवर ओपेन मार्केट, एवर ओपेन आफिसेज होने चाहिए । और दूसरे यह कि हथियारों के ऊपर लाइसेंस जो अंग्रेजों की दी हुई गुलामी है, यह जो गुलामी का कलंक अंग्रेजों ने लगाया है वह आज से

[श्री यशपाल सिंह]

खत्म होना चाहिए । हर एक बालिग को, हर एक मनुष्य को हथियार रखने का हक हासिल होना चाहिए । श्रौर यह मुखालिफ लब्ज, अपोजीशन लब्ज इंग्लैंड का दिया हुआ है । हमारे यहां मुखालिफ कोई नहीं होता । हमारे यहां हितैषी होते हैं ।

पुरुषाः बहवो राजन् सततं प्रिय वादिनः
अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः ।।

हम आपके हितैषी हैं । जब आप गलत रास्ते पर चलेंगे तो आपको रास्ता दिखायेंगे । जब आप कोई रांग वे अख्तियार करेंगे तो आप को सही रास्ते पर लायेंगे । भगवान आप का कल्याण करे, आप को सुमति दे और यह 50 करोड़ की जाति उठे, विजेता बने । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अविश्वास के प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं ।

**Shri Harish Chandra Mathur** (Jalore): Mr. Chairman, there is no answer to my esteemed friend, Shri Yashpal Singh, who has the greatest freedom to speak about all corners not only of this mundane world, but also of the heavenly abode where he travelled with Nandaji. I will confine myself like a humble parliamentarian to this no-confidence motion and purport of it.

Even my friend who spoke earlier, Shri Humayun Kabir, to whom I listened with great respect, also felt so embarrassing. While speaking with all vehemence, instead of confining himself to what has happened since we adjourned last and dealing with the matters which prompted the Opposition to bring this motion of no-confidence, he spoke so passionately about devaluatin. I do not know whether he wanted to take us to the last session of Parliament. Devaluation was discussed last time both during the discussion of the no-confidence motion as also on the resolution concerning Government's economic policy. I could have appreciated it if he had said that after devaluation these are the steps which should have been taken and which have not been taken. If he had made some concrete suggestions, I would have been able to appreciate what he said.

I hope he will also not mind if I refer to the mutual respect which we have for each other. My impression when he walked out of the Congress was that his dissatisfaction was more with the State Government than with the Central Government of which he has been an integral part for long years. After making some reference to the State, he turned only to certain basic questions regarding planning, economic policies, student indiscipline and others which have very little to do with the recent happenings. I would say that even as regards student unrest, I would be able to understand and appreciate what he has to say, because he has written books and beautiful articles on it, to which he himself referred, which I have read with great care and admiration.

I will remind my friend that it was as early as 1955 when as a member of the Rajya Sabha I had moved a resolution regarding student indiscipline. At that time there had been a wave of student indiscipline. There was firing in Gwalior and here and there, and we discussed this matter, and the conclusions which have been drawn today after inviting all the Vice-chancellors and IGPs and all that, are the conclusions which had been drawn in 1955. I do not mean to say that we have not traversed further from 1955. The situation has deteriorated, I understand it; some of the deterioration was inherent in the vast expansion which has taken place. That is understood and that is recognised both by those in the academic world and those in administration, but I will touch upon this subject later.

Regarding this motion of no-confidence, I venture to submit that I do not want to dismiss it as a meaning-

less ritual, even though this most powerful weapon, unfortunately, is being used by the opposition to its greatest disadvantage. This no confidence motion has to have some purpose. I can understand that the opposition does not have a chance of replacing the Government, which is the purpose of a no-confidence motion, but what hurts me more is that, being what they are, they themselves are not taking it seriously. I am not talking of the empty benches today. Even yesterday there were hardly four or five members, and there are comments in all the papers today, which clearly indicates how seriously our friends take the no confidence motion themselves.

Apart from that, what is the type of motion which I am supposed to answer? An absolutely amorphous sort of motion without head or tail. When a no-confidence motion is moved in he House of commons, they say that during this session the Government has gone wrong in its Rhodesian policy, they have done this, done that. Similarly, if the opposition had clinched certain issues, we would be able to understand their meaning, but when the motion is amorphous without head or tail, when they talk of things which happened 20 years ago, about the division of States on a linguistic basis, about everything which had already been discussed on the floor of the House threadbare, it becomes extremely difficult for us to give serious thought to the matter, to give serious consideration to the points raised by the opposition, and we find ourselves in difficulty simply because of this state of affairs.

Mr. Masani yesterday, while speakon this motion, very rightly said that the real vote of no confidence will be taken in the general election. I appreciate that and I would also welcome him to live in a great paradise at least till before the elections; after the elections he will be a disillusioned man, there is no harm if he lives in a paradise till then thinking that this will happen and that will happen. We have had the most unfortunate experience of the Swatantra Party seizing a small unit, the Corporation in Jaipur that large city; it is being controlled by the Swatantra Party and it is a stinking monument of mismanagement. This is the capacity which our friends have exhibited already, and I do not know what would be our fate if one or two States had gone to them. I very much wish that one or two States go to a party like the Swatantra Party, because then possibly there will be a disillusionment in the country, and it will realise that there is no choice but the Congress.

When I say this I do not say that the Congress has no weaknesses, I am not so enamoured of the Congress, that the Congress has not to look at itself, and to cure itself of many of the ills which have corroded, which have eroded the most vital parts of this organisation. I do not for a moment say this. Even while speaking to my party, I say: we have got quite a lot to our credit, but let us vigorously, candidly put it through, and let there be no hesitation in admitting before the country our weaknesses, our mistakes, our failures. That is definitely the position. The Congress has certainly been a self-regulating body. Nobody can deny this, that the Congress has been a self-regulating body. What happened during the last session? There was a lot of talk. There has been a great atmosphere created. We discussed iron and steel. We discussed the 55th report of the P.A.C. Mr. Madhu Limaye has emerged out as a new star in the horizon. But let us not forget the basic fact that it was the P.A.C. headed by Mr. Morarka, the Chairman, who stood with dignity and independence and gave the material to this House. It was he who consistently and persistently, even to the embarrassment of the Ministers and the Government gave an exceedingly good account of himself. Was it the Opposition or a Member sitting on this side? Did it not inspire confidence in all? I find that a committee has been appointed

[Shri Harish Chandra Mathur]

to go into the entire series of cases. That will inspire confidence anywhere on God's earth. An ex-Chief-Justice and two other persons are there. I ask the Opposition. Everyone outside and the Opposition here said that no better choice could have been made. Is it not an earnest of the Congress Government's desire to see that right things are done? Again we have placed before this House an interim report of the Administrative Reforms Commission. That report definitely indicates our great anxiety to see that our Ministers are above suspicion, that there is a clean administration, that there is not even any room for suspicion. We do not want charges to be there against Ministers. Ministers have got to be above suspicion. A wrong climate is created. I do not say every one is honest. There may be black-sheep. There is a sort of wrong climate created. It is the anxiety of the Government and of the Congressmen always to bring them above suspicion. In no place where we have studied the functioning of the democracies, have we found an institution like the one which we have suggested to make this Parliament powerful and to place at the disposal of this Parliament an institution which will take the best care and see that we have a clean administration. Not even the Ministers have been spared. This is the earnestness with which we want to proceed. It is not in the interest of one party. Let us understand each other and see where we stand.

It would not matter if the Congress is in power or not. But certainly it matters that this country has to be stable and with a good and strong Government. That is the situation as it exists today. Mr. Masani will realise it sooner than later. He is unwittingly helping the communists who want nothing but chaos and confusion. I am sure the Congress will be returned. Suppose it is not returned, after Congress there is chaos and confusion and after chaos and confusion, possibly the Communists. There is absolutely no hope whatsoever for any other party which I could visualise. If they want to go that way, let them. Has any of the communist friends said a word against the red guards of the Chinese and what is being done there? Now, these are the friends who sit here and talk about democracy but they will not say a word about those activities. They would not say a word when China committed aggression on this country; they will not say a word when those people say that the foreign minister of their own country should be burnt alive. That is the goal and that is the theory which is being practised. There is not one single word said in their papers outside or here. Now, are these the people who are going to condemn this Government and undermine this parliament in its functioning? Are these the people who are to be trusted to safeguard the democratic movement and democracy? This is the state of affairs.

**17 hrs.**

I will speak a little about the economic situation, because that has very much disturbed us. We all feel extremely pained. As a matter of fact, the whole country is worried about it. But let us take a clear, perspective view of the entire situation. I repeat, as I said last time, that our economic troubles have not their origin in 1952; not in the first Plan; not in the second Plan and not in the third Plan. The entire economic trouble starts from 1962, after the Chinese aggression. That is so clear. If you see deficit financing, deficit financing comes from 1962 in a large measure. Instead of spending Rs. 250 crores, we have been compelled to spend about a thousand crores of rupees on our defence. On defence, we earlier depended upon the British and others; we had never maintained an up-to-date army; we have to spend on it now. When Rs. 750 crores are pumped into unproductive work, though it is of the utmost importance to the safety of the nation, it is definitely going to disturb the economy of the country. Unfor-

tunately, as it happens, it is at this very time that we have consecutively three plans. It is all this very time that we had another aggression from Pakistan. But I am not offering any apology for this. I am just trying to analyse the facts. We have to change our strategy in planning and our economic administration in our economic development. I understand it, and we are at it. Let us also see what has happened during this very time. What is the position in the USA? In the USA, you have got an economy where it is of such abundance; but even there, they are today faced with inflation. They are now waging this small war in Vietnam. But what is the position? A tractor which used to sell in the U.S.A. for Rs. 6,000 dollars is now selling at 9,000 dollars. What has happened to the economy of the United Kingdom? Everyone knows that they have taken such stringent measures now, that thousands of people are going out of employment. Is it because of mismanagement there also? What has happened in other places? When we talk about our economy, we must not forget that this Government, even now, has stood firm.

I am now talking only of very recent events. Only about three months ago, Mr. Bell was here and he made certain suggestions and the report is there. Everyone knows what happened. Our Commerce Secretary rebuffed him when he talked about export incentive; he said that these export incentives do not fit in with the economic reforms. Our Commerce Secretary told him that the USA is doing the same thing; that England is also doing the same thing. France is also doing it. He has been a man on the continent and he spoke with force and he rebuffed Mr. Bell.

Then we were told that we are not going to get any food aid, this, that and the other, if we have trade and business with Cuba. Have we given them up? We said, no; we still have our dealings with Cuba in respect of our jute. We have not surrendered it. These are matters which we must not forget when we talk about the economic situation.

I would remind my hon. friends of one thing, when we talk about the food situation. In 1955, when Shri Ajit Prasad Jain was here as the Food Minister, he told this House and the country that if you are going to pump this money into the economy of this country, the shortage of food will be accentuated because it is quite obvious. This money has relationship with the food supplies. You cannot deny that. There are crores and crores of people who are absolutely underfed, almost living on the starvation level; they have started eating a little more and we do not grudge it. This is bound to happen. This food shortage is not to be calculated by Shri Subraniam now that there are so many mouths more to feed and therefore so many more tons are required. Apart from the addition to the population, the people in this country who have been living at a very low level of sustenance will eat much more. Therefore, our demand for food will go up. With our prosperity, with more money in the market, our demand for food will go up more and more. Therefore, we have to provide for it. Let us understand the situation as it is.

What is it that they say? What has happened in China? In spite of its rule of thumb, in spite of unsparing dictatorship, China is importing a large quantity of food. Russia is importing a large quantity of food. My hon. friend, Shri Trivedi, wanted to compare India with Taiwan. Let us compare comparables. Taiwan is a tiny country where all the money that was needed was pumped in by the United States of America. Let us not compare Taiwan and this country.

When I am talking about these droughts, I will easily concede to all Members of the Opposition to do anything they like to embarrass the Government. They can embarrass the Government in Government's adversity. But I will certainly appeal to them not to embarrass the people of

[Shri Harish Chandra Mathur]

this country in their adversity. The people are suffering at the present moment. We do not take credit, the Government does not take credit if there is a bumper crop, if there are good rains. They cannot also be simply blamed and despised because there have been one or two droughts over which Shri Subramaniam or anybody else has no control. Certainly, this throws up all our weaknesses and I will not spare the Government or anybody if they do not take adequate steps to provide against these droughts which are likely to be there.

Therefore, we have to concentrate on these things. All the time we have been saying that our agricultural policy will have to be reconsidered, will have to be strengthened, this will have to be done and that will have to be done. While I am on this subject of food, I would appeal to the Food Minister that he should not, even unwittingly, do anything which will divide the country on the food front. I want that there should be complete free flow of food throughout the country. It may be that because of administrative difficulties for a short while they may make some administrative arrangements. I have seen the report of the Foodgrains Committee. The Foodgrains Committee has got administrative insight, they know the difficulties, but they are merely administrative people, they have not got the political vision which is necessary. Political vision demands that the country should never be divided on the food front, there should be absolute free flow of food. That is the goal we must have. He should within a year, two years or three years, come forward and say that he has the buffer stock and there is free flow of foodgrains. If there is free flow of foodgrains, as my friend, Shri Kabir was just pointing out that simply because there was free flow from district to district, from place to place, now when the difficulties have been more those difficulties have eased, the difficulties will become less and less. Even in Rajasthan, with famine in 5000 villages, simply because of the crop the rate of Bajra has gone down from Rs. 33 to Rs. 25 because of free flow of foodgrains. You must have courage and the vision. You must take all these steps.

Something was said yesterday when the Prime Minister made a statement about the tripartite conerence. Let us not at least cut our noses to spite the Government. That will do us no good. Nobody claimed that this tripartite conference was going to be something which will solve all our problems. It had a limited purpose and it has definitely served that limited purpose. That limited purpose was significant and important for us. That purpose has been served. As we have been saying all the time, and as I said in this House six months ago, you cannot have political independence without economic independence. The tripartite conference emphasised it. When we talk about the tripartite conference let us also remember that it is not only this Government which is concerned. We must have a little sense of respect for the other participants. The head of the Yugoslavian Government deserves congratulations of this House because he has all the time, in adversity, stood with this Government. Whether it is Kashmir or any other problem, he has always supported us. Let us understand it. Then, what about General Nasser? He is fighting Muslim communalism in a most courageous manner. Therefore, let us understand the implications of this.

At the same time, President Johnson is having a meeting in Manila. In Moscow there is a meeting of all the Socialist countries. The whole world is in turmoil. So, let us make whatever little effort we can towards the advancement of peace.

When Shri Masani talked of DIR I felt a little hurt, because on the DIR we have already expressed our sentiments on the floor of the House. Can he quote one instance where DIR has

been used for arresting people except in the three border States? What is the use of attacking DIR which, for all practical purposes, is dead in all States except the three border States? So far as the border States are concerned, everybody has warned the Government about the situation prevailing there and, therefore, DIR has to be in force in those States.

One thing that worries me is the bundhs in various States. I hope the Home Minister will make a study as to who is financing these bundhs. This is a crucial question. Somebody was saying that the bundh and *jaloos* which were organised in the capital cost about Rs. 75 lakhs. Opposition members are always talking about election funds of the ruling party. I do not think we need even half that amount for the election fund. And I think that money is much more tainted because it is coming from somewhere else. I do not think these bundhs are being organised from the money in the pockets of our friends here who have nothing. I think the Government should address itself to this important problem.

I am not discussing the student problem today because I have already given notice of a motion and I will speak on it when I get another opportunity.

I am sorry that the opposition is not here today. I again make this appeal to the opposition. Let them do anything to embarrass the Government but let them not do anything which will undermine the stability of democracy, which will undermine parliamentary institutions. Like Kennedy, let each one of us ask this question: what am I doing for my country. The moment we start asking this question, I am sure all these troubles will be over.

**The Minister of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri C. Subramaniam):** Mr Chairman, it is rather unfortunate that I have to speak at a time when the opposition benches are empty. It is not merely for the purpose of answering the points which they have made that I deplore this absence, but because I feel that in this matter of food the country has to pull together without any difference, particularly in regard to politics; because, on all accounts, we are passing through one of the very great periods of crisis in our career after independence. Last year was one of unprecedented drought. Looking into the statistics of rainfall, we find that this has not happened during the last 60 or 70 years. The production drop has also been rather steep, from 89 million tonnes to 72 million tonnes. When I said that the shortfall was likely to be of the order of 10 million to 12 million tonnes, there were critics who said that I was exaggerating the shortfall.

My hon. friend, Shri Humayun Kabir, who is not here, questioned the statistics, but, after all, the statistics are on the same basis from one year to another and with all these defects and deficiencies, even if they will not give the actual figures of production, they will certainly reflect the trend of production. Therefore, from that point of view we find, from a 89 million tonnes level the drop was to 72 million tonnes level.

There are some critics of our agricultural policy; who, in fact, attack the entire planning in our country and even the very basis of planning. But, apart from that, there has been sharp criticism of the policy that we have been following in the matter of procurement and distribution.

After all, the merit of a policy will have to be judged by the results. While I do not claim that our policy was perfect, it was possible to avoid difficulties. What is important to realise is: What were the alternatives available to us in a situation of this sort? Was there a better alternative? What was the result of this policy? Has it helped us to tide over this very difficult situation or has it landed us in difficulties?

[Shri C. Subramaniam]

While I am not happy that we should have these restrictions on movement from one State to another and within one State from district to district and from tehsil to tehsil, still, this policy has been able to tide over one of the worst years. Therefore, the policy has something to commend for itself.

Apart from that, I would like to place before the House the response of the country as a whole about which I am glad that the Prime Minister spoke in one of her broadcast talks. It was not a spirit of despondency which prevailed over the country; on the other hand, I am glad to say that the call of the country was answered, as on all crucial occasions, by the people of the country, in a magnificent manner. I want to go on record to say that when we organised on emergency food production programme—I am talking particularly about the rabi season—when we wanted the farmers to take to a crop to which they were not accustomed all along, traditionally, where they never used to have a rabi crop or a summer programme, when we asked them in this hour of crisis, in the hour of difficulties, wherever water was available and the production programme could be organised it was done and I am glad to say that about million acres of additional crop—if I remember aright—was raised, in the sense that the crop was not being raised traditionally on the lands on which they were raised.

Not only that, the response to the subsidiary food production programme, like vegetable growing and potato growing which we got from the urban, semi-urban and rural people was something about which we can be proud. But for this subsidiary food programme, particularly in Bengal and U.P., . . .

**Mr. Chairman:** Madhya Pradesh should be more interested in this speech.

**Shri C. Subramaniam:** I am glad to say that sufficient quantities of vegetables and other subsidiary foods are available. As a matter of fact, in U.P. the disposal of the potato became a problem, even though there was scarcity of other things. In Bengal, during one of my visits; the complaint was made, "We are asked to take more and more vegetables instead of cereals". Unfortunately, our food habits are such that we do not realise that vegetables are much better food than mere cereals.

But what I want to emphasize is that whenever facilities were provided to the people for the purpose of taking up this programme and technical assistance was made available, they came forward to grow vegetables and other foodgrains and foodstuffs to which they were not accustomed all along. Therefore, it gave us a new experience. As a matter of fact, it gave us a new confidence. It also gave us a new insight into agriculture to our traditional agriculturists who have been in the fields for centuries together that it is possible to raise a second crop in many of the lands where they were, all along for generations, raising only one crop.

Apart from this production programme, even with regard to the distribution programme, we can take some credit. We had to meet this deficit by imports. I will be failing in my duty if I did not refer to the generous help which we got from the United States of America. Unfortunately, there are some people who think that to say anything anti-American is progressive. I am not here to justify every policy of the American Government or the American Administration. But as a people, the American people are the most friendly people to India and they have always been friendly to us. I want to say that it is wrong to condemn a whole set of people simply because some people have some prejudice, some phobia, about it. It is a completely wrong approach. I want to

say that at the hour of need, we got this massive food aid from the United States of America and I want particularly my friends who are not here to consider what would have happened if these 10 million tonnes of foodgrains were not available from the United States of America. One of the greatest tragedies would have happened in India. But still we think it is fashionable, it is progressive, to abuse even the food aid which we have received after having eaten it. I am not happy about the position that we have to depend upon imports. Nobody will be happy about it. Now, take for example, Bihar. Bihar is undergoing one of the worst droughts. For argument sake, suppose it is an independent country, and it takes up an attitude, "We shall not import foodgrains from outside. We have got so much natural resources, the rivers and the best fertile lands. Why should we, therefore, import from outside to feed the millions in Bihar?", what would have happened? In the same way, there was absolutely no other alternative but to import.

I have no doubt in my mind that even friends on this side who were a little critical about the foodgrains programme will realise that there was no other alternative for us but to import the food at that time.

Then, even importing the foodgrains is not an easy task at the level of 10 million or 12 million tonnes which would be the total import during this year, 1966. Doubts were expressed whether our ports would handle and whether our labour will be competent to handle millions of tonnes of foodgrains, unload them from the ships and put them on the rails or on the lorries. But we have shown that our port authorities, the labourers and all those who are involved in this task are able to handle it. They did a magnificent job in handling 10 million or 12 million tonnes during this year, in receiving the ships, unloading them and sending them to the various parts of the country. It is not only the handling at the ports which is important but, after that, these millions of tonnes of foodgrains have to be moved by the Railways. The Minister of State for Railways is here. I want to say that the Railways did a magnificent job. I congratulate the Railway administration and all those men who are involved in the rail movement and I want to say that at no time they failed me. That is why it was possible to move millions of tonnes of foodgrains to the various parts of the country where they had got to reach. It is not only the carrying of foodgrains by the railways which is important but ultimately it is the distribution programme which made the foodgrains reach the needy millions of people in various parts of the country. We were able to build up a distribution programme which delivered the goods and which made the foodgrains available in all the scarcity parts. Therefore, we are in a position to say with a certain amount of self-respect that in spite of one of the worst droughts, there was no starvation death in our country.

Now and then questions are put about starvation deaths. Even take, for argument's sake, that they are true. How many were pointed out? One or two, here and one or two, there. Even those cases were inquired into and in many cases it was found that they were not really starvation deaths but were otherwise. Consider what happened in the past during the British regime whenever a situation of this sort occurred. How many millions died? I am prepared to concede that because of mal-nutrition, because of non-availability of foodgrains, some people would have suffered. But looking at the magnitude of the problem, I wish to say that we have really tided over one of the worst crises in our country. Because this big catastrophe did not happen, we sometimes under-estimate the magnitude of the task with which we were faced. Last year if we had looked at the foreign newspapers, they were predicting that millions of deaths would have happened in India as starvation deaths. Therefore, from every point of view, while we pass through a very difficult period, at the

[Shri C. Subramaniam]

same time we are proud of the fact that our people responded magnificently to the challenge and we are proud that our administration, our officers, our workers and our labourers responded to the challenge and that is why we were able to tide over the crisis. If anybody should say that I should not take the credit, that the Government should not take the credit, I concede that we are not taking the credit; the credit should go to the people for the way in which they functioned, for the way in which they responded.

We were all hoping that at least the coming year would be more comfortable and it looked like that till August. Even though there was some delay in the outbreak of the monsoon by the end of August, I was hoping from the information available from the various States that we were going to have bumper crop in many of the States, but, unfortunately again, there was a break in the monsoon and that was a long and crucial break. From the first week of September to the end of October, when rains are necessary, when moisture is absolutely necessary for the ripening of the grains, for the formation of grains, it unfortunately failed us. Therefore, it was a bigger tragedy; where sowing has been done, where watering has been done, when the crops have come up and looked like giving us a bumper crop and when perhaps fertilisers were applied for the purpose of getting more production, if the devastation takes place it is a greater loss to the farmers; it is a great tragedy. This is what has happened during this year unfortunately. A question was put as to why we did not take measures even from September first week onwards. As a matter of fact, till the end of August, the position was so satisfactory that we were hoping that there would be a bumper crop. It was only when the monsoon got delayed and it was not in the horizon that we were troubled and we thought that perhaps the monsoon had failed us. Even then we had the hope that at least a few showers would come to save the situation. As a matter of fact, wherever we had a few showers, the situation was saved. In the beginning of September I was in Orissa and they told me that unless there were rains within the next fortnight, what they expected to be a bumper crop would completely fail and again the story would be repeated as far as Orissa was concerned; another period of acute scarcity would develop in Orissa. But fortunately, if not in adequate quantities, there were at least slight showers throughout and it improved the situation. So also in Bengal where the situation was looking hopeless, the situation completely changed because they had, at least for a week, good rains, In the south also, it looked as if the crop would be completely wiped out; even in the resevoirs which used to have traditionally got filled up during the months of June, July and August, we were informed that there was absolutely no water, but fortunately there have been heavy rains and we are afraid that we are having slightly over-rains, today I am warned that there might be a cyclone in the Bay of Bengal which might cross anywhere between Madras and Cuddalore. I do not know what this is going to do. Unfortunately testing times come over and over again. But let us hope that this would not cause any great damage there.

What I want to emphasise is this that unfortunately we do not have control over nature. Not only we, but even the most developed countries do not have control over nature. If only people would go into what happened in Australia during the last year and how many millions of cattle and sheep perished there and the damage that was caused to the crops, they would find that even Australia which was experimenting with artificial rain and all those things in a very intensified manner was also a victim of natural calamity. There-

fore, if today we are faced with a situation of this sort, it is beyond our control; it is a natural calamity. What is important now is this. How are we going to face this natural calamity which has come successively in two years? This is the most important thing. If I should take the blame or the Government should take the blame for the failure of the monsoon, let us take the blame, but it will be irrational to think that either the Government or the Food Minister has got powers over nature, either to have rains or not to have rains. I wish we had such powers! Therefore, what is important now is how the nation is going to face this second year of scarcity conditions, this second year of large-scale failure of monsoon. This is the most important thing.

In that connection, I would like to place before the House and the country that we are now trying to take all measures on the basis of the experience that we gained during the last year to improve the situation everywhere. As I have already stated, some people would put the question: 'What were you doing all along without making sufficient preparations? As a matter of fact, as soon as the *hathia* rains failed, we took steps. We were feeling confident that the *hathia* rains would be available at least in meagre quantities, but when it failed completely, we immediately sent an official team consisting of officers from the Agriculture Ministry, from the Planning Commission and from the Finance Ministry to make an on-the-spot study and to make recommendations for the purpose of taking immediate steps, and we have taken immediate steps there.

I would like to place before the House how we are trying to approach this problem and how we are trying to solve this and how we are trying to meet this challenge of scarcity, again, particularly intense scarcity in Bihar. But before doing so, I would like to emphasise one aspect, the difference between last year and this year with regard to the failure of monsoon. As I have already mentioned on another occasions, last year, that is, 1965-66 followed a bumper year of 1964-65 when the production was 89 million tonnes. Unfortunately, 1966-67 follows one of the worst years, namely 1965-66, and, therefore, there is no cushion, and there is no flow-over from the production of last year. Therefore, that pipe-line is almost completely empty.

Then, another disturbing feature is this. Last year, it was almost widespread. If I may say so, there was no pocket of intense scarcity as it has happened during this year. In Bihar I was looking into the figures and I find that throughout Bihar, it is only half a district here or half a district there which can be considered normal, and it is only a few districts which have got 50 to 75 per cent production, the majority of the districts have below 50 per cent, and when I say 'below 50 per cent', it ranges from 3 to 50 per cent. This is the picture. Similarly if you take eastern U.P. you find that the conditions there are not much different from the Bihar conditions. Central UP is also affected to a great extent. It is only western UP which presents a normal picture. In addition to that, Madhya Pradesh is affected, Rajasthan is affected, and Gujarat is affected. I was hoping that it was only these five areas that would have to be tackled. But, now Maharashtra has intimated that there has been failure also. The West Bengal Chief Minister has just now come into the picture saying that there also scarcity conditions exist in a few districts.

So this is the picture of intense scarcity which was not there last year, so much so that in particular States there were some foodgrains available to flow to various parts; therefore, it was a question of supplementing what was available.

**श्रीमती सहोदरा बाई राय** (दमोह) : श्रौर मध्य प्रदेश में ? मध्य प्रदेश का नाम नहीं लिया। श्रापने ।

**Shri C. Subramaniam:** I did refer to Madhya Pradesh also. As I was saying, it was a question of supplementing what was available there. But this year it looks as if in Bihar the major portion of the grains will have to flow from out side. So also in eastern UP and perhaps in the other areas we may have to give some quantities of foodgrains. But even then, it will have to be considered, where the supply would come from.

Today we find Bihar asking that they should have at least 4 lakh tonnes per month for the next twelve months. In UP also the situation is the same; perhaps when I go to Lucknow tomorrow, a similar demand will be made or it may be slightly less than that.

**Shri Bishwanath Row** (Deoria): The population is more.

**Shri C. Subramaniam:** A voice is raised that the population is more.

In the same way, demands come in terms of lakhs of tonnes. If I calculate all this, it comes to at least 1 million to 1¼ million tonnes per month. Where do I get all this from? This is the real difficulty.

Apart from that, there is another factor disturbing me. Last year the movement had to take place mostly near about the ports. But this year, it has to take place far into the interior, into Bihar, UP, Madhya Pradesh and other areas.

**Shri Harish Chandra Mathur:** Again the Railways.

**Shri C. Subramaniam:** Again the Railways will have to bear the burden. But you cannot stretch their capacity beyond a certain limit. Their capacity is not something which is limitless, which can be streched to any limit. There is a limit to their capacity also.

Taking all this into account, I want to tell Members, particularly the representatives from these States, that what we have got to do is to make an estimate of what would be available. We have to make an estimate of what is the possible movement. Whether we like it or not, we have to take account of the various difficulties and we have to plan it in such a way that we are able to manage with what we have. We cannot produce more than what we have and we cannot also get from other countries in unlimited quantities. There also this sovereign House will have to take a decision with regard to our import policy. Are we going to take up the same attitude, 'No, we shall not import'? I hope this responsible House will not take up that attitude. I want to pose this question because some people seem to think that I am the villain of the piece. One communist paper has started writing that I am cooking up figures for the purpose of justifying imports. What interest do I have in doing so?

**Shri Harish Chandra Mathur:** Another important factor is the coming general elections. Do not forgot that.

**Shri C. Subramaniam:** That is also a very important thing because naturally it will be particularly played up by the Opposition parties as our our failure. That is one aspect.

The second aspect is that we have to increase production within the country as much as possible. Therefore, I attach great importance to that. I am glad in Bihar and UP they are taking up a big production grogramme, to which they were not used all these years.

So this production programme has to go through. I want to say this to Members from Bihar. The Agriculture Secretary has just returned and his estimate is that it is possible to organise an additional production programme, which was not happen-

ing in the past, of between 1.2 million—1.5 million acres. He has identified the water sources for that. The land to be utilised for this purpose will have to be utilised on the basis of these water resources available. We should have new pumping sets. As a matter of fact, when my Planning Colleague and I were in Patna, they made a demand that they should have larger pumping sets, of between 15 and 40 H.P. I said I would make an appeal to the various State Governments for this purpose, and I am glad that there has been good response. Till now about 120 to 125 pumps from three or four States, 70 coming from Madras, have been recived, but now these will have to be diverted to both U.P. and Bihar. I think the Prime Minister will be interested in this She was putting the question: you are organising the supply of pumping sets, what is happening to U.P.? We are sharing them between the two, taking into account the interests of U.P. and Bihar.

**Shri Birendra Bahadur Singh** (Rajnandgaon): What about Madhya Pradesh? We are having a very big drought.

**Shri C. Subramaniam:** Therefore, this production programme will have to be vitalised, because it solves the problem of movement also. Whenever there is production, to that extent you need not move foodgrains from the ports or from outside to that area. Therefore, it would ease the situation of movement also. Therefore, we attach great importance to this.

At the same time, we are also organising a vegetable proframme, and I am glad the response from U. P. this year has been very good. Last year they did a splendid job, and this year they are organising a much bigger programme with regard to vegetable growing. In the same way I hope Bihar also would respond. In all these things the main thing is that we should have the seeds for these areas, we should have fertilisers, we should have pesticides, and we are organising the supply of all these things. And particularly as far as Bihar is concerned, I can tell the hon. Members that we have already despatched all the seeds, and we shall see that they are properly utilised. Therefore, the production programme and next, movement and distribution of foodgrains—these are very important.

In addition to that, in many areas, drinking water is going to be a problem as it happened last year also. That will have to be properly organised. There is going to be the health problem. Therefore, that will have to be organised. Then, fodder for the cattle. All these will have to be organised. And if these have to be organised, unless you have got an efficient and effective administration, I am afraid we would collapse in this process. That is why we are laying some emphasis on administrative effectiveness and administrative efficiency and the streamling and strenghthening of the administrative machinery. I hope in this prestige would not come in the way, saying: "We are State Governments, after all we are not dependent on the Central Government for the purpose of administration, we are our own masters"; I hope such an attitude would not be taken, because that would be calamitous and it would be a tragedy if such a thing should happen, because we know, particularly in Bihar, there are administrative weaknesses. There is no use of shutting our eyes to that. So, it has to be properly steamlined and strenthened. Otherwise it is not a question of 4 lakh tons, or asking for Rs. 100 crores for relief work. What is important is how we are going to utilise this. Therefore, unless we are sure that our administrative apparatus is equal to this task, in spite of the fact that foodgrains are available in spite of the fact that money is available for relief work, perhaps a tragedy could happen there. That is

[Shri C. Subramaniam]

why we are all anxious, not that we want to find fault with any State administration, but in a crisis of this sort, when these challenges are there, I do not think prestige should stand in the way of strengthening and streamling the administration. If necessary, officers from the Central Government will have to move to the State administration and take over new responsibilities there, and see that whatever materials are available, whatever finances are available, are utlised to the maximum extent, to the optimum extent, so that distress is relieved and misery is minimised. This should be our endeavour today. I hope there would be sufficient response from the State Governments also as far as this is concerned. I hope that this strengthening of the administration happens within the shortest possible time. There is no time to make experiments in this, to say: let us see how the existing administrative set-up functions, and that if there is any failure, later on we shall strengthen it. This will be, I am afraid, a wrong attitude to take, a dangerous attitude to take. We cannot afford to take risks in that. Therefore, if there are better officials available, more effective officials available, all of them should be put on this job, because this has got number one priority.

Hon. Members also, as representatives of the people, will have to discharge their responsibilities in an effective way to see that the official organisation functions effectively and also efficiently and with integrity. That should be our job and I hope the hon. Members here would take charge of certain areas within their constituency, if not the whole constituency, and see that on the non-official side they give strength to the administration in the various relief works which would be undertaken; they should see that proper distribution takes place efficiently. An official agency, unless it is backed by non-official effort would perhaps not be able to get the best out this. I am glad in Bihar a non-official committee has been formed under the chairmanship of Shri Jayaprakash Narayan. In the same way perhaps a non-official agency will have to be formed in U.P. also. We shall certainly consider it. We cannot leave everything completely to the official agency to look after. Non-official agencies and voluntary agencies will have to come into picture particularly with regard to the feeding programme of children, nursing mothers and expectant mothers and with regard to running gruel centres for the sick and old and disabled; they will have to come into the picture more and more and see that distribution takes place in a rational and equitable manner and to see that relief works are also properly organised and wages are properly paid and there are no middlemen who would make profit out of the misery of the people. This will have to be ensured. I hope all these efforts would come from the repesentatives of the people. I know the elections are coming and perhaps this would be the best thing even from the point of view elections to do.

As I said already, it is going to be a very difficult year for us but on the basis of the experience gained and on basis of what we could get from abroad this year also, it should be possible for us to tide over and meet this challenge effectively an successfuly. We have organised our import programme from as many sources as possible because after the large supply which the USA made, their reserves have also gone down and therefore they may not be in a position to supply as much wheat as they did last year. So, we have to find out from where foodgrains are available and try to get them on negotiated terms. Perhaps we may have to use some foreign exchange. I know it is a scarce commodity but we still have to use it in such a way that we get the

maximum benefit out of it. Naturally people get dissatisfied that after nineteen years or 20 years of freedom we are still in this position of facing crisis after crisis. I would not judge our agricultural progress on the basis of what had happened during these two years of unprecedented drought. Some people have an impression that our neighbour country Pakistan had done very well in the agricultural field and that their performance is much better than India's. Recently a study had been made by experts and we found there is no such better performance in Pakistan. But that is no consolation for us. We need not be ashamed of our performance on agriculture.

**Shri Harish Chandra Mathur:** It has to be much better.

**Shri C. Subramaniam:** We have done fairly well but what is important is we have got to do it in a much better way because we cannot plead natural calamities and failure of rains and say that there is no other alternative to get foodgrains from outside. If foodgrains are not available, are we going to say that the only alternative is to starve. Therefore we have to have a programme whereby even in the worst years we should be in a position to meet our requirements; we must do it in such a way that we produce a little surplus during the better years and thus build a buffer stock to meet the requirements during the lean years. This is the programme which we are trying to visualise. What is happening today? If even this production is taking place, where has this come from? It is only from places where assured irrigation was available that even this much foodgrains production was possible. So, irrigation facilities will have to be given the topmost priority. That is one thing. Not only top priority to irrigation must be given, but we should be able to get maximum production out of the water available. Today we are not getting even from the water available the maximum which it is possible to get, taking advantage of what has been developed in science and technology. That is why, while water is important, what is more important is to get the maximum amount from existing water-supply, and that is why we have evolved this new programme, the new strategy of high-yielding programme. As a matter of fact, if I confidently say that our production will be much better than last year's it is mainly because we would be having at least five million acres of land under the high-yielding programme, which would be yielding five million tonnes more than the traditional varieties. That is where we confidently predicted that it would be much better than last year, though it may not reach the peak figure of 1964-65. If only we are able to organise this high-yielding programme and use the water and the soil to the maximum advantage, I have no doubt in my mind that even in a period of lean year like this, it would be possible for us to reach a level of production which would meet the minimum requirements; and in an ordinary year we would be able to have even a little bit surplus. This is how we are organizing it. In that, we have to use particularly the new science and technology, and here I want to pay my tribute to our young scientists particularly who have responded to this challenge.

Foreign experts have come and seen what our young scientists are doing and they are all praise, and I want to pay my tribute, and I am sure the country will be greatly indebted to the scientists who are doing a splended job in evolving new varieties and finding out our agronomic problems and finding out also the various pest and plant control measures which are necessary. More than that. We are organizing a study in a new line, soil and water management, that is, the utilisation of soil and water to the best advantage possible. We are moving towards this. Therefore, it is only by utilising this modern knowledge which is available to us that we would be able to get over this diffi-

[Shri C. Subramaniam]

culty of producing enough to meet the needs of the country.

**Shri Harish Chandra Mathur:** Next year.

**Shri C. Subramaniam:** Let us hope so. We would be taking four to five million acres and we had programmed to reach 32 million acres by the end of the Fourth Plan, but by the enthusiasm shown by the farmers, I find we may be able to reach perhaps this 32 million acres within three years provided we have the fertilisers and also the pesticides and various other materials and inputs required for this purpose

Therefore, while the picture is gloomy this year, while we are passing through difficult periods, still, I want to give you this assurance that we are on the right track. Some people may be pessimistic about the new programme, because we have got new problems. I want to tell you that you cannot have any new techniques or methods without some new problems. Fortunately, those problems have an answer or solution. Therefore, simply because we ran into some difficulties here and there, there is a tendency to cry down this new programme. But I want to assure this House and through this House the country that these problems have been identified and fortunately our scientists assure us that all these problems can be effectively solved. This is the picture. This is where I see that I am at a disadvantage when the Opposition is not present here; if we have got to meet this challenge in this year, how are we going to do it? It has got to be properly planned; the movement will have to be properly planned; the imports will have to be planned, and if there is any breakdown anywhere, I am afraid we would not be able to meet the situation properly. Therefore, if there should be a strike or a slow-down in our ports, it is going to affect the lives of millions of our people; their lives will be at stake if such a thing should happen. If there is any delay in the movement or any hold-up in the movement, that would affect the lives of millions of people. And that is why I want to appeal to the people, and to those in the Opposition—even though they are not here I am sure they will be looking into the proceedings here—and to the Congressmen and to the whole community, whatever else you may do in other activities, let us come to a decision in this our of crisis, when we are faced with one of the biggest challenges, that we shall not do anything which will retard the movement of foodgrains either in the discharge at the ports or in the movement through the railways or on the roads. Bandhs and other things are being organised. Sometimes it is claimed that they are being organised for the benefit of the poor, so that the Government will be forced to give them a little more foodgrains. How can more grains be given unless the supply is there? By their very act, by organising bandhs and other things, they are obstructing the movement of foodgrains, they are retarding the movement of foodgrains. Therefore, there is less availability of foodgrains, and by these bandhs, which they say they are organising for the benefit of the poor consumers, they are making it more and more difficult. It was all right, it had been done. But now, as I have alreoady informed the House, we are in a very precarious position. If there should be any disruption in our plans of movement this will be a big disaster. Therefore, anybody who does this, who encourages this or who connives at the stopping of trains or stopping of movements or stopping of unloading of ships, will be the greatest criminal who will be responsible for the lives of the millions of people in India. This the community should understand today, because sometimes it is put forward that it is being done by certain political parties for the benefit of the people, particularly for the benefit of the poor. On the other

hand, these are the people who strike at the belly of the poor people particularly because the rich people somehow or the other manage to get their food from somewhere. Therefore, this should be made clear, and at least such an understanding we should arrive at. I am not saying that they should not do other things, but at least this minimum should be ensured, that nobody would obstruct our plans of movement. Only today I said that I would be moving 100 thousand tons to Bihar. How have I planned it? I have planned it on the basis of movements from Madras to Bihar, from Vishakhapatnam to Bihar, from Kandla to Bihar, from Bombay to Bihar and so on. Now, unfortuntely, because of the incidents in Andhra I am unable to move anything from Madras to Bihar or Vishakhapatnam to Bihar. It is completely stopped. How am I going to fulfil the target of 100 thousand tons? If because of the non-movement of foodgrains there are starvation in Bihar, they will be responsible for it. Somebody said that Kerala is being starved. I do not know who gave him those figures. As a matter of fact—I am sure some Kerala Member at least is here—today they are the best serviced people as far as foodgrain is concerned. They are assured of a certain quantity which nowhere else they are able to get. Even there I am unable to move rice from Andhra because there is this agitation for the so-called steel plant and about which the Government is giving full consideration.

My friend, Shri Humayun Kabir, dealt with devaluation and also the price level. He put forward a strange proposition that when you devalue the money automatically the prices would go up, particularly its internal prices. I will prove that the increase in prices is not due to devaluation. On the other hand, this year the price structure is much better than what it was during the last year when there was no devaluation. Devaluation is not of the internal value of the money, it is with reference to the parity with regard to foreign currency. Threfore, to think that because of this the internal prices should automatically rise is not correct. What happened during last year? With a fall of 17 million tonnes, particularly rice, from 39 million tonnes to 31 million tonnes do you think here would not be any rise in the price structure?

**Shri Harish Chandra Mathur:** Do you deny that that is not having a reflected action—there is direct action, indirect action and reflected action.

**Shri C. Subramaniam:** Kindly look at the figures and then you can say that. After all, in June devaluation took place. June to August-September is the leanest season and the behaviour of the price structure during these months during all these years has been that it rises. I would respectfully request hon. Members, particularly Shri Mathur, to go into the statistics and find out how the prices behave during these four months, what has been the behaviour of price during last year during the lean season, even though we had a bumper harvest the year before, namely, during 1964-65. If we study the behaviour of prices during June and July, we find that there is a general increase in prices during that period, but this year it is less compared to last year.

**18.00 hrs.**

I do agree that devaluation might have created difficulties with regard to articles which have got imported components and, naturally, in such cases there will be an increase in prices. But that is applicable only to industrial goods. So, to make a general statement that devaluation would or should bring about an increase in prices is not correct and is not borne out by facts. I would like hon. Members to go into the statistics and find out whether my statement is not correct: Devaluation will increase the price of only imported items, and as compared to our total production the imports constitute only 10 per cent, perhaps even less. Therefore, if you take that into account, I have no doubt in my mind that the

[Shri C. Subramaniam]

price behaviour, taking also into account the supply and demand position, has not been erratic and has not been accentuated by devaluation. That is my respectful submission.

But if you ask the other question, whether we have really got all the advantages of devaluation, I may not be able to give a satisfactory answer. But that is a different question. It is not correct to say that devaluation has brought about all sorts of ills and evils in the agricultural front. The difficulty in the field of agriculture is due to various other factors. The decrease in agricultural production naturally gets reflected in the supply and demand position.

Therefore, I would appeal to the House that we have today to face one of the greatest challenges, and this challenge has to be faced on the eve of the elections, when political advantage will be taken of our difficulties. It is but natural for the opposition parties to do that. So, hon. Members of this House, particularly the Congressmen have got a great responsibility at this juncture to see that our machinery of production and distribution function in such a way that just as we met the challenge and tided over the situation last year, this year also with will and determination, with the co-operation of the people we shall meet this challenge successfully and we shall get over the crisis. Perhaps, this crisis itself would create a new confidence in the people so that next year we shall be in a better position.

---

**18.03½ hrs.**

## RELEASE OF MEMBER

(*Shri Rameshwaranand*)

**Mr. Chairman:** I have to inform the House that the Speaker has received the following communication, dated the 3rd November, 1966, from the Superintendent, Central Jail, New Delhi:

> "I have the honour to state that Swami Rameshwaranand, Member, Lok Sabha, has been released from this jail on the 3rd November, 1966 at 10.00 hours."

---

**18.04 hrs.**

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, November 4, 1966/ Kartika, 13, 1888 (Saka).*

---

GMGIPND—LS—II—1837 (Ai) LSD— 6-12-66—970.